



The Gazette of India

शाधिकार से प्रकारित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1986/आधण 11, 1908

No. 311

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1986/SRAVANA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्ता सा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—चण्ड ३—उप-चण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिस्त्रानाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गह मंत्रालय

(धारसरिक सुरका विमान) (पुनर्यास प्रभाग) नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

का. मां. 2652 — निष्कांत सम्पत्ति प्रजासन भ्रिष्ठिनियम, 1950 (1950 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) धारा प्रवस्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा गृह मंत्रालय, धान्तरिक सुरक्षा विभाग (धुनर्वास प्रभाग) के धुनर्वास (बंदोबस्त विंग) में बंदोबस्त भ्रिष्ठकारी श्री जे. एस. सहोता को उक्त भ्रिष्ठिनियम के द्वारा ध्रथवा भ्रंतगैत सहायक भ्रष्ठिरक्षक को सौंप गए कार्यों का निष्पादम करने के प्रयोजन से अनके भ्रपने कार्यभार के भ्रतिरिक्त तत्काल प्रभाव से सहायक भ्रष्ठिकक नियुक्त करती है।

[संज्या -1(9)/ब. सैस/86-एस. एस.-II (बा)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Internal Security)
(Rehabilitation Division)
New Delhi, the 17th July, 1986

S.O. 2652.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) the Central Government hereby appoints Shri J. S. Sahota, Settlement Officer in the Rehabilitation Division (Settlement Wing) under the Ministry of Home Affairs, Department of Internal Security, as Assistant Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties, for the purpose of performing the functions assigned to such Assistant Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(9)|86-Spl. Cell|SS. II(B)]

का. ग्रा. 2653 .—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) प्रिष्ठिमयम, 1954 (1954 का 44) की बारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह मंत्रालय, ग्रान्तरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्वास प्रभाग के ग्रधीन पुनर्वास प्रभाग (वैदोबस्त विग) में वेदोबस्त ग्रधिकारी की थे. एस. सहोता को उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन श्रथवा उसके द्वारा प्रवेध श्रधिकारी को सौंप गए कार्यों का निष्यादन करने के लिए तरकाल प्रभाव से प्रवेध श्रधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या -1(9)86---विशेष सैल/एस. एस.-II (क)] मृ. धसलम, उप सिधव

S.O. 2653.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri J. S. Sahota, Settle-

ment Officer in Rehabilitation Division (Settlement Wing) under the Ministry of Home Affairs, Department of Internal Security, as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act, with Immediate effect.

[No. 1(9)|86-Spl. Cell|SS. II(A)] M. ASLAM, Dy. Secy.

विस मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

चादेश

नई दिल्ली, 15 जुलन्हें, 1986

का. धा. 2654 .--विदेशी मुद्रा विनियमन ध्रिष्ठिनियम, 1973 . (1973 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय (ध्रार्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 1 अनवरी 1974 के सा. का. नि. संख्या 63 तथा मंत्रिमंडल सिषवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 22 फरवरी, 1975 के का. धा. संख्या 741 में निहित भारत सरकार के वर्तमान द्वादेशों के प्रधिकमण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा :--

- (i) सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे उक्क ओहदे के प्रत्येक सीमां-शुल्क प्रधिकारी;
- (ii) केन्द्रीय उत्पादन णूल्क के सहायक समाह्ता तथा उससे उच्छ भोहरे के प्रत्येक केन्द्रीय उत्पादन णूल्क के श्रीवकारी की उपर्युक्त श्रीवियम की धारा 37 के श्रीवित प्रत्येक श्रीवकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य-निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. मं. 178/5/84-त. स. (प्र.)] ए. के. प्रग्निहोत्री, धवर समिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th July, 1986

- S.O. 2654.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the existing Orders of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. G.S.R. 63, dated the 1st January, 1974 and in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 741, dated the 22nd February, 1975, the Central Government hereby authorises:—
 - every officer of Customs of the rank of an Assistant Collector of Customs and above;
- (ii) every Central Excise Officer of the rank of an Assistant Collector of Central Excise and above. to exercise the powers and discharge the duties of an officer of Enforcement under section 37 of the said Act.

[F. No. 178|5|84-TC(E)] A. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

(भाषिक कार्यं विभाग)

(बैकिंग प्रभाग)

मर्च विरुमी, 15 जुलाई, 1986

का० थां० 2655 .— भारतीय स्टेट बैंक ग्रीविनयम, 1955 (1955 को 23) की बारा 19 की उपवारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 20 की उपवारा (1) के ग्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, प्रतब्दारा श्री सी. एस. कल्याणसुन्दरम्, उप प्रवन्ध निदेशक, भारतीय

स्टेट बैंक को उसके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से लेकर औ 4 जनवरी, 1988 को समाप्त होने वाली ग्रवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबक्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

> [संक्या एक. 8/5/86-भी, ओ. -1] एम. एस. सीतारामन, ग्रवर संविव

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2655.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 19 and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri C. S. Kalyanasundaram, Deputy Managing Director, State Bank of India as the Managing Director of the State Bank of India for the period commencing with the date of his taking charge and ending with January 4, 1988.

[No. F. 8|5|86-BO. I] M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

والمواور الأوالية المنت اليسارون الاسترامي الانتهام المنطاعين

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 भगस्त, 1986

श्रावेश

का. आ. 2656: — निर्यात (क्वालिटी निर्यक्षण और निरीक्षण) प्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संस्कार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना धावश्यक और समीचीन है कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाव का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया वाए।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजम के लिए नीचे विनिदिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंद्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 2 के उपनियम (2) की घ्रपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को घेज दिया है;

मतः, मब, केन्द्रीय सरकार, उक्त उप नियम के मनुसरण में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को रंगलेग तथा संबंध उत्पादों से संबंधित मिश्रसूचना संख्या का.मा. 355 तारीख 16 फरवरी, 1980 को उन बातों के सिवाय मिश्रिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे प्रधिकमण से पहले किया गया है या करने का लीप किया गया है, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाणित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की मंभावना है।

2. यह सूर्चना वी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई व्यक्ति कोई काक्षेप या सुझाब देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11वीं मंजिल, प्रगति टाबर, 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 की भेज सकता है।

प्रस्ताव

- (1) म्धिसूचित करना कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यान से पूर्व क्वालिटी निर्यक्रण और निरीक्षण के श्रधीन होंगे;
- (2) (क) सुसंगत भारतीय मानक तथा ग्रन्य राष्ट्रीय मानको का निर्यात निरीक्षण पश्चित् द्वारा मान्यताप्राप्त ग्रन्थ निकायों के मानकों को ;
 - (ब) उत्पादों के परिमिष्ट-1 में दी गई न्यूनतम अनेकाओं की पूर्ति करने के अधीन रहते हुए संविदासक विशेन श्रीं को रंगलेप तथा संबंध उत्पादों के लिए मानक दिनि देंगों के रूप में मान्यता देना;

- (3) इस आदेश के परिशिष्ट-2 में दिए गए रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद का निर्धात (क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1985 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार की निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में जिनिधिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों को लाग् होगा।
- (4) ग्रम्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मनुकम में ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रतिषिद्ध करना अब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी निर्यक्षण और निरीक्षण) ध्रिष्टिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के म्रधीन स्थापित एक भ्रभिकरण द्वारा निर्यात के लिए जारी किया गया इस ग्राशय का प्रमाण-पन्न न हो कि ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का मोनक विनिर्वेशों और म्रधिनियम की भ्रपेक्षाओं के भ्रनुसार सम्बक्ष रूप से निरीक्षण कर लिया गया है।
- 3. इस श्रावेश की कोई भी बात भावी केताओं को भू-मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग द्वारा रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के उने नमूनी को लागू नहीं होगी जिनका पोतपर्यन्त निःशुस्क मूल्य 500 रुपए से घधिक नहीं है।
- इस भ्रक्षिमूचना में रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों से इस भ्रादेश की सारणी-I और II में दी गई मदें प्रमिन्नेत हैं।

मारणी-I

- 1. संश्लिष्ट इनेमल
- 2. ऊष्मारोधी वार्निशें बायु शुष्कम बिदुमन प्र_{का}र के।
- संण्लिक्ट वार्षिगें, जि़िनिसिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए)
- इमस्याम रंगलेप (प्लास्टिक/ऐक्क्लिक इमल्सन)

∙ सारणी-∐

- मभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके इन्त्यांत संश्लिष्ट इनेमल को छोड़कर प्राइम, फिलर, अंडर कोटिंग तथा फिनिसिंग भी है।
- 2. लंशिलब्ट वर्गिश फिनिसिंग (सामाध्य प्रयोजन के लिए तथा ऊष्मारोधी वर्गिशों) हथा गुष्कम, विदुमन प्रकार के (प्रतिरिक्त सभी प्रकार की वर्गिशों) प्राकृतिक लाख या संश्लिष्ट या दोनों से बनाई गई।
- प्लास्टिक तथा ऐकलिक के प्रतिरिक्त सभी प्रकार के इमल्सन रंगलेप।
- 4. फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्षा सादी या रंग मिली हुई।
 - 5. पेस्ट रंगलेष श**या** पेस्ट हिन्देशार
 - सूखें डिस्टेम्पर, चूने के रंग तथा सिमेंट रंग
 - 7. सिमेंट रंगलेप
 - 8. रंगलेप की मिलाने के लिए विलेयक
 - 9. रंगलेप के लिए संश्लिष्ट लाख
 - रंगलेप के लिए संसाधित तेल और रंगलेप के लिए गुष्कम था प्रद्यापुष्कम तेल
 - 11. बिटुमिनिमस कोटिंग
 - 12. एल्युमिनियम पेष्ट

परि**प्रि**ष्ट-1

न्यूनतम भपेकाएं

- सामाध्य प्रवेशाएं
- 1.1 प्रत्येक उपर के डिक्बों पर सिम्मिलिखत से चिन्हिन किया आएगा।
 - (क) सामग्री का नाम और श्रेणी
 - (ख) विनिर्माता का नाम और/या भ्यापार चिन्ह

- (ग) फैक्ट्री कोड, यदि विनिर्माता की एक से ग्रधिक विनिर्माण एकक है।
- (च) सामग्रीकी माला
- (इ.) विनिर्माताकाबैच
- (च) विनिर्माण का वर्ष सथा मास ।
- 1.2 पैक मे प्रारम्भिक डिब्बे इस तरह से पैक किए चाएंगे जिससे उनमें आपस में टकराव न हों।
- 1.3 डिक्बों की रिसाव परला और मीवन क्षमता की धनेआएं ऐसी होंगी जो विनिमर्ति द्वारा अधिकथित की जाएं।
- 1. 4 बुल्ड डिब्बों (बैरल) या लकड़ी की पेटियों/गत्तेदार डिड्बों की जिनमें प्राइमरी डिड्बों पैक किए आएंगे फिनिश अच्छी होगी और जोखिय सहन करने में पर्याप्त मजबूत होगे।
- 1.5 फैकने की पद्धित, उत्पाद की उत्तेजक प्रकृति, विक्रवे की प्रद्धित्व जौर अन्य ऐसे संगत पहलुओं के बारे में उठाई धराई निर्देश विशेषतः अन्तरराष्ट्रीय रूप से माध्य संकितिक शस्त्रों में पैक के बाहरी और अकित किए जाएंगे।
- 1.6 प्रत्येक परेषण पर प्रयोग के लिए निर्देश या तो प्रत्यक्ष रूप में डिट्डे पर अंकित होंगे या साहित्यिक रूप में होंगे।
 - 2. परीक्षण:
- 2.1 निर्यात में लिए लीट पर निम्नानुसार परीक्षण लागू होगा। मारणी-1 की मदों के लिए उपाबंध (1) से (4) के ब्रनुसार मारणी-2 की मदों के लिए संविदात्मक ग्रुपेक्षाओं के श्रनुसार।
 - टिप्पणी सारणी-2 की मदों के मामलों में, संगत राष्ट्रीय मानकों मे विशिष्टताओं के लिए विनिर्देश फैला की धरेकाओं के धनुसार संविदा में वर्णित किए आएंगे।
 - 3. नमूना लेना
- 3.1 नमूने के रूप में चुने गए डिज्बों की संख्या प्रति लौट निम्मा-नुमार होगी।

ममूना लेने का मापदण्ड

लौट ग्राका (डिक्बों की		नमूना सेमे के लिए चु ने गए डिब्बोंकी संख्या
	50	3
51 से	100	4
101 से	200	5
201 से	300	6
301 से	400	7
401 से	800	8
801 से	द्मधिक	10

टिप्पणी: ----नमूना लेने के प्रयोजन के लिए सीट डिक्बों के नापीं पर घ्यान दिए बिना विशेष फैक्ट्री कोड लिए हुए किसी विशेष वर्ग के उत्पाद के विनिर्माना का प्रत्येक वैच लगा होगा।

- 3.2 परीक्षण नमूनों की तैयारी: लौट से निकाल गए प्रत्येक नमूना का भार के लिए जहां कहीं लागू हो प्रति दस लीटर प्रलग प्रलग परीक्षण किया जाएगा धौर यदि विनिर्विष्ट मानकों के प्रनुसार पाया जाता है तो उसी लार में से लिए गए फ्रलग नमूने मिला लिए जाएंगे धौर एक मिश्रिस नमूना बन जाएगा धौर सामग्री विनिर्वेश की सभी विशेषताधों के लिए मिश्रित नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।
- 3.3 परीक्षण की प्रणाली : परीक्षण की प्रणाली निर्यात संविधा में विनिर्विष्ट की प्रनुसार होगी। ऐसे विनिर्विष्ट मनुबंध की प्रनुपस्थित में परीक्षण की प्रणाक्षी सुसंगत भारतीय मानक विनिर्वेशों के धनुकन होगी।

संक्लिब्ट इनेमल के लिए परीक्षण

- 1. प्रारम्भिक परीक्षण: ताजे खुले डिच्हों में सामग्री सिवरिंग, प्रस्थि-रता मादुड नहीं होगी विलोडित भवस्था पर बग करने के लिए यह एक एकसार साफ भौर उजित उत्पाद 🕏 पश्चातु बनाएंगा। तथापि सामग्री को पलला करने के पश्चात् गाढ़ा छिड्काव होगा।
- 2. फिनिश: पैनल पर जब लागू हो जैसा कि निर्धारित हो, फिनिश चिकनी ग्रीर चमकदार होगी, कंकरीलेपन, रंग भे ग्रसगाव या श्रम्थ कोई सतही संबोध से मुक्त होगी।
- 3. पिसाई की सफाई : हैममेन गेअ से जब परीक्षित किया जाएगा यह 6 मौर कीच, की रीडिंग देगा।
 - सामग्री नीचे दी गई प्रपेक्षाओं का भी मनुपालन करेगी।

कम सं	विशेषताएं	भवेकाएं
(1) (i) सुखाने का समय	
	(क) सतह गुष्क	ग्रधिकतम 8 मन्टे

- (स्रं) कठोर मुख्क प्रश्चिकोतम 18 घन्टे
- (ग) टेंक मुक्त क्रांडे ग्राधिकतम 24 घन्टे
- (ii) रण श्रेता द्वारा विनिर्विष्ट भी मनुसार (निकटतम मैच होना चाहिए)
- 🛨 15 सेकेंड विनिविष्ट (iii) 30° सेंग्र पर बी-4 फोर्ड कप में विस्कासिता
- (iv) प्रत्येक 10 लिटरपरभार 🛨 3 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
- 30° सें ग्रे. से कम नहीं (v) क्लेश प्लाइंट
- (vi) खराच कठोरता परीक्षण परीक्षण पास करते के लिए
- (vii) लजीलापन तथा भासंजन परीक्षण पास करने 🔻 लिए परीक्षण
- (viii) निर्लेपन परीक्रण

-यथोक्त—

(5) पक्के रंग भी लिए परीक्षण: नमूने परीक्षण पास करेंगे।

नोट: यह परीक्षण प्रत्येक परीक्षण पर करने की आवश्यकता नहीं। होगी। प्रस्येक विनिर्माता सभी निरूपणों ^के लिए प्रस्येक बास में कम से कम एक बार यह परीक्षण करेगा।

उपा**र्वध -- II**

अञ्मारोधी वार्तिश कें लिए परीक्षण हवाशुष्कम विदुमन प्रकार

- 1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे खुले डिक्बों में सामग्री गहरे भूरे से काले रंग, तरक्ष धवस्था में, तुबचा पर चिपकने से मुक्त, घवसाय तथा बाह्य पदार्थी से मुक्त होगी विलोडित प्रवस्था पर यह साफ, एक सार भीर एक रूप मिश्रण होगी।
- 2. कापर के साथ बानिश की प्रतिक्रिया जब परीक्षण किया जाए तब कापर का रंग नहीं बदलेगा।
- 3. (क) 5000 वोल्ट/मिलीमीटर (ग्यूनतम) कक्ष तापमान पर हवा में विद्युत अमता बोल्ट/मि मी (अधिकतम) में होगी।
- (ख) पानी में निम्नजन के पश्चात् समता प्रतिकत सामग्री 3000 कोल्ट/मि मी / स्थूनतम पर परीकाण पास करेगी।

सामग्री मीचे वी गई घपेक्षाभी का भी पालन करेगी:

कम सं०	विगोषताएं	ध्येकाएं
(i)	प्रत्येक 10 लीटर पर भार	🛨 5 प्रतिशत विनिर्विष्ट
(ii)	30. सें ग्रें परशी—4 फोर्ब रूप में विस्कासिता	\pm 15 নীনীত বিদিবিত
(iii)	शुष्कन समय	
	(क) कडा सूखा	बधिकतम छह चन्टे
	(ख) टेक मृक्त सूका	मधिकतम 24 घ न्टे
[(iv)	फलेग प्वाइंट	30 डिग्री सें ग्रे से कम नहीं
(v)	रंग	प्रत्येक नमूने के ग्रनुसार (निकटतम मैच होगा)
, (v i)	मवरोष्ठया भवमिश्रण की . क्षमता	100 प्रतिसत
(vii)	भवष्पशील पदार्थ प्रतिशत	🛨 ३ प्रतिशत विनिर्विष्ट
(viii) खानिज तेल का प्रतिरोध	परीक्षण पास करने के लिए
(ix)	गरमल एंडयूरेंस परीक्षण	य यो सः
(x)	सचीलापन तथा भासंजन परीक्षण	—ग थोक्त

जपा**यंध**−Ш

संश्मिष्ट वानिश, फिनिशिय के लिए परीक्षण (सामास्य प्रयोजन के सिए)

- 1. प्रारम्भिक परीक्षण: ताजे सुखे विक्यों में सामग्री लियरिंग या मस्थिरता के कोई भी विन्ह नहीं विखाएंगी। सामग्री साफ पारवर्षी तथा मकसाद तथा पपड़ी से मुक्त होगी। इसके संघटकों के कियाशील होने पर **वराबर भीर सामरू**प करने के लिए तेजी से बिखेरा जाएगा।
- 2. फिनिशा: निर्धारित पैनल पर जब सामग्री लागु होगी, फिनिश अराबर घौर चमकक्षार होगी।
 - 3. सामग्री नीचे दी गई मपेक्षामी का भी मनुपालन करेगी:

घपेकाएं

ययोक्त

विशेषताएं

परीक्षण

(xiii) निर्लेपन परीक्षण

कम

सं०	774114
(i) सुखाने का समय	
(क) सुखी सतह	ङः घन्टे (श्रधिकतम)
(खा) सस्त मूख	18 वन्टे (मधिकतम)
(ग) टैक ें मुक्त	24 घण्टे (मधिकतम)
ह्य(ii) रंग	प्रति समूने के धनुसार (एक निकटतम सैच होगा)
(iii) फर्लमा व्याइंट	30. सेंटीग्रेड से कम नहीं
(iv) बाष्पशील पदार्थं प्रतिशत	60 प्रतिशत प्रधिकतम
(V) 30° सेंट्रीग्रेड पर विस्कासित	ता 13 स्टोक
(vi) मूल्य ग्रम्लमान	25.0 (मधिकतम)
(viii) प्रति 10 लिटर चार	± अत्रतिशत विनिर्दिष्ट
(viii) मलकली के लिए प्रतिरोध	परीक्षण पास करना
(ix) ऐसिड से प्रतिरोध	यधोक्त
(🛪) पानी से प्रतिरोध	यथोभत
(xi) कठोर चरोंच परीक्षण	ययोक्त
(xii) सचीलापन ग्रीर ग्रासंजन	ययोक्त

उपावध---V

इमरुशन रंगलेप के लिए परीक्षण (प्लास्टिक/एकलिक इमल्मन)

- 1. प्रारम्भिक परीक्षण: साजे सूखे खिळ्यों में सामग्री डलों पपडी से मुक्त होगी, भिंधक ललाइट से पिण्ड बनाने काणकायन, निर्वारण या रंग प्रथमकरण से बाहर नहीं होगी और चिक्तनी और एक सार भवस्था के निए निर्लेगन के साथ प्रासानी से बिखरी होगी। यह बदबूदार गंध से मुक्त होगी पतला करने के पश्चात गाढ़पन कण या छिडकाब करने या रोलर प्रयोग करने के निए गाढ़पन बराबर और एकसार होगा।
- 2. गुष्कम समय: रंग लेप के गुष्क सत्तह का समय 1 घन्टा (मधिकतम होगा) तथा पुनः कोटिंग का समय 4 मन्टे (प्रधिकतम होगा)
- फिनिया: निर्धारित पैनल पर जब सामग्री लागू होगी, फिल्म की फिनिक, बराबर और अण्डे की सफोदी जैसी जनकदार होगी।
- 4. रंगः विदेशी त्रेसा द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के लिए निकटसम मैंच होगा।
- 5. भार अपर्धयण से प्रतिरोध: 4000 भोसिलेशन के लिए रंगलेप फिल्म का परीक्षण पास करेगा।
- 6. प्रति 10 लिटर का भारः विनिदिष्टों भारः के प्रिययेक हैं 16 ्रै लिटर पर सहायता ± 5 प्रतिकृत होगा।
 - 7. हरूका सा पनका: नमूने परीक्षण पाम करेंगे।
 - प्रश्कली से प्रतिरोध: नमूँने परीक्षण पासर्द्धिकरेंगे।

परिशिष्ट-II

[प्रस्ताव का पैरा (HI) देखें]

[(निर्मात) भवाशिटी नियंत्रण और निरीक्षण (म्रम्निनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (ध) के स्रमीन बनाएं गए प्रस्ताबित नियमों का प्रारूप)]

- 1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का सक्षिप्त नाम रंगलेप तथा संबंध उत्पाद (क्वासिटी नियंत्रण भौर निरीक्षण) नियम, 1986 है।
- परिमाथाएं : इन नियमों में जब तक कि संवर्ध से अन्यथा इप्लेक्षित न हो ।
 - (क) "श्रिश्वनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) ग्रिश्वनियम, 1963 (केन्द्रीय श्रीवनियम 1963 का 22) ग्रिपेनेत है;
 - (ख) "ग्रामिकरण" से श्राधिनियम की भ्रारा 7 के ग्राधीन सम्बर्ड, कलकत्ता, कोचिन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित ग्रामिकरणों में से कोई एक ग्रामिकरण ग्रामिग्रेत है।
 - (ग) रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद से प्रमित्राय है।

सारणी-I

- (i) संश्लिष्ट इनैमल
- (ii) कप्सा रोधी वानियों शुक्त हवा, (विदुसन प्रकार)
- (iii) संक्रिलष्ट वानियों, फिनिशिंग (सामस्य प्रयोजन)
- (iv) इमलकान रंगलेप (प्लास्टिक/एकलिक इमल्सन)

सारणी-II

- (i) संश्लिष्ट इनेमल के श्रांतिरिक्त सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके श्रन्तर्गत प्राइमर, अंडरकोटिंग फिनिशिंग भी है।
- (ii) संक्लिष्ट यानियों फिनिर्शिंग (सामध्य प्रयोजन) और ऊष्मा-रोग्नी वानियों (हवा शुष्क, बिटुमन प्रकार) के ग्रेतिरिक्त सभी प्रकार की वानियों (कृतिम शक्ष या संग्लिष्ट राल या दोनों से बनाई गई)
- (iii) प्लास्टिक तथा एकॉलिक के छतिरिक्स सभी प्रकार के इस्लसन रंतलेय।

- (iv) फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाईट्रोसेल्यूलोज लेकर गाड़ी या रंग मिली हुई प्रलाक्षा ।
- (v) पेस्ट रंगक्रेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर,
- (Vi) सूखे जिस्टेन्पर रंग तथा सिमेंट रंग,
- (vii) सिमेंट रंगलेप,
- (viii) रंगलेप को मिलाने के लिए निशेयक तथा पतली करने वाक्षा पदार्थ।
- (ix) रंगलेप के लिए संक्लिप्ट राज।
- (x) रंगलेप के लिए संगोधित तेल या रंगलेप के लिए गुष्कम या धर्म गुष्कम तेल।
- (xi) बिद्यनी कोटिंग ।
- (xii) एल्यूमीनियम रंगलेप।
- (ष) "परिषद्" से मिश्रिमियम की धारा 3 के श्रश्रीम स्थापित निर्मात निरीक्षण परिषद् ग्राभिप्रेत हैं;
- (क) "प्रमुखी" से प्रन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. निरीक्षण का ग्राधार : निर्यात के लिए ग्रामियत रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद मिर्यात (क्वालिटी निर्यप्तण और निरीक्षण) ग्राधिनियम, 1963 केन्द्रीय ग्राधिनियम (1963 का 22) की वारा 6 के ग्राधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के ग्रमुक्त है।
 - (क) यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद धनुसूची-1 में विनिष्टिट उत्पादन के दौरान ग्रामिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विमिमित किया गया है।
 - (का) अनुसूची-III में विनिद्धिः अग के अनुसार किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर।
- 4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) रंगलेप तथा संबंध उत्पादों के परेवण का निर्यात करने का इब्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या प्रादेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यीरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में मूचना देगा जिससे अधिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।
- (2) इस प्रयोजन के लिए ध्रिकरण द्वारा गठित विशेषकों के पैनल द्वारा उत्पादन के वौरान पर्याप्त नवालिटी नियंत्रणों की पर्याप्त अवस्था रखने वाले धनुमोदित विनिर्माण एकक के रंगलेप सथा संबंधित उत्पादों का निर्मात करने के लिए निर्मातकर्ता उप नियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्मात के लिए ध्राशियत रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों का परेषण ध्रनुसूची-1 में ग्रिधि-कथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करने हुए विनिर्मित किया गया है तथा परेषण प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के धनुक्षण है।
- (3) निर्यातशर्ता भ्रमिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहुंचान धिन्ह भी देगा।
- (4) उपरोक्त उप नियम (1) के मधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर के परेषण के भेज जाने वाले कम से कम सात विन पूर्व वी जाएगी जबकि उप नियम (2) के मधीन घोषणा सिंहत सूचना विनिर्माण के परिसर से परेषण के भेजे जाने में कम से कम तीन विन पूर्व वी आएगी।
- (5) उप नियम (1) के घ्रधीन सूचना और उप नियम (2) के ब्रधीन घोषणा यदि कोई हो के प्राप्त होने पर ग्रामिकरण,
 - (क) बिनिर्माण की प्रित्रिया के दौरान मपना यह समाधान कर लैने पर कि विनिर्माता ने इस प्रयोजन के लिए माध्यत। प्राप्त मानक विनिर्देशों के भ्रनुरूप उत्पाद को बनाने के लिए भ्रनु-मूची-1 में ग्रीकियत पर्याप्त क्यालिटी नियंत्रणों का प्रयोग

किया है तथा इस संबंध में परिषद/प्रामिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश यदि कोई हो का पालन किया है, रंगलेप तथा संबंध उत्पादों के परेषण को निर्यात करने के लिए तीन दिनं के भीतर निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी कर देगा । जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां परेषण का ऐसा सत्यापन सथा निरीक्षण जो आवश्यक हो अभिकरण द्वारा किया जाएगा जिससे यह गुनिश्चित हो जाए कि उपरोक्त शलीं का पालम किया गया है। अभिकरण परेक्षणों में से कुछ परेषणो की स्थल पर जांच करेगा और यूनिटों द्वारा अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण और पर्याप्तता को मत्यापित करने के लिए नियमित अन्तरालों पर युनिट में भी जाएगा । यदि जिनिर्माण युनिटों में यह पाया जाता है कि उनमें विनिर्माण में किसी भी प्रक्रम पर ग्रपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण है उपायों और प्रभिकरण के प्रशिकारियों की सिफारिणों का पालन नहीं किया गया है तो यह बोधित किया जाएगा कि मूनिट के पाम उत्पादन के वौरान पर्याप्त स्वालिटी नियंबण नहीं है । ऐसे मामलों में मूनिट अपनी कमी को दूर करेगा और उत्पादन के दौरान क्यालिटी नियंत्रण का प्रतुमीधन प्राप्त करने के लिए फिर से मया प्रावेदन देगा।

(का) ऐसी यहाओं में जिसमें निर्यानकर्ता ने उपनियम 3 (खा) के अधीन निर्यात करने की मांग की है अपना यह समाधान करने पर कि रंगलेप तथा संबंध उत्पादों का परेषण किए गए निरीक्षण/परीक्षण के आधार पर मानक विनिर्देशों के अनुकृष है, निरीक्षण के सात दिन के भीतर रंगलेप तथा संबंध उत्पादों के परेषण का निर्यात करने के लिए निरीक्षण प्रमाण-पन्न जारी करेगा।

परन्तु जहां ध्रमिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यात के लिए ऐसा प्रमाण-एक जारी करने से हंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सृष्ठित निर्यातकर्ता को देगा।

- (6) ऐसी दशा में जहां विभिन्नांता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्मात करने के लिए निर्मातकर्ता नहीं है या परेषण का उप नियम (5) (ख) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, वहा अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पण्चात् पैकैजों को परेषण इस ढंग से सीलकन्द करेगा कि सीलकंद पैकेजों में रहोबदल न की जा सकें। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्मातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मामलों में, निर्मातकर्ता इन नियमों के नियम २ के अधीन कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा।
 - निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण :--
 - (क) मा तो ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर;

य

- (क्र) ऐसे परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने मान प्रस्तुत किया है परस्तु तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त मुविधाएं विद्यमान हों।
- 6. निरीक्षण फीस: इन नियमों के श्रधीन निरीक्षण फीस के रूप में निर्यासकर्ता धीमकरण को प्रत्येक परेषण के पीत पर्यन्त निःमुस्क प्रत्येक इक सी रूपए पर एक कपया की वर से फीस वेगा।
- 7. घपील :---(1) नियम (4) के उप नियम (5) के प्रधीम प्रभाण पख देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषक रैनल को छपील कर सर्णगा जिसमें कम से कम तीन तथा घडिक से घडिक सात व्यक्ति होंगे।

- (2) विशेषकों भे पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम वो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।
 - (3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।
 - (4) भ्रपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निषटा वी जाएगी। अनुस्ची-1

[नियम 3 (क) देखें]

रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादो का विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने अनुसूची-LI में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निस्त- लिखित नियंत्रणों का प्रयोग किया है।

कच्ची सामग्री नियंत्रण :

- (क) प्रयोग की जाने वाली करूवी सामग्री की विशिष्टताओं को समाविष्ट करने हुए विनिर्माता द्वारा ऋष विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) कच्ची सामग्री के स्वीकृत परेषणों के माय या तो प्रवायकर्ता का परीक्षण प्रमाण-पत्न होगा या कृष विनिर्देशों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए निरीक्षण प्रमाण-पत्न होगा। जिसमें विशिष्ट, प्रवायकर्ता के लिए केता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक की प्रति जांच की जाएगी या क्य की गई सामग्री का केना द्वारा अपनी प्रयागशाया में या प्रयोग-माला/परख सदन के बाहर अधिकयिन क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता मुनिष्टिन करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण ग्रीर परीक्षण किया जाएगा।
- (ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए ननूना लेना अभिलिखित अन्वेपण के आधार पर विनिर्माता द्वारा अधिकयित किया जाएगा।
- (घ) निरीक्षण या परीक्षण करने के पण्चात् स्वीकृत नया अस्वीकृत सामग्री के पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियां यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाएंगी कि अस्वीकृत सामग्री का रंगलेप धौर संबद्ध उत्पादों के निर्माण में प्रयोग तो नहीं हो रहा है।
- (ङ) उपयुक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा नियमित भौर ब्यवस्थित रूप में रखे गए अभिलेख वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त होंगे।

प्रिक्या नियंत्रण :

- (क) कच्ची सामग्री भीर मध्यम श्रेणी उत्पाद आदि कोई हो, को सम्मिलिल करते हुए विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ब्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देण विनिर्माता द्वारा कच्ची सामग्री भीर मध्यम श्रेणी उत्पाद की विशिष्टताओं के साथ अधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) प्रक्रिया विनिर्वेशों में अधिकथिन उत्पाद को नियंत्रित करने के लिए उपकरण तथा उपस्करों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।
- (ग) विनिर्माण की प्रिक्षिया के बौरान बस्तुन प्रयुक्त नियंत्रण के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्वाप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

उत्पाद नियंत्रण :

- (क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच बहा तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हो।
- (ख) प्रत्येक बैंश से प्रतिनिधि नमूना लिया जाएगा सामूहिक नमूने को दो बराबर परख नमूनों में बांट दिया जाएगा ऐसा एक नमूना विनिर्माता द्वारा उत्पादन की अपेक्षाम्रों के लिए परीक्षित

किया जाएगा तथा बूसरा नमूना उसके ब्योरे सहित कम से कम छः माम के लिए निर्देश नमूने के रूप में रखा जाएगा।

- (ग) नमृता लेने ग्रीर परीक्षण के बारे में अभिलेख इस संबंध में बस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तना का सस्यापन यस्ते के लिए नियमित ग्रीर व्यवस्थित रूप में रखे आएंगे।
- (घ) अनुसूची H में निर्दिष्ट के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूननम स्वर होंगे।

परिरक्षण नियंत्रण :

विनिर्माता मध्यम तथा अस्तिम उत्पाद के परिरक्षण के लिए अपेक्षाएं अधिकथित करेगा।

पैकिंग निर्यक्षण :

- (क) अधिनियम की घारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के न्यूनतम विनिर्देशों की संतुष्टि की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देशों की अधिकथित किए जाएंगे तथा उनका कठोरता से पालन किया जाएगा।
- (ख) पैकिंग के संबंध में प्रयुक्त नियंत्रणों के लिए अभिलेख विनिर्माता द्वारा व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे ।

अन् सूचि-II

नियंक्षण के स्तर

(क) सारणी⊸I में इल्लिखित इत्याद के लिए

त्म भनेकाएं ते.							संवर्भ	नमूतों की संख्या	ग्रःबृ ति
1 2	<u> </u>					· · · ·	3	4	5
1. गेंद्रापन	•		,		-		इसप्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त भानक विनिर्देश	एक	স ি শীৰ
2. मुष्कत समय .	•			-			11	17	11
3. फिनिस			,				11	"	"
4 प्रति 10 लिटर मार			-				,,	11	"
 रंग , . 							"	11	1)
 खरोंच कठोरता . 					•		11	11	"
7. लिबीलापन तथा भ्रामंज	न ,		•				11	11	7,7
 निलंपन परीक्षण . 							-	n	,,,
9, रंगका पक्कोपन .	-	•					11	"	73
10. धम्ल धंग .	•	•				•	n	"	,,
11. भ्लेश प्वाइंट .) 7	n	11
12. क्षारता परीक्षण .							11	17	11
13. वाष्पशीण पदःर्थं			•				1)	11	11
14. पानी का भ्रजरोध							11	11	Jī
15. सम्ल का श्रवरोध			•	•			**	. 23	"
16. क्षार का भगरोध .							, ,	7)	,,
17. पिसाई की सकाई		•	-				D	11	11
18. विस्क मिता		٠					"	,,	11
19. चमक भ्रवरोध .					•		"	1)	1)
2.0. पानीकी मक्ता (%)							n	"	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
21. गील/पन				•	•		")	. 0	1)
22. इ.य-विशुत क्षमना परी	क्षण			,			17	1)	· · ·
 कायत एनेमल उष्मसह 			•	-			1)	1)	,,
24. कीपर सहित वानिश व	हः स्रवरोध	_					,,	"	"

(ख) यारणी-II में चिललियात एत्याद के लिए:

(1) सभी पकार की संक्लिप्ट वानियों के धतिरिक्त, (फिनिशिय के लिए संक्लिप्ट वानियों धीर क्रमारोधी वानियों, हवा मुक्कम, बिट्मन १४० में धनावा) सभी पकार के नैयार मिश्रित रंगलेप धीर एतेमल, प्लास्टिक धीर एकलिक नाइट्रो सैल्यूलींज लैंकर, साफ या कोमवियत के धितिरिक्त सभी प्रकार के इमल्सन रंगलेप, जिसमें फिल्टर, सतहों के प्राहमर पेस्ट रंगलेप और पेस्ट डिस्टेम्पर भी सम्मिलित है।

 कम वं.	भ्रपेक्षाएं,						सं वर्ष	नमूनों की संख्या	च ⁻ व्सि	टिप्पर्वाः
1	2					— —. •	3	4	5	6
1.	गाक्षापन .		4				इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिधेश	एक्	प्रति सेच	जब भी लागृही
2.	शुब्कन समय			•		-	3)	"	·11),
3.	फिनिश .		•				и	1)	"	"
4,	प्रतिक्रिटर/गैलन गार						n	11	"	11
5.	रंग .				•		1)	1)	n	. ,
6.	खरोंच कठोरता						17	17	**	71
7.	लवीलापन तथा द्यासंजन			-			11	23	"	11
8.	घम्ल यंश/भम्सीयता						71	,, t a	1)	"
9.	कारता .						19	n	n))
0.	विद्युत प्रावलता						"	n	ני	19
I 1.	द्रवण की बना में संकारण	से सुरका					11	17	"	17
l 2.	बाटपशील पदार्थ						"	11	11	,,
13.	भविषाकतता परस				-		11	11	33	11
	काल प्रभावजन		•				,,	11	"	n
1 5.	लेल का प्रभाव						n	17	n	17
	पतेण प्वाइंट			•			11	11	n	***
	माच्छन क्षमता		•				11)1	1)	71
	भ्रत्य परखें						"	,11	1)	,,

1::1	mrac	क्रिस्टेस्पर.	सने	16 1	मंग	HELL	ची र्वेड	र्थना	
1 11 1	מינוע	18865444	чч	en i	₹*1	αчі	MIMC		

1	2									3	4	5	6
1.	णुष्कन का समय	(कऽोरत	ा तथा	 पुनः	कोटिंग	की	विशेषताएं)			इस प्रयोजन के लिए भाग्यताप्राप्त	एक	प्रति वैष	जब भी शाग्हो
										मानक विनिद्देश			
2.	. फिलिश	.'	•					•		,, v i	, ¹⁷	""	n
3	. रंग						•	٠	•	,,		n	"
4.	. लाइट की चमक	•								"	· n	1)))
5.	. जाली पर ग्रवशे	ष								n	11	n ^c	n
6.	. शुब्क रगड़ने पर	प्रतिरोध				,	•		•	"	"	n 💆	11
7.	. जल विकर्षन का	मता								"	77 F.	n t	"
8.	भिश्रित रंगलेप की	ो घट स्र	स्था							n '	n 9	"	$_{n}^{r}$
9.	. गुणधर्मं प्रनुरक्षण	τ								"	n '7	") H
10.	. फैलाब क्षमता						÷	-		,,	"	" ^r	,,
11.	. फैलाब का समय						-			n	n	"	77 ₄
1 2.	. झमता						•			"	11	n	"
ı 3.	भ्रन्य परखे								•	17	73	17	n

 रंग प्रपेक्षितचनस्य प्रास्त्रम क्षेत्र वाब्यीकरण का प्रवेशव कोरी बूटानोल भान हाईब्रोकार्यन विलेयकों के ि सक्षारित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईब्रोकार्यन विले प्रम्ल धुलाई परवा 				• .				
 मासनन केत पाब्यीकरण का प्रवेशव कोरी बूटानोल भान हाईक्रोकार्यन विलेयकों के वि सक्तादित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईब्रोकार्यन विवे 					. इस प्रकोजन के लिए मान्यताप्राप्त मामक विनिर्देश	एक	प्रति नेष	जब भी शागू
 वाब्बीकरण का ग्रवेशय कोरी बूटानोल भान हाईड्रोकार्बन विलेयकों के ि सक्तारित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईड्रोकार्बन विलेय 					• "	17	77	,
 कोरी बूटानोल भान हाईब्रोकार्यन विलेयकों के ि सक्तान्ति गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईब्रोकार्यन विले 				•	. 11	,,	n	,,
 हार्रक्रोकार्यन विलेयकों के ि सक्तारित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हार्रक्रोकार्यन विले 					1 17	n	žī.	11
 हाईक्रोकार्यन विलेयकों के ि सझान्दित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईक्रोकार्यन विले 		-			. ,	1)	17	,,
 सकारित गंधक के लिए पर क्लोरीनित हाईब्रोकार्धन विले 		प्लाइट की	र मिश्चित	एनिसिन व्याइ			"	ta
8. क्लोरीनित हाईब्रोकार्यन विले	, =	_				,,	n	"
		तया वेंजीव	। मुक्त के	लिए परख	. ,,	"	,,	n
B. PICH MINING TIME .			<u>.</u>	,	. "	1)	"	,,
 हाईड्रोजन सल्फाईड तथा वि 	रकीपटैन के	लिए परख			. 3)	n n		 D
ा. सीसे से मुक्ति .				•	. "	,,	"	,,
1.2. फलेश प्वाइंट								
 विकेता तथा केता के बीच : 	सय हाई विक्रि	ष्ट परखे.	यकि कोई	i w'Y	. "	<i>1</i> 1	<i>n</i>	"
					. "	<u>.</u>		
(iv) रंगलेष के शिए संक्ष्सिण्टः	राल: ————							
1 2					3	4	5	6
1. विस्कासिता		•	•	•	. इस प्रयोजन के जिए भारयताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति थैन	जब भी लागू
2. अस्म माम					. 21	,,,	3 F	**
3. एम. पाईट (गलन विन्दु)	•		-	•	· n	it.	4, 1	11
4. स्वच्छता .					,	,,	11	А
5. अन्य परखें					.))	,,	, ,	,,
1 2	•				3 इस मयोजन के	<u>4</u> एक	5 प्रति नैच	6 जब भी लागृहों
					लिए मास्यता प्राप्त मानक विनिर्देश			
2. विशिष्टि घनत्व (या धनत्व)		•	•		**	,,	,, 1	+1
3. भ्रम्म मान					1)	,, l	,, }	11
	•				.,	,, <u>1</u>	n .	,,
4. अपर्वतन शालिका .	•							
	ं डिविन्दु)	•			,,	.,		.,
4. अपर्वतन शालिका 5. गलन (या सांद्रिकरण सें. ग्रेय 6. आयोहिन मान	ं व विष्दु)	•			,,	1)	D ·	<i>n</i>
 गलन (या सांद्रिकरण सें. ग्रेय 6. भायोडिन मान 	व विष्दु)				n n	12	n ,	٠.
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेय 6. भायोदिन मान 7. साबुन किरण मान	ग विण्दु)				р п р	n n	n n n	τ. <i>Β</i>
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेय 6. आयोडिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें	ब बिन्दु)				n n	12	n ,	₹,
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग 6. आयोडिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें vi) बिदुमनसक कोटिंग	र विष्धु)				n n n n	n n	n	5) 2) 2)
गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् शयोदिन मान . साबुन किरण मान . अन्य परखें .	ं व विष्डु)				" " "	n n	" " "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग 6. भायोदिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें vi) बिदुमनसक कोटिंग 1 2 1. विज्ञिष्ट धनस्व	ं व विष्डु)				n n n n	n n	n	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5 गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग 6 आयोडिन मान 7 साबुन किरण मान 8 अन्य परखें vi) बिदुमनसक कोटिंग 1 2 1 विज्ञिष्ट धनन्य 2 कीमकता बिन्धू	ं व विष्डु)				" " 3 इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त	" " 4 एक	" " "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् 6. आयोदिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें VI) विदुमनसक कोटिंग 1 2 1. विशिष्ट धनस्व 2. कीमकता विन्धू 3. बेधन परीक्षण	ं व विग्दु)				" " 3 इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त भानक विनिर्देश	n n	" " " 5 प्रति बैच	" " 8 अब भी ुलागृ है
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् 6. आयोदिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें VI) विदुमनसक कोटिंग 1 2 1. विशिष्ट धनस्व 2. कीमकता विन्धू 3. बेधन परीक्षण	ा विष्कु) 				य य उ इस प्रयोजन के जिए माम्यताप्राप्त भानक वितिर्देश	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	" " " 5 प्रति बेच	्र १ अब भी लागृह
5. गलन (या सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् 6. भायोदिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें VI) बिदुमनसक कोटिंग 1 2 1. विज्ञिष्ट धनस्य 2. कीमकता बिन्धू 3. बेधन परीक्षण 4. छश्चन परिख	र विण्डुं)				य य उ इस प्रयोजन के जिए माम्यताप्राप्त भानक वितिर्देश	0 2 2 3 4 Q 奪	" " " 5 प्रति बैच	ं ं अब भी लागृ ह
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् 6. कायोदिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें vi) बिदुमनसक कोटिंग 1 2 1. विज्ञिष्ट धनस्व	र विण्डु)		•		अ इस प्रयोजन के जिए मान्यताप्राप्त भानक विनिर्देश	0 2 2 3 4 Q 奪	,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	ं ं अब भी लागृ ह
5. गलन (मा सांद्रिकरण सें. ग्रेंग् 6. आयोडिन मान 7. साबुन किरण मान 8. अन्य परखें Vi) बिदुमनसक कोटिन 1 2 1. विज्ञिष्ट धनाव 2. कीमकता बिन्धू 3. बेधन परीक्षण 4. छीसन परख	ा विष्डु)				अ इस प्रयोजन के जिए मान्यताप्राप्त भानक विनिर्देश	77 77 78 78	" " " " " " " " " " " " " " " " " "	ह अब भी लागू है

1	2							3	4	5	6
1.	एस्यूभिनियम भूर्ण			,		-	-	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एम .	प्रति भैच	अवभी लागृहो
2.	वर्षमाम .							11	11	11	n
3.	छानने पर अवशेष (15	0 माइकोन	75 मा इ व	तेन 53	भा.मा.	छशनी)		n	11	0	12
4.	चिकनाई संश				-			n	*1	,,	,,
5.	फिनिश .					•		•,	1)	11	71
6.	अमने की विशिष्टताएं			_				1)	1)	,,	,,
7.	भाष्पणील पदार्थ,						-	11	17	11	,,
8.	गुणधर्म अनुरक्षण			,				11	n	,	n
9.	कौपर तथा सीसे सहित	कुल समाहि	यां		•			11	,,	,,	
	अन्य परखें	41		_				"	ĮJ.	,,	,,

अनुसूची–III

3004

[नियम 3 (खा) देखें[]

- 1.1 रंगलेप ग्रीर संबद्ध उत्पादों के परेषण को अधिनियम की घारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता सुनिक्ष्रित करने के लिए निरीक्षण भीर परीक्षण के अधीन किया जाएगा।
- 1.2 जब कि संविदात्मक विनिर्देशों में अस्यथा उल्लिखित न हो, नमूना मापवंड भीर निकाले गए नमूनों की संख्या अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूजित न्यूमतम अपेक्षाम्नों के अनुसार होगी।
- 1.3 एक लौट में लिए गए प्रस्पेक नमूने का प्रति 10 लीटर भार के लिए जहां कहीं भी लागू होगा अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा। यदि ये विनिर्धिष्ट मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं तो उसी लीट से लिए गए अलग-अलग नमूनों को एक सिम्मिलिल नमूना बनाने के लिए इकट्टा मिश्रित किया जाएगा। ऐसे एक परीक्षित नमूने का संगत विधिष्टिताओं के लिए परीक्षण किया जाएगा भीर दूसरा कम से कम छः मास के लिए इसके ब्योरे सहित निर्धिष्ट नभुने के रूप में रखा जाएगा।
- 1.4 यदि निर्धाल संविद्या में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो परीक्षण की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्दिष्टों के अनुसार होगी।

[फाइल सं. 6(5)/85-ई आई एंड ईपी] एन.एस. हरिहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd August, 1986

ORDER

S.O. 2656.—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Paints and Allied Products should be subjected to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said pur-

pose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. S.O. 355 dated 16th February, 1980 relaing to Paints and Allied Products except as respects, things done or omitted to be done, hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person who desire to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this Order in the Official Gazette of the Export Inspection Council of India, 11th Floor, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

- (i) To notify that Paints and Allied Products shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (ii) To recognise
 - (a) relevant Indian Standard or any other national standard; or standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;
 - (b) contractual specifications subject to the products satisfying the minimum requirements as set out in Appendix I—as the Standard Specifications for Paints and Allied Products
- (iii) To specify the type of quality control and Inspection in accordance with the draft Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1986 as set out in Appendix II to this Order as the type of inspection which shall be applied to such Paints and Allied Products prior to their export;
- (iv) To prohibit the export of such Paints and Allied Products in the course of international trade unless the same are accompanied

by an Inspection Certificate for export issued by an Agency established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Paints and Allied Products have been duly inspected in accordance with the standard specifications and requirements of the Act.

3. Nothing in this Order shall apply to the export by sea, land or air of bonafide trade samples of Paints and Allied Products not exceeding Rs. 500]- only in Free on Board value to the prospective buyers.

4. In this notification "Paints and Allied Products" means items given in Tables I and II to this Order.

TABLE I

- 1. Synthetic enamels.
- 2. Insulating Varnishes (air drying, Bitumen type).
- Synthetic Varnishes, finishing (General purposes).
- 4. Emulsion Paints, (Plastic Acrylic Emulsion).

TABLE II

- Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers, under-coating and finishing except synthetic enamels.
- 2. Varnishes of all types (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
- Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.
- 4. Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including filler, primers or surfacers.
- 5. Paste paints and paste distempers.
- Dry distempers, limecolours and cement colours.
- 7. Cement paints.
- 8. Thinners for paints.
- 9. Synthetic resin for paints.
- Processed oils for paints and drying or semidrying oils for paints.
- 11. Bituminous coatings,
- 12. Aluminium paste.

APPENDIX I MINIMUM REQUIREMENTS

1. General Requirements

- 1.1 Each primary container shall be marked with the following:—
 - (a) Name and class of the Material.
 - (b) Name of the manufacturer and or trade mark.
 - (c) Factory code when a manufacturer has more than one manufacturing unit.
 - (d) Quantity of the material.

- (e) Batch of manufacture.
- (f) Month and year of manufacture.
- 1.2 The primary containers in a pack shall be so packed as to avoid collisions amongst them.
- 1.3 The requirements of leakproofness and seam strength of containers shall be as laid down by the manufacturer.
- 1.4 The bulk containers (barrels) or the wooden cases or corrugated boxes in which primary containers are packed shall be well finished and strong enough to withstand hazards.
- 1.5 Handling instructions preferably in internationally accepted symbolic codes in respect of method of slinging, inflammable nature of product, vertical position of container and such other relevant aspects shall be predominantly displayed on the outer packs.
- 1.6 Each consignment shall be accompanied by instructions for use either directly printed on the containers or in the form of literature.

2. TESTS

2.1 The tests which shall be applied against a lot for export shall be as below:—

For Table I items—As per Annexures (i) to (iv). For Table II items—As per contractual requirements.

Note: In the case of Table II items, specifications against the characteristics in the relevant National Standards are to be mentioned in the contract as per buyer's requirements.

3. SAMPLING

3.1 The number of containers to be selected as samples per lot shall be as given below:—

SCALE OF SAMPLING

L (Number o	ot Size f container	s)	Number of containers to be selected for sampling		
Upto		50	3		
51	to	100	4		
101	to	200	5		
201	to	300	6		
301	to	400	7		
401	to	800	8		
801	to	abovo	10		

Note A 'lot' for the purpose of sampling shall be each batch of manufacture of the particular class of product bearing the particular factory code irrespective of the container sizes.

3.2 Preparation of test, samples.

Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litres where applicable and if found conforming to the specified standard, the material of individual samples drawn from the same lot shall be blended to make a composite sample. Tests for all remaining characteristics shall be conducted on the composite sample.

3.3 Methods of tests.

Methods of tests shall be as stipulated in the export contract. In the absence of such specific stipulation methods of tests shall be as per the relevant Indian Standard Specification.

ANNEXURE I

TESTS FOR SYNTHETIC ENAMELS

1. Preliminary Examination

The material in a freshly opened container shall not show livering, instability and hard settling. On stirring it shall form a uniform, smooth and homogeneous product suitable for application by brushing. However, after thinning the material shall be of spraying consistency.

2. Finish

When applied on a panel as prescribed, the finish shall be smooth and glossy, free from grittings, separation of colour or any other surface imperfection.

3. Fineness of Grind

When tested with Hegman's gauge it shall give reading between 6 and 7.

4. The material shall also comply with the requirements gien below :--

S.No.	Characteristics	Requirements					
(i) D r	ying time						
a)	Surface dry	8 hours maximum					
(b)	Hard dry	18 hours maximum					
(c)	Tack free dry	24 hours maximum					
(il) Co	lour	As specified by buyer (shell be a close match)					
	cosity in B-4 Ford Cup 30°C	Specified ± 15 seconds					
(iv) We	eight per 10 litros	Specified 3%					
(v) Fla	ish Point	Not below 30. C					
(vi) Ser	atch Hardness Test	To pass the test					
(vii) Fl	exibility and adhesion						
tes	st	- đo-					
(viii) S tr	ipping tost	-do-					

5. Colour Eastness Test

The sample shall pass the test.

Note—This test need not be done on every consignment. Each manufacturer shall carry out this test at least once in every six months for each formulation.

ANNEXURE II

TESTS FOR INSULATING VARNISHES (AIR DRYING, BITUMEN TYPE)

1. Preliminary Examination

The material in a freshly opened container shall be dark brown to blackish in colour, liquid in state, free from skin formation, foreign matter and sediments. On stirring it shall become a smooth, uniform and homogeneous mixture.

2. Reaction of Varnish with Copper

The copper shall not change colour when tested.

- 3. (a) Electric strength in volts m. in air at room temperature 5000 volts mm. (Minimum)
 - (b) Electric strength after immersion in water

The material shall pass the test at 3000 volts mm. (Min.)

4. The material shall also comply with the requirements given below:—

S.No.	Characteristics	Requirement
(i) We	ight per 10 litres	Specified ± 5%
(ii) Vis	cosity in Ford Cup	
B -4	at 30°C.	Specified ±15 seconds
(iii) Dr	ying time	<u>-</u>
(a)	Hard dry	6 hours maximum
(b)	Tack free dry	24 hours maximum
(iv) Fla	sh point	Not below 30°C
(v) Co		As per sample (shall be a
		close match)
(vi) Co	mpatibility or dilu-	
tio	n ability	100%
(vii) No	n-volatile matter %	Specifed ± 3%
(vili) Ro	sistance to Mineral Oil	
(ix) Th	ermal endurance test	-do-
(x) Fl	exibility and Adhesion	-do-
tos	t	

ANNEXURE III

TESTS FOR SYNTHETIC VARNISHES, FINISHING (GENERAL PURPOSES)

- 1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall show no sign of livering or instability. The material shall be clear, trasnparent and free from sediment and skin. On stirring its components shall be rapidly dispersed to smooth and homogeneous.
- 2. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish shall be smooth and glossy.
- 3. The material shall also comply with the requirements given below:—

S.No.	Characteristic	Requirement	_
(i) I	Orying time		
1	(a) Surface dry	6 hours (max.)	
	(b) Hard dry	18 hours (max.)	
	(c) Tack free dry	24 hours (max.)	
(ii) (Colour	As per sample (shall be close match)	a
(iii) I	Plash point	Not below 30°C	
(iv)	Volatile matter %	60% Max.	
(v) '	Viscosity at 30° C	1-3-stokes	
(vi)	Acid value	25.0 (Max.)	
vii)	Weight per 10 litres	Specified ± 3%	
(vili)	Resistance to Alkali	To pass the test	
(ix)	Resistance to Acid	-do-	
(x)	Rosistance to Water	-do-	
(xi)	Scratch hardness test	-do-	
, ,	Flexibility and Adhesion test	-do-	
(xiii)	Strlpping test	-do-	

ANNEXURE IV

TESTS FOR EMULSION PAINTS (PLASTIC/ACRYLIC EMULSION)

- 1. Preliminary Examination.—In a freshly opened container, the material shall be free from lumps and skins, shall not exhibit excessive settling caking, granulation, livering or colour separation and shall be easily dispersed with a stirrer to a smooth homogeneous state. It shall be free from offensive odour. The consistency shall be smooth and uniform suitable for applying by brushing or graying or by roller after thinning.
- 2. Drying Time.—The paint shall have a surface drying time of 1 hour (Max.) and recoating time of 4 hours (Max.).
- 3. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish of the film shall be smooth and matt or of egg shell gloss.
- 4. Colour.—It shall be a close match to standard specified by the foreign buyer.
- 5. Resistance to wet abrasion.—The paint film shall pass the test for 4000 oscillations.
- 6. Weight per 10 litres.—The tolerance on the specified weight per 10 litres shall be 5%.
 - 7. Fastness to light.—The sample shall pass the test.
 - 8. Resistance to alkali.—The sample shall pass the test.

APPENDIX II

(See paragraph (iii) of the proposal]

[Draft rules proposed to be made under clause (d) of subsection (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963)].

- 1. Short title.—These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1986.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—
 - (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963);
 - (b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras.
 - (c) "Paints and Allied Products" means

TABLE I

- (i) Synthetic enamels
- (ii) Insulating varnishes (Air drying, Bitumin type)
- (iii) Synthetic varnishes, finishing (General purposes)
- (iv) Emulsion Paints (Plastic/Acrylic Emulsion).

TABLE II

- Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers, under coating and finishing except synthetic enamels.
- (ii) Varnishes of all type (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumin type).
- (iii) Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.
- (iv) Nitrocellulose lecquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers.
- (v) Paste paints and paste distempers.
- (vi) Dry distempers, lime colours and cement colours.
- (vil) Cement paints.
- (viii) Thinners for paints.
- (ix) Synthetic resin for paints.

- (x) Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints.
- (xi) Bituminous coatings.
- (xii) Aluminium paste.
 - (d) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
 - (e) "Schedules" means scheduled appended to these rules.
- 3. Basis of Inspection.—Inspection of paints and allied products for export shall be carried out with a view to seeing that the paints and allied products conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963):
 - (a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Schedule I;

A٠

- (b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Schedule III.
- 4. Procedure of Inspection,—(1) An exporter intending to export a consignment of Paints and Allied Products shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.
- (2) For export of Paints and Allied Products of a manufacturing unit approved as having adequate inprocess quality control by the Panel of Experts constituted by the Agency for this purposes, the exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Paints and Allied Products intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Schedule I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.
- (3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied on the consignment to be exported.
- (4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while the intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.
- (5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency:
 - (a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality control as laid down in Schedule I to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose and the manufacturer had followed the instructions if any, issued by the Council/Agency in this regard, shall within three days issue an inspection certificate for export of the consignment of Paints and Allied Products. In case where the manufacturer is not the exporter, such verification and inspection of consignment as necessary shall be carried out by the agency as to ensure that the above conditions have been complied with. The agency shall visit the units at regular intervals and conduct snot checks on some of the consignments to verify the adequacy of inprocess quality control adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adpoting the required quality control measures or recommendations of the officers of the Agency at any stage of manufacture the unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control. In such cases, the unit shall rectify deficiencies and apply afresh for the approval of inprocess quality control.
 - (b) In case where the exporter has sought export under sub-rule 3(b), on satisfying itself that the consignment of Paints and Allied Products conform to the standard specifications, on the basis of inspection/

testing carried out shall within seven days of inspection issue an inspection certificate for export of the consignment of Paints and Allied Products;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall refuse to issue a certificate of inspection for export and shall communicate such refusal to the exporter within the said seven days alongwith the reasons therefor.

- (6) In case where the manufacturer is not the exporter for export under sub-rule 5(a) or the consignment is inspected under sub-rule 5(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal under rule 8 of these rules.
- 5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either:—
 - (a) at the premises of the manufacturer of such products;

or

- (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for inspection and testing exist therein.
- 6. Inspection Fee.—A fee at the rate of one rupee for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.
- 7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government;
- (2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials;
 - (3) The quorum for the panel of experts shall be three.
- (4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE I

[See under rule 3(a)]

Every manufacture of Paints and Allied Products shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product as laid down below together with the levels of centrol as set out in the Schedule II.

- (i) Raw Material Control:
 - (a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.
 - (b) The accepted consignments of raw materials shall either be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case counter checks shall be conducted atleast once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier or the purchased materials shall be regularly tested and inspected by the purchaser in own laboratory

- or in an outside laboratory/test house to ensure conformity with the laid down purchase specifications.
- (c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be laid down by the manufacturer based on the recorded investigations.
- (d) After the inspection or test 13 carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials to ensure that the rejected materials are not used in the manufacture of Paints and Allied Products.
- (e) Records in respect of the aforesaid controls regularly and systematically maintained by the manufacturer shall be adequate to verify the control actually exercised.

(ii) Process Control:

- (a) Detailed process specification for different processes of manufacture including those for raw materials and intermediate products, if any, shall be laid down by the manufacturer alongwith the properties of raw materials and intermediate products.
- (b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.
- (c) Records shall be maintained by the manufacturer to verify that the controls actually exercised during the process of manufacture are adequate.

(lii) Product Control:

- (a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to the standard specification recognised under section 6 of the Act.
- (b) A representative sample shall be drawn from each batch. The bulk sample shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested by the manufacturer for the requirements of products and the other preserved as referee samples alongwith its particulars for at least six months.
- (c) Records in respect of sampling and tests shell be regularly and systematically maintained to verify the adequacy of the controls in this regard actually exercised.
- (d) The minimum levels of control to check the product shall be as specified in Schedule II.

(iv) Preservation Control:

The requirements for preservation of intermediary and final products shall be laid down by the manufacturer.

(v) Packing Control:

- (a) A packing specification shall be laid down with a view to satisfying minimum of the standard specifications recognised under section-6 of the Act and shall be rigidly implemented.
- (b) Records in respect of the controls exercised in respect of packing shall be maintained by the manufacturer regularly and systematically.

SCHEDULE-II

LEVELS OF CONTROL

(a) For products mentioned in Table-I

S. No	R-quirement	Reference	No. of samples	Frequency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Consistency	Standard Sp cifica- tions recognised for the purpose	One	Per Batch
2.	Drying Time	,,	7.7	_
3.	Finish	**	* *	r 1
4.	Weight per 10 litres	17	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	'1
5.	Colour	***	., H	•
6.	Scratch Hardness	•1	D	,,
7.	Flexibility & Adhesion £	**	1)	11
8.	Stripping Test	**	**	* *
9.	Colour Fastness	,,	,,	,,
10.	Acid Value	1,	,,	,,
11.	Flash Point	**	,,	,,
12.	Alkalinity Test	4)	21	, ,,
13.	Volatile Matter	•	,,	,,
14.	Resistance to Water	,,	1,	"
15.	Resistance to Acid	12	**	,,
16.	Resistance to Alkali	11	44	**
17.	Pineness of Grad	1)	11	,,
18.	Viscosity	,,	"	**
19.	Gloss Retention	**	**	"
20.	Water Content (%)	11	1)	,,
21.	Wet Opacity	23	11	11
22.	Di-electric Strength Test	1)	,,	,,
23.	Resistance to Coil Enamel Insulation	,,	,,	,,
24.	Reaction of Varnish with Copper	,,	,,	"

(b) For products mentioned in Table-II

(i) Ready mixed paints and enamels of all types except synthetic, varnishes of all types (except synthetic varnishes for finishing) and insulating varnishes (air drying, bitumen type). Emulsion Points of all types except plastic and acrylic, Nitrocellulose lacquires, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers, paste Paint and paste distempers.

s. No	Requirement	Reference	No. of samples	Frequency	Remark
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consistency	Standard sp. cification recognised for the purpose	One	P.r Butch	Whenever applicable
2٠	Drying time	**	**	6.9	
3.	Finish	F1	1)	"	* *,
4.	Weight per litre/Gallon	11	1,	7.6	ī
5.	b olour	**	,,	**	ş #
6.	Stratch hardness	,,	,,	.,	** ,
7.	Firaibility & adhesion	,,	,,	,,	11
8.	Acid valu/acidity	7,7	7.1	"	11
9.	Alkalinity	"	**		•••
10.	Electric strength	• •	1)	••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Protection against corrosion under			19	**
	conditions of condensation	**	1)	,,	•
12.	Volatile matter	**	,,		F.1
13.	Toxicant availability test	,,	1,	4.4	- 4
14.	Aging	*1	1,	,,	**
15.	Effectofoil	3.1	1>	**	21
16.	Flash Point	*1	,,	,,	11
17.	Covering capacity	**	,,	,,	01
18.	Other tests	•••	1)	,,	, 11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Colour	Standard specifications recognised for the purpose	Оле	Por batch	Whenever applicable
2.	Sp. Gr. (or density)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,,	,,	3 7
3.	Acid value	"	11	11	P+
4.	Refractive Index	,,	**	• •	
5.	Melting (or solidification) point oc.	11	,,	,,	,,
6.	Iodine value	+ 7	,,	,,	**
7.	Saponification value	**	,,	11	**
8.		,,	,,	,,	,,

	Bituminous coatings				
(1)	(2)	(3)	(4)	(*)	(6)
1.	Sp cific gravity	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per b' 1ch	Wh never applies b
2.	Softening point		,,	,,	,
3.	P:n:tration test	**	,,	23.4	"
4.	Peol test	,,	,,,	1,	,,
5.	Impact strength	**	,,	1)	,,
б.	Sag test	**	,,	11	,,
7.	Ash content	***	**	1)	**
8.	Other tests	,,	,,	,,	**
) Aluminium pasts (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
vii 1) 1.		(3) Standard specifications	(4)	(5) P.r. batch	
1)	(2)	Standard specifications recognised for the			(6) Whenever Epplicable
1)	(2) Aluminium powder	Standard specifications recognised for the purpose	One	P.r batch	Whenever Epplies b
1)	(2) Aluminium powder Leafing value	Standard specifications recognised for the			
1)	(2) Aluminium powder	Standard specifications recognised for the purpose	One ,,	P.r batch	Whenever Epplies b
1) 1. 2.	(2) Aluminium powder Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content	Standard specifications recognised for the purpose	One	P.r batch	Whenever applies by
1) 1. 2. 3.	(2) Aluminium powder Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content Finish	Standard specifications recognised for the purpose	On- ''	P.r batch	Whenever spplics b
1) 1. 2. 3. 4. 5.	(2) Aluminium powder Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content Finish Settling properties	Standard specifications recognised for the purpose	One ,,	P.r batch	Whenever spplice b
2. 3. 4. 5. 7.	Aluminium powder Leafing value Residue on sieve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Sieves) Grease content Finish Settling properties Volatile matter	Standard specifications recognised for the purpose	One ,,	P.r batch	Whenever & pplice b
1) 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.	Aluminium powder Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content Finish Settling properties Volatile matter Keeping properties	Standard specifications recognised for the purpose ,, ,, ,, ,,	One .,,	P.r batch	Whenever & pplice b
1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content Finish Settling properties Volatile matter Keping properties Total imparities including copper and	Standard specifications recognised for the purpose ,, ,, ,, ,, ,, ,,	Onc .,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,	P.r batch	Whenever & pplice b
1)	Aluminium powder Leafing value Residue on silve (150 micron, 75 Micron 53 micron LS, Silves) Grease content Finish Settling properties Volatile matter Keeping properties	Standard specifications recognised for the purpose ,, ,, ,, ,, ,, ,,	Onc .,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,	P.r batch	Whenever & ppliet b

\$CHEDULE III

[See under rule 3(b)]

- 1.1 The consignment of Paints and Allied Products shall be subject to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.
- 1.2 Unless otherwise mentioned in the contractual specifications, the sampling criteria and the number of samples to be drawn shall be as per the minimum requirements notified under Section 6 of the Act.
- 1.3 Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 1 litre wherever applicable. If they are found to be conforming to the specified standard individual samples drawn from the same lot shall be blended together to make composite sample and then shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested for the relevant characteristics and the other preserved as referee sample alongwith its particulars for atleast six months.
- 1.4 If not otherwise specified in the export contract, methods of testing shall be as per relevant Indian Standards Specifications.

[F. No. 6(5)|85-EI&EP] N. S. HARIHARAN, Director

उद्योग मंद्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

मई विल्ली, 15 जुलाई, 1986

का, द्या. 2657.—एकाधिकार तथा प्रवरीधक व्यापारिक व्यवहार प्रक्रिमियम, 1969 (1969 का 54) की घारा 26 की उपधारा (3) के श्रमुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा में सर्व मोपाल गुगर इण्डस्ट्रीज

लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सेहोर (मध्य प्रदेण) -466003 में है, (पंजीकृत प्रमाण पत्न संख्या 1112/75) के उक्त प्रधिनियम के भन्तर्गंत पंजीकरण के निरस्तीकरण को भविमुचित करती है।

> [संख्या 16/12/86-एम. -3] ग्रार. डी. मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2657.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Ms. Bhopal Sugar Industries Limited having its registered office at SEHORE (M.P.)—466003 under the said Act (certificate of Registration No.—1112|75).

[No. 16|12|86-M. III] R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

खास और नागरिक पृक्षि संत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 8 ज्लाई, 1986

का. भा. 2658.—सदस्य, वायदा बाजार भायोग, बम्बर्ड के रूप में भ्रपने बढे हुए कार्यकाल के पूरा होने पर श्री ए. एन. कोल्हाटकर, बार्ड. ग्रार. एम. (भार्ड. टी.) ने 30 जून, 1986 के श्रपराहन से भायोग में सदस्य के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

> [मं. ए-12011/17/82-प्रशा. -II] भो. पी. खंत्रपाल, ध्रवर सचित्र

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 8th July, 1986

S.O. 2658.—On the completion of his extended term as Member, Forward Markets Commission, Bombay, Shri A. N. Kolhatkar, I. R. S. (11), relinquished charge of the post of Member in the Commission on the afternoon of the 30th June, 1986.

[F. No. A-12011|17|82-Estt. II] O. P. KHETRAPAL, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय (कोथला विभाग)

मई दिल्ली, 10 जुलाई, 1986

का० आ०.2659.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (धर्जन क्षेत्र विकास) प्रधिनियम, 1957 (1957 का 20) की घारा 4 की उप-धारा (1) के प्रधीन जारी की गई, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की प्रधिसूचना सं. का. भा. 2308 तारीखा 15 मई, 1985 द्वारा, उस अधिसूचना ने उपायक धनुसूची में विनिविष्ट परिक्षेत्र में 816.50 एकड़ (लगभग)

श्रपमे भागय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला भाभिप्राप्य है ;

या 330,42 हेक्टर (लगभग) भूमि में कीयले का पूर्वेक्षण करने के

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपावद्य ग्रनुसूची में विणत 816.50 एकड़ (लगभग) या 330.42 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का ग्रजैन करने के ग्रपने भ्रामय की सूचना देती है;

टिप्पण :— 1. इस मधिसूचना के भन्तर्गत माने वाले केत के रेखांक सं. राजस्य 1/86 तारीख 4-1-86 का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्जसल हाउस स्ट्रीट, कलकता-1 के कार्यालय में मध्यवा सेन्ट्रल कोलंकील्ड्स लिमिटेड (राजस्व भनुभाग) वरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

हिष्पण :— 2. कोयला धारक क्षेत्र (प्रजीव और विकास) प्रधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान भाक्षण्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :—

"8. (1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के ग्राधीन ध्रियमूचना जारी की गई है, हितबढ़ कोई भी व्यक्ति, क्रिश्चसूचना जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग में या उस पर के किन्हीं क्रिश्चगरों का श्रर्जन किए जाने के बारे में धाक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :---इस घारा के प्रयोक्तिर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना भाक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्कयं किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मादेश सक्षम

प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी बाक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर वेगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोंई हैं, करने के पश्चात् जो वह अवस्यक समझे या तो बारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न दुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिकारिंगें और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अधिकास सिहत विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिय्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबढ़ समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का बावा करने का हकवार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं प्रधिकारों की इस प्रधिनियम के स्थीन प्रजित कर लिया जाता।"

टिप्पण: केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकला को उक्त प्रधिनयम के प्रजीन सक्रम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

धनुसूची इः उत्तर बुंदू ब्लाक दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र जिला हजारीयाग (यिहार)

र्घाजित की जाने वाली भूमि : सभी प्रधिकार

कम संग्राम	थाना	थाना सं०	জিলা	क्षेत्र	टिप्पणिया
ब्लाक ''क''					
1. बसारिया	मांडू	38	हजारीबाग	179.00	भाग
2. बुंदू	मांडू	39	"	320.00) भाग
3. टोंगी ब्लाफ 'ख'	मांबू	135	1*	224,00) भाग
4. चोरघारा उर्फ (खर पतनगर)	रामगद	55	,,	93.50) भाग
	 कुश अन्न	:	816.50 ए क	 इड्(लगभग)	
	या		330, 42 हैय	टर (लगभग))

क्लाक ^{(*}क["]

बसारिया ग्राम में ग्राजित किए जाने वाले प्लाट सं०

228, 229 (भाग), 30, 32 से 255, 256 (भाग), 257, 258 (भाग), 276 (भाग), 277 (भाग), 278 (भाग), 287 (भाग), 327 (भाग), और 432 (भाग)

बंद ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट सं०

55 (भाग), 59 (भाग), 60, 61 (भाग), 62 (भाग), 63 (भाग), 65 (भाग), 136 (भाग), 137 (भाग), 138 से 209, 210 (भाग), 211 (भाग), 212 (भाग), 213 से 221, 222 (भाग), 223 से 227, 228(भाग), 229 (भाग), 230, 231, 232, 233(भाग), 234 (भाग), 235 (भाग), 236 (भाग), 237 (भाग), 247 (भाग), 249 (भाग), 293 (भाग), 294 (भाग), 295 (भाग), 296, 297, 298 (भाग),

428 (भाग), 474 (भाग), 475 से 480, 481 (भाग), 482 से 500, 501 (भाग), 502 से 506, 507 (भाग), 508 से 558, 559 (भाग), 574 (भाग), 575, 576 (भाग), 577 से 598, 599 (भाग), 604 (भाग) 605 (भाग), 606 (भाग), 607, 608, 609 (भाग), 610 से 614, 615 (भाग), 616 से 641, 642 (भाग), 649, 650, 654 और 655। टोंगी ग्राम में भजित किए जाने वाले प्लाट सं०

936 (भाग), 943 (भाग), 944, 945, 946 (भाग), 947 से 976, 977 (भाग), 978, 979, 980 (भाग), 981, 983 (भाग), 991 (भाग), 992, 993 (भाग), 994, 995, 996 (भाग) भीर 1025 (भाग)।

ब्लाक ''ख''

चोरधारा उर्फ खरपतनगर ग्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं०

7 (भाग), 8 (भाग), 9 से 19, 21, 22, 23 मीर 24। बलाक 'क" का सीमा वर्णन :

क—स्त्र रंखा, बसारिया ग्राम में, दामोदर नदी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है।

खा⊸ग रेखा, बुंदू ग्राम में, वामोदर नदी की पूर्वी सीमा के भाग की साध-साथ जाती है।

ग-च रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट सं. 560 भौर 562 का उत्तरो सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं. 576 से होकर जाती है (जो कोयला घारक क्षेत्र (ग्रर्जन भौर विकास) ग्रधि-नियम, 1957 की धारा 7(1) के ग्रधीन लापांगा ब्लाक विस्तार II की सम्मिलित सीमा का भाग बनासी है)।

च-इ-च रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट सं० 576, 574, 576 से होकर, प्लाट सं. 642 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ भौर प्लाट सं. 642 से होकर जाती है भौर गृदू भौर टोंगी ग्रामों की मिमलित सीमा से भागके साथ-साथ जालो है (जो सिरका कोलियर। विस्तार के 102.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला घारक क्षेत्र (धर्जन और विकास) भोवनियम, 1957 के ध्रधान प्रजित क्षेत्र की सम्मिलत सीमा का भाग बनाती है)।

च-छ रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं. 993 से होकर जाती है (जी सिरका कोलियरी विस्तार के 102.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला घारक क्षेत्र (प्रजैन भौर विकास) मिधितयम, 1957 की घारा 9(1) के श्रधीन ग्रजित क्षत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है।

छ-ज रेखा, टोंगी भीर सिर्का ग्रामों की सम्मिलत सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है।।

ज-स रैखा, टोंगी प्राम में प्लाट सं. 993 से होकर जाती है (जो सिरका कोलियरी विस्तार के 140.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला घारक क्षेत्र (प्रार्गन और विकास) प्रधिनियम, 1957 के प्रधीन श्रीजत क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

ब-ज रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं॰ 993, 996, 993, 991 977, 980, 983, 1025, 946 से होकर जाती है।

अ-क रेखा, टोंगी पाम में प्लाह सं. 946, 943 भीर 936 से होकर जाती है, बुंदू पाम में प्लाह सं. 615, 604, 609, 605, 606, 599, 507, 428, 501, 428, 474, 481, 474, 298, 295, 294, 293, 210, 211, 212, 222, 223, 249, 228, 247, 228,

229, 233, 234, 236, 237, 235, 137, 136, 62, 63, 61, 65, 559, 55, 559, 55, 559 भीर 59 से होकर जाती है, फिर बसारिया ग्राम में 432, 256, 327, 256, 258, 256, 276, 277, 278, 287 भीर 229 से होकर जाती है भीर भार-भिक्त बिन्दु "क" पर मिलती है।

ब्लाक "ख"

z--8

रेखा, चारधारा ग्राम में प्लाट सं. 8, 7 भौर 8 से होकर जाती है (जो लापोगा ≆लाक विस्तार के लिए कोयला धारक क्षेत्र (प्रजंन भौर विकास) भ्रधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के भ्रधीन भ्रजित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ठ-ड रेखा, चौरधारा ग्राम में थ्लाट सं. 26 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है (जो चौरधारा ब्लाक के लिए कीयता धारक क्षेत्र (ग्रर्जन ग्रीर विकास) प्रधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के भग्नीन ग्रजित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ड-ढ-ट रेखा, चौरप्रारा ग्राम में वामोदर नदी की पूर्वी, उत्तरी ग्रीर पश्विमी सोमा के भाग के साथ—साथ जाती है ग्रीर ग्रारम्भिक बिन्दु"ट" पर मिलती है।

[सं. 43019/33/84-सी ए]

MINISTRY OF ENERGY

(D partment of Coal)

New D lhi, the 10th July, 1986

S.O.2659.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Min s and Coal (Department of Coal) No. S.O. 2303 dated the 15th May, 1935 issued and remay ction(1) of section 4 of the CoalB aringAreas (Acquisition and D velopment) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government green pice of its incention to prospect for coalin 816-50 acres (approximately) or 330.42 hectares (approximately) of the leads in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And while-as the Cintral Gov imment is satisfied that coal isobtainable of the said lands;

Now, therefore in exercise of the powers confered by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government here by give notice of its intention to acquire the lands measuring 316.50 hours (approximately) or 330.40 hectares (approximately) of scribed in the Schedule appended here to:

Not 1:—The olon No. Rev/1/36 dated 4-1-36 of the area covered by the coefficient many beinspected in the Office of the Deputy Commission, a Hazaribi ghe (Bihar) or in the Office of the Coefficient and Control Coefficient for the Office of the Coefficient (Button) Coefficient (Button) Dorbhanga Hous, Ranchi (Bihar).

Note? —Attention is her by levit deto the provisions of section 8 of the Chal Barring Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows —

"3'(1) Any person interested in any land in respect of which a notification underested on 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation—It shall not be an objection with in the meaning of this is even for any person to say that he hims it desires to undertake mining operations in the land for the production of contant the tsuch operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(*) Every objection under sub-section (1) she il be mede to the completent authority in writing, and the completent authority shell give the objector an opportunity of being heard either in person or by all gelipractition read shall, after her ring all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks increase any, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different port in respect of different percels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with their cord of the proceedings half by him, for the diction of that Government.

(3) Forth purpos softhis sotion, approachall be deamed to be introsted in land who would be engitled to claim an interesting componential in land or any right, in or over such land were acquired under this wet.

Not 3:—The Coal Controller, 1, Council House Street, C. louter, has be nappointed by the Centrel Government as the computant authority under the Act.

SCHEDULE NORTH BUNDU BLOCK NORTH KARANPURA COALFIELD DIST. HAZ'RIBAGH (BUIAR)

Lands to be acquir d All Rights

S ri 1 numb r		Villeg:	Thana	Thana number
Black 'A'	1.	B saria	Mandu	38
	2.	Bundu	Mandu	39
	3.	Tongi	,,	135
Block 'B'	4.	Chordhara clias (Kharpatan	Ramgarh lagar)	55

District	Ar(B	Romarks
Hizarib gh	179 00	Part
,,	320.00	,,
,,	274.00	,,
19	93.50	**

Total area—316 50 acr s (approximately)
Or 330.42 h ctares (,,)

Block 'A'

Plot numb rato b acquir d in vill g Basaria :-

208, 209 Part), 230, 232 to 255, 256(Part), 257, 258(Part), 275(Part), 277(Part), 273(Part), 287 (Part), 327(Part), and 432 (Part).

Plot numbers to be acquired in villag Bundu :-

55(Part), 59(Part), 60, 61[Part), 67(Part), 63(Part), 65(Part), 136(Part), 137(Part), 138 to 209, 210(Part), 211)(Part), 212 (Part), 213 to 221, 222(Part), 223 to 227, 228(Part), 229(Part), 230, 231, 232, 233(Part), 233(Part), 237(Part), 237(Part), 237(Part), 237(Part), 247 (Part), 249(Part), 293(Part), 294(Part), 295(Part), 296, 297, 298(Part), 418(Part), 474(Part), 475 to 480, 481(Part), 482 to 500,

501(Part), 502to 506, 507(Part), 508 to 558, 559(Part), 574(Part), 575, 576(Part), 577 to 598, 599(Part), 604(Part), 605(Part), 006 (Part), 607, 608, 609(Part), 610 to 614, 615(Part), 616 to 641, 647 (Part), 649, 650, 654 and 655.

Plot numbers to be acquired in village Tongi :-

936 (part), 943(Part), 944, 945, 946(Part), 947 to 976, 977 (Part), 978, 979, 930(Part), 981, 983(Part), 991(Part), 992, 993(Part), 994, 995, 996(Part) and 10°5(Part).

Block 'B'

Plot numbers to be acquired in Village Chordhara alias Kharapatnagar:

7(Part), 3(Part), 9 to 19, 21, 22, 23 and 24. Boundary description of Block 'A'

- A B line passes along the northern boundary of Damodar river in village Basaria.
- B-C line passes along the part eastern boundary of Damodar river in village Bundu.
- C-D line passes along the northern boundary of plot numbers 560 and 562 through plot number 576 in village Bundu which forms part common boundary of Lapanga Block Extn. II U/s 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development Act, 1957).
- D-E F lines pass through plot numbers 576, 574, 576 along northern boundary of plot number 642 and through plot number 642 in village Bundu and along part common boundary of villages Bundu and Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 of Sirka Colliery Extn. for an area of 102.00 acres).
- F-G line passes through plot numbers 993 in village Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/s9 (1) of Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 of Sirka colliery Extn. for an area of 102.00 acres).
- G H line passes along the part common boundary of villages Tongland Sirka.
- H-I line passes through plot number 993 in village Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/3 9 (1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 of Sirka colliery Extn.

 III for an area of 140,00 acres).
- I-J line passes through plot numbers 993, 996, 993, 991, 977, 980, 983 1025, 946 in village Tongi.
- J-A line passes through plot numbers 946, 943 and 936 in village Tongi, through plot numbers 615, 604, 609, 605, 606, 599, 507, 428, 501, 428, 474, 481, 474, 298, 295, 294, 293, 210, 211, 212, 222, 223, 249, 228, 247, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 235, 137, 136, 62, 63, 61, 65, 559, 55, 559, 55, 559 and 59 in village Bundu, then through plot numbers 432, 256, 327, 256, 258, 256, 176, 177, 178, 287 and 229 in village Basaria and maots at starting point 'A'.

Block-'B'

K-L line passes through plot numbers 8, 7 and 8 in village Chordhara (which forms common boundary with the acquired U/s (9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 for Lapanga Block Extn.)

L. M liaz passes along northern boundary of plot number 26 in village Chordhara[which forms common boundary with the area acquired U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 for Chordhara Block[.

M-N-K liabs pass along the part eastern, northern and western boundary of Damodar river in village Chordhara and meet at starting point 'K'.

[No. 43019/33/84-CA]

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1986

शुद्धि पत

का.मा. 2660.—- भारत के राजपन, तारीख 22 फरवरी, 1986 के माग II खण्ड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 664 से 665 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की मधिसूचना का.मा. सं. 661, तारीख 4 फरवरी, 1986 में:——

पुष्ठ ६६४ पर--प्रधिसूचना में :---

- (1) "पूर्वक्षण" के स्थान पर "पूर्वेकण" पढ़िए।
- (2) "नागपुर 140004" के स्थान पर "मागपुर-440001" पश्चिए ।

धनुसूची में---

- (3) कमांक 1 में तहसीश स्तम्म के नीवे "बाधनगढ़" के स्थान पर "भाष्यगढ़" पढ़िएँ।
- (4) कम सं. 4 में प्राम स्तान्न के नीचे "पिनोरा" के स्थान पर "पिनौरा" पित्रिए धीर जहां कहीं यह गब्द प्रयुक्त किया ही बहां "पिनौरा" पित्रिए।
- (5) क्र.सं. 5 में टिप्पण स्तम्भ के नीचे "सम्पूर्ण" के स्थान पर "सम्पूर्ण" पढ़िए ।
- (6) क्र.सं. 9 में प्राम स्तम्म के नीचे "म्यामादोगरी" के स्थान पर "म्यामाक्षोगरी" पढ़िए भीर जहां कहीं भी यह सन्द प्रयुक्त किया ही वहां "म्यामाक्षोगरी" पढ़िए।
- (7) कम सं. 10 में साधारण संख्या स्तम्भ के मीचे "39" के स्थान पर "391" पढिए ।

सीमा वर्णन में---

रेखा ''ख - ग'' में ''कोहक'' के स्थान पर ''कोहका'' पढ़िए। [सं. 43015/27/85-सी ए]

New Delhi, the 10th July, 1986

CORRIGENDA

S.O. 2660.—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 661, dated the 4th February, 1986 published in the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 22nd February, 1986, at page 665:—

Under the heading 'Boundary description',-

- (1) in line 11, for "Dogdowa" read "Dagdowa";
- (2) in line 15, for "through" read "through".

[No. 43015]27[85-CA]

कां.आ. 2681 — भारत के राजपत, तारीख 19 मप्रैल, 1986 के भाग II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में पृष्ठ क्रमांक 1753 से 1755 पर प्रकांत्रित भारत सरकार के जर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की ग्रीध-सुबना कां.गां.सं. 1562, तारीख 11 ग्रीक, 1986 में—

पुष्ट 1754 पर---

(1) बेलटिकरी प्राप्त में भाजित किए गए प्लांट स० में "365 से 372 (भाग)" के स्थान पर "365 से 372" भीर "529 से 531" के स्थान पर "528 से 531" पढ़ें।

[सं. 43015/28/85-सी ए]

S.O. 2661.—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 1562, dated the 11th April, 1986, published at pages 1755 to 1757 of the Gazette of India, Part-II-Section 3-Subsection (ii), dated the 19th April, 1986,—

AT PAGE: 1756:-

In plot numbers acquired in village Dipka for "446" read "644";

AT PAGE : 1757 :--

In Boundary Description in line N-A for plot number "563" read "653".

[No. 43015|28|85-CA]

का॰ आ॰ 2662.—भारत के राजभन्न तारीख 15 फरवरी, 1986 के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 607 से 608 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की मधिसूजना का. भा. सं. 578, तारीख 29 जनवरी, 1986 में:—

पुष्ठ 607 पर— प्रधिसूचना में :

- (1) "राजस्य अमुभाग" के स्थान पर "राजस्य मधिकारी" पिढ्रिए श्रिष्ठिसूची में : ।
- (2) "करकाती ब्लाक" के स्थान पर "करकटी ब्लाक" पढ़िए।
- (3) कर्म सं, 1 में भीन हेक्टर के स्तम्भ के नीचे "142.06"
 के स्थान पर "142.260" पिंडए ।
- (4) कम सं. 8 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "बरसला" के स्थान पर "बरतरा" पढिए ।
- (5) क्रम सं. 9 में टिप्पणियां स्तम्भ के नीचे "माृग" के स्थान पर "सम्पूर्ण" पढ़िए ।

पृष्ठ 608 पर सीमा वर्णन में :

(6) रेखा क-ख में "सरकरी" के स्थान पर "करकटी" पिछए ।

[सं. 43015/30/85-सीए]

- S.O. 2662.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 578, dated the 29th January, 1986, published at pages 608 to 609 of the Gazette of India, Part-II. Section 3-Sub-section
- (ii), dated the 15th February, 1986 at page 609, in the Schedule—
 - (i) for column heading "Sl.", read "Sl. No.";
 - (ii) against Sl. No. 12 under the main heading "District", for "South Shahdol Division, read "South Shahdol Division".

[No. 43015]30]85-CA]

का. था. 2663.—-भारत के राजपत तारीख 8 फरवरी, 1986 के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 530 से 531 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की मधिसूचना का.भा. सं .49 1 तारीख 30 जनवरी, 1986 में :—-

पुष्ठ 530 पर---धनुसूची "क" में :---

- (1) कम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "जुगदी" के स्थान पर "जुगदी" पिहिए ग्रीर तहसील स्तम्भ के नीचे "वानी" के स्थान पर "वणी" पिहिए ग्रीर जहां कही यह शब्द प्रमुक्त किया हो जस जगह "जुगाडी" ग्रीर "वणी" पिहिए।
- (2) अम संख्या 3 में ग्राम का नाम स्तम्भ के दीने "मुनगोली" के स्थान पर "मुंजोली" पढ़िए श्रौर जहां कहीं यह शब्ब प्रयुक्त किया हो उस जगह "मुंगोली" पढ़िए।
- (3) त्रम संख्या 6 में प्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "ताकावी" के स्थान पर "टाकली" पढ़िए और जहां कहीं यह प्रैंब्द प्रयुक्त किया हो उस जनाह "टाकली" पढ़िए।
- (4) त्रम संख्या 7 में प्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "चिखाली" के स्थान पर "चिखली" पढ़िए भीर जहां कहीं यह शब्द प्रमुक्त किया हो उस जगह "चिखली" पढ़िए।
- (5) कम संख्या 8 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "परमरोह" के स्थान पर "परमझोह" पहिए भीर जहां कहीं यह मध्य प्रगुक्त किया हो उस अगह "परमझोह" पहिए ।

सीमा वर्णन ब्लाक-1 में :---

- (6) रेखा "क-ख" में मनगंगा "पनगंगा" के स्थान पर "पेनगंगा" पिक्ए भीर जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "पेनगंगा पिक्ए ।
- (7) रेखा "ख-ग" में "बनर्गगा" के स्थान पर "पेनगंगा" पढ़िए।
- (8) रेखा "ग-य" में "खिखाली भीर कानखा" के स्थान पर "चिखली भीर चानखा" पढ़िए भीर "सिवानी भीर एनाक" के स्थान पर "सिवानी भीर एनाड" पढ़िए।
- (9) रेखा "च-क" में "बिन्द" के स्थान पर "बिन्दु" पहिए । मनुसूची "ख" में :---
- (1) "मार. लिंकल" के स्थान पर "राजस्व निरीक्षक मंद्रल" पढ़िए।
- (2) कम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "संगोधा" के स्थान पर "सांगोडा" पढ़िए ग्रीर "चंतूर" के स्थान पर "चान्तूर" पढ़िए ग्रीर "राजरा" के स्थान पर "राजुरा" पढ़िए।

पुष्ठ संख्या 531 पर :---

- (3) कम संख्या 3 में 5 स्तम्भ के नीचे "राजपुरा" के स्थान पर "राजुरा" पिक्रिए ।
- (4) ऋम संख्या 4 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "गदेगांव" के स्थान पर "गाडेगांव" पड़िए ग्रीर जहां कहीं यह शब्य प्रयुक्त किया हो उस जगह "गोडेगांव" पढ़िए ।
- (5) ऋम संख्या 7 में 4 स्तम्भ के नीचे "शैराज" के स्थान पर "शैरज" पढिए ।

सीमा वर्णन ब्लाक-11 में :---

(6) रेखा "क-ला" में "गडेगांव और खेरगाव व प्राप्त गडेगांव भीर कावटगांव" का के स्थान पर "गाडेगांव भीर खैरगांव भीर कावटगांव की" पढ़िए।

> [सं. 19/47/83-सी.एल./मो.ए.] समय सिंह, घवर समिष

- S.O. 2663.—In the rousscation of the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal, No. S.O. 497, dated the 30th January, 1986, published at pages 531 to 533 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th February, 1986, at page 532, under the heading "the Boundary Description Block-1.
 - (i) C-D, in line 2, for "Paramdok", read "Paramdoh";
 - (ii) D-E, in line 2, for "Siawni", read "Siwani" and in line 4, for "Kolagaon", read "Kolkaon";
 - (iii) E-E, in line 2, for "Villages", read "Village".

[No. 19|47|83-CL|CA] SAMAY SINGH, Under Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गीस मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का. या. 2664 — सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिकोगियों की केवखनी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की प्रारा 3 हारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूनपूर्व पैट्रोलियम मंत्रालय की 10 जून, 1985 की अधिक्षुचना के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार नीत्रे की सारणों के स्तम्भ (1) में बॉणत नैगमिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को, जो कि सरकार के राजपित अधिकारियों के रैंक के समतुन्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोगनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती हैं, जो उक्तवारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्ट में विनिधिष्ट सरकारी स्थानों के प्रयोग के लिए संपदा अधिकारिता की स्थानों के भीतर हों, उन्ता का होने स्थानों या उसके सम्पदा अधिकारियों को प्रवत्ते स्थानों के भीतर हों, उन्ता का श्रीनियम द्वारा या उसके सम्पदा अधिकारियों को प्रवत्त शिक्तियों का प्रवत्त करेंगे तथा अधिरोपित कर्नेयों का पालन करेंगे।

सारणी

श्रक्षिकारी का पद नाम

सरकारी स्थानों के प्रवर्ग ग्रौर ग्रधिकारिता की स्थानीय सोमाएं 🎎

__

1 उप निवेशक (सम्पदा एवं भवन) प्रशासन निवेशालय, तेन एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग, देहरादून-248003 उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में तेल श्रीर प्राक्टिनिक गैस भायोग की धौर से जसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधियहम की हो सिनाय इस प्रकार के जो प्रन्य सम्पदा ष्रिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्राते हों।

- उप निदंशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) क्षेत्रीय कार्या-लय, पश्चिमी क्षेत्र, तेल एवं प्राकृतिक गैस भाषोग, मक्करपुरा रोड; बड़ौदा-390009
- गुजरात राज्य कं बड़ौदा जिले में तेल शीर प्राकृतिक गैन प्रायोग की झोर से उसके ह्यारा पट्टें पर या अधिप्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा प्रधिकारियों के प्रणासनिक नियंत्रण में साते हों।
- उप निदेणक (कार्मिक एवं प्रशासनिक अहमवाबाद परियोजना, तेल एवं प्राकृ-निक गैस श्रायोग, श्रहमवाबाद-380005
- गुजरात .राज्य के श्रह्मदाश्वाद जिले में
 तेल ग्रीर प्राकृतिक गैन श्रायोग की घोर
 से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे गर
 या श्रधिग्रहण की हो स्थितए इस
 प्रकार के जो ग्रन्थ सम्पदा ग्रधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में
 श्राते हों।
- उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक (श्रंकलेश्वर परियोजना, तेल एवं प्राक्त-निक गैस श्रायोग, श्रंकलेंश्वर-393010
- गुजरात राज्य के बड़ीदा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस घायोग 1 की श्रोर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या प्रश्लिक्त की हो सिवाण इस प्रकार के जो भन्य सम्पदा प्रक्षिकारियों के प्रशासनिक नियंजण में झाले हों।

 उप निवेशक, मेहमाना परियोजना, तेल एवं प्राफ़तिक गैस आयोग. नेहसाना, गजरात राज्य गुजरात राष्य के मेहसाना जिले मे तेल भीर प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पहुँ पर या धिधग्रहम की हो निवाए इस प्रकार के जी ग्रन्य सम्पदा ग्रधि-कारियों के प्रशासनिक नियन्नण में प्राते हों।

6. संयथन निदेशक, कैम्बे परि-यो बना, तेल फ्रीर प्राकृतिक गैस भायोग, बैम्बे ।

गजनत राज्य के खेरा शिसे में लेल श्रीर प्राकृतिक गैस श्रायोग की श्रीर गे उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या ग्रिधियहण की हो नित्राए इस प्रकार के जो श्रन्य सम्पदा म्रधिकारियों के प्रणासनिक नियंद्रण में भाते हों।

 उप निदेशक, विप्रा परि-योजनाः तेल एवं प्राकृतिक र्गेस श्रायोग, श्रगरतना-799001

क्षिपरा राज्य में नेल और प्राफुनिक गैस भायोग की मोर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या प्रश्चिम्रहण दी हो सिवाएं इस प्रकार के ओ घन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंद्रण में माते हों।

S. उप निवेशक (फार्मिक एवं प्रशासनिक) तेल एवं प्राफ्र-तिक गैस सायोग पूर्वी क्षेत्र नजीरा।

भ्रमस राज्य में शिवसागर जोस्हट जिले में शियसागर गीलाघाट, जोरहाट, सरापत्थर, बोरहाला लक्ष्या में तेल एवं प्राकृतिक गैस भायोग की श्रोर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिप्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो ग्रन्य सम्ददा अधि-कारियों के प्रशासनिक दिवंद्रण में में अपने हों।

9. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक (नेल एवं प्राकृतिक गैस भायोग, कच्छर, परियोजना, सिएछर धसम राज्य के कच्छर जिले में तेल भ्रौर प्राकृतिक गैम भ्रायोग की श्रोर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या ग्रक्षिग्रहण को हो सिजाए इस प्रकार के जो भ्रन्य सम्पदा श्राध-कारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में ऋसे हों।

10. प्य निवेशक (शामिक एवं प्रधासस्ति) "कैलाण" छङा ठार, 2.५ कस्तु**रक्ष**ामधी मार्ग, नई दिएली ।

विल्ली/नई दिल्ली के संध्यासित क्षेत्र में सेख एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा या उसकी योर से उनकी या पट्टे पर लो अथवा मांग की गई ऐसी सम्प्राप, जो चत्य किसी सम्पदा शशिकारियों के नियंत्रण यें न हो।

[फाइल मं, फो-11023/1/85-मो,एन,जी /डो-Ш] भी. जी. भाजे, उप मचित्र

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS New Delhi, the 14th July, 1986

2664.—In exercise of the powers conferred by S.O. Section 3 of the Public premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (10 of 1971), and in supersession of the Notice ation a steel the 10th June, 1985 of the crestwhile Ministry of Perfoleon, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column 1 of the Table below, being Officers of the corporate authority, equivalent in rank to a gazetted Officer of Government to be Estate Officers for the

purposes of the Said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, in respect of the premises specified in column 2 of the said Table :-

TABLE

Designation of the Officer

Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction

2

1

and Housing) Directorate of Administration, Oil & Natural Gas Com-

mission Delicadun-248003

1. Deputy Director (Estate Premises belongong to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District Dehradun Uttar Pradesh except such of them as are under the administrative control of the other Estate Officers.

sonnel & Administration) Regional Office, Western Region, Oil & Natural Gas Commission, Makarpura Road Baroda-390009.

2. Deputy Director (Per- Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or o n behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District of Baroda Guiarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Offi-

3. Deputy Director (Personnel Administration). Ahmedabad Project. Oil & Natural Gas Commission Ahmedabad-380005.

Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District of Ahmedabad. Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

4. Deputy Director (Personnel Administration) Ankleshwar Project, Oil & Natural Gas Commission Ankleshwar-3930!0.

Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Baroach, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

Project, Oil & Natural Gra Commission Mehsana Gujarat State.

5. Deputy Director, Mehsana Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Mehsana Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

6. Joint Director, Combay Project, Oil & Natural Gas Cournissing, Cambay.

Premises belonging to or taken on lease or regulationed by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Khara, Guiarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

Project Oil & Natural Gas Commission Agartala-799001.

7. Deputy Director Tripura Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the State of Tripura except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

- 8. Deputy Director (Person- Premises belonging to, or taken nel & Administration) Oil & Natural Gas Commission Eastern Region. Nazira.
 - on lease or regulationed by or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in Sibsagar Golaghat Jorhat, Sarupathar, Borhalla Lakwa in the district of Sibsagar Jorhat in Assam State, other than those under the administrative control of other Estate Officers.
- 9. Deputy Director (Personnel & Administration) Oil & Natural Gas Commisslon, Cachar Project, Silchar.
- Premises belonging to, or take on lease or requisitioned by or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in district Cachar in Assam State, other than those under the administrative Control of other Estate Officers.
- 10. Deputy Director (Person- Premises belonging to or taken nel & Administration) "Kailash" 6th Floor, 26, K.G. Marg, New Delhi.

on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in Union Torritory of Delhi/ New Delhi, except such of them as are under control of the other Estate Officers.

[No. O-11023/1/85-ONG/D.III] C. B. BHAVE Dy. Secv.

नई विल्ली, 15 जुलाई, 1986

का, आ. 2665.--यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतिश होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवागाम की. जी. एस-I से जी. जी. एस-III तक पेट्रेशनयम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्**पायद** अन्भूची में वर्णित सृमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवस्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम भौर खनिज पाइपलाइन (भिम में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पानिलयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधित करने का अकार आगय मनददारा घोषिस किया है।

बगुर्ने कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे भारत लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेप तथा प्राकृतिक नैंग आयोग, निर्माण भीर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिमुचना की सारीख से 21 दिनों के जीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविध्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी. जी. एम.-I से भी. जी. एस III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य:----गजरात जिला:--खेडा तालका---मातर

गांब	सर्वे नंबर	हेक्टेयर	आगर से	न्टीयर
नवागाम	747	0	02	0(
	748/1	0	03	40
	749	0	03	5 (
	751/1	0	01	00
	738	0	06	3:
	कार्ट ट्रेक	0	01	0.0
	706	0	03	25
	615	0	0 1	0.0
	621/2	0	02	0.5
	620	0	03	0.0
	619/2	0	00	45
	618/1	0	02	0.5
	617/3	0	03	10
	632/6	0	0.0	50
	632/4	0	01	2 5
	609/2	0	01	3 5
	646/2	0	02	0 (
	464/3	0	01	7 :
	470/2	0	03	25
	470/1	0	04	25
	493	0	02	20
	492	0	02	1 8
	491/1	0	02	13
	482/2	0	00	25
•	490	0	02	70
	489	0	04	00
	482/3	0	01	0.0

[सं. O-12016/106/86-घो एन जी, की.- 4]

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2665.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Nawagam G. Gs. I to G G.S. III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine-als Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user flierein:

in the said land Provided that any person interested may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390003.)

shali also And every person making such an objection state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GGS I TO GGS III
State : Guiarat District : Kheda Taluka : Matar

State : Gujarat	District: Kheda	Taluka:	Mata	Г
Village	Survey No.	Hectare	Ате	Centiare
Nawagam	747	0	02	00
-	748/1	0	03	40
	749	0	03	50
	75 1/1	0	01	00
	738	0	06	35
	Cart track	0	01	00
	706	0	03	25
	615	o ´	10	00
	621/2	0	02	05
	620	0	03	00
	619/2	0	00	45
	618/1	0	02	05
	617/3	0	03	10
	632/6	0	00	50
	632/4	0	01	25
	609/2	0	01	35
	646/2	0	02	00
	464/3	0	01	75
	470/2	0	03	25
	470/1	0	04	25
	493	0	02	20
	492	0	02	15
	491/1	0	02	15
	482/2	0	00	25
	490	0	02	70
	489	0	04	00
	482/3	o	01	00

[No. O-12016/106/86-ONGD-4]

का. शा. 2666.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीस होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नयागाँमं सी॰टी॰ एक से जी, जी, एस-I तक पेट्रोलियम के परिवहन के निए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

भौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की विकान के प्रयोजन के लिए एतदपायद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद्द्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए आक्षेप मध्यम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण भीर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोवरा-9 को इस अधिसुचना की तारीख से 21 दिनों के भीसर कर सकेगा।

भीर ऐसा आक्षेप करने बाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हीं या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

नवानाम सी.टी.एफ. से जी.जी, एस-I तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य:गुजरात	जिला:	खेडा	न(स्का:—मातर
--------------	-------	------	--------------

र्गात	सर्वे नं,	हेक्टेयर	आार सेन	टीयर
1	2	3	4	5
तंबागाम	887	0	03	75
	868	0	05	15
	869	0	02	35
	870	υ	01.	50
	871	0	03	00
	872	0	04	30
	879	0	04	25
	880	0	04	92
	954	0	02	75
	955	0	02	50
	956	0	01	25
	957/2	0	00	37
	964	0	00	50
	962	0	02	00
	973	0	04	35
	974	0	03	25
	9 ७ ७ /ए	n	02	60
	987/1/ए	0	02	40
	989	0	02	40
	992/2	0	01	8 5
	992/1	0	01	0.0
	996	0	01	8(
	998/2	0	01	00
	998/1	0	01	0.0
	998/3	Ú	01	0.0
	998/4	v	01	0.0
	999/2	0	01	8
	1000	0	03	0
	कार्ट ट्रेक	0	00	2
	155	0	03	5
	154	0	02	0.0
	157	0	02	0.0
	162/3	0	03	0 (
	859/1	υ	01	7
	862	Ø	01	6
	858/2	0	01	60
	859/2	0	01	7

[सं. 0-12016/105/86-मो एन जी बी-4] पीर्व के राजगोपानन, दैस्क अधिकारी

S.O. 2666.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Nawagam C.T.F. to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be iald by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390003).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE
PIPELINE FROM CTF TO GGS I

Village Su	rvey No.	Hectare		
		11001410	Area	Cent iare
1	2	3	4	5
Nawagam 88		0	03	75
86	3	0	05	15
86	9	0	02	3 5
87	0	0	01	50
87	t	0	03	00
87:	2	0	04	30
87	9	0	04	25
88	0	0	04	92
95	1	0	02	75
95	5	0	02	50
95	5	0	01	25
95	7/2	0	00	37
96	1	0	00	50
963)	0	02	00
97	3	0	04	35
974	1	0	03	25
97.	5/ A .	0	02	60
98	7/1/A	0	02	40
989	•	0	02	40
9 92	2/2	0	01	85
993	2/1	0	01	00
990	5	0	01	80
998	3/2	0	01	00
998	3/1	0	01	00
998	3/3	0	01	00
998	3/4	0	01	00
999	2/2	0	01	85
100	00	0	03	00
Ca	rt track	0	00	25
15	5	0	03	50
154	l '	0	02	00
157	7	0	02	00
162		0	03	00
859		0	01	75
862		0	01	60
858		0	01	60
	9/2	Ō	01	75

[No. O-12016|105|86-ONG. D. 4.] P. K RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का. इ.च. 2667 ----यतः पेट्रोलियम और जनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के इन्धिकार का कर्जन) इन्धिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के क्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की इन्धिसूचना का. इ.च. अ. 806 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस इन्धिसूचना से संलग्ध अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के इन्धिकार की पाइपलाइनों को विष्ठान के लिए श्राजित करने का सपना आस्थय भोषित कर दिया था।

और यतः सकाम प्राधिकारी ने उन्त धिवियम की बारा ६ की उप-भारा (1) के मधीम सरकार को रिपार्ट वे दी है। ग्रीर भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उन्त रिपोर्ट्स पर विचार करने के पक्षात् इस मिल्लना से संलग्न अनुभूषी में विनिविन्द भूगियों में उपयोग का मधिकार मंजित करने का विनिश्चय किया है।

क्ष्म, ग्रतः उक्त ग्रिधिनियम की द्यारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित कश्ती है कि इस ग्रिधिस्चना में संलग्न ग्रामुच्ची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का ग्रिधिकार पाइपलाइन विष्ठाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा श्रीजत किया जाता है।

और घागे उस धारा की उपघारा (4) द्वारा प्रदेश प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के अजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख को निहित होगा।

धनुपूरक बाद धनुसूची एस. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्राजिन्ट

जनपट	तहसील	परगना	ग्राम	भटा मं ,	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालीन	कोंच	कोंच	क्योलारी	253	0-35	
				112	0-03	
				229	0-02	

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2667.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petrolcum, S.O. 806 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petrolcum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) or Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

	•	H.B.J. G	as Pipelir	ie Proje	ct	
District	Tahsil	Par- gana	Village	Plot No.	Area in	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Kyolari	253 112 229	0 35 0 03 0 02	

(No. O-14016|289184-GP)

as quantitative for the same function of the same of t

का . चा. 2668. चतः पेट्रोलियम् और खनिश पाइपलाइन (शूमि में उप-योग के द्विकार का ग्रर्जन) क्रिजिन्यम, 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ग्रधिसूचना का . ग्रा. सं. 808 तारीका 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस ग्रधिसूचना से संलग्न ग्रनुसूची में विनिद्दिष्ट भूमियों के उपयोग के ग्रधिकार को पाइपलाइनों को जिलाने के लिए ग्रजित करने का ग्रपना

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त ग्राधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) के ग्राधीन सरकार को रिपोर्ट दें दी है।

और धार्गे यतः केन्द्रीय सरकार मे उक्त रिपोर्ट्र पर विचार करने के पश्चात् इस मधिसूचना से संलग्न ग्रनुसूची में विनिद्धित झूमियों में उपयोग का ग्रधिकार ग्राजित करने का थिनिश्चय किया है।

भव, श्रतः उक्त भिवितियम की घारा 6 की उपद्यारा (1) द्वारा प्रवस मिनत का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा घोषित करती है कि इस ग्रविस्चना में संजन अनुसूची में विनिधिस्ट उक्त पूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतब्द्वारा भिजत किया जाता है।

और धागे उस धारा की उपधारा (4) हाहा प्रवक्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उसत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होंने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम की इस तारीख को निहित होंगा।

क्षनुषूरक वाद धनुसूची एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

अनपद	स र् सील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालीन	कोंच	कोंच	रेपुरा	31	0-12	
			[π]	O-1401	6/308/8	3 4/जीपी

S.O. 2668.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 808 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village !	Plot No.	Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Raipura	31	0 12	2
				lo. 0-	14016/308	/84-GP1

का.धा. 2669.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि —में उपयोग के ग्रिक्षकार का ग्राजंन) ग्रिष्ठितियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रिष्ठीम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ग्रिष्ठियुचना का ग्रा. सं. 805 तारीख 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रिष्ठ्युचना से मंत्रान धनुसूची में बिनिविष्ट भूमियों के उपयोग के ग्रिष्ठिकार को पाइपलाइनों को थिछाने के लिए ग्रिजित करने का अपना आशय योखित कर विया था

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उनत प्रधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के ध्रधीन सरकार को रिपोर्ट दें वी है।

और धार्ग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट्न पर विचार करने के पक्ष्यात् इस ग्राधसूचना से संख्यन ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का ग्राधिकार क्रॉजित करने का विनिय्चय किया है।

ग्रव, ग्रतः उक्त ग्रीधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्रारा घोषित करती है कि इस ग्रीधित्वना में संस्था ग्रमुसूची में विनिधिच्ट उक्त मूथियों में उपयोग का ग्रीधिकार पाइपसाइन विछाने के अयोजन के लिए एतव्द्रारा ग्रीजत किया जाता है।

और प्राप्ते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रश्चिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

श्चनुपूरक याद अनुसूची एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम ग	हासं. ह	तेत्रद्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालीम	जालीन	जालीन य	ोरा राठोर	245	0-09	

ं [सं. O- 14016/187/8-4जी.पी.]

5.0. 2669.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 805 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Re- mark
1	2	3	4,	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Gora Rathaur	245	0 09	

[No. O-14016-187/84G.P.]

का. छा. 2670.— यतः पेट्रां लियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ध्रिधकार का धर्जन) ध्रिधिनयम, 1962 (1962 को 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ध्रिधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंद्रालय की ध्रिधसूचना का. धा. सं. 129 तारीख 13-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ध्रिधसूचना से संलय्य ध्रनुसूची में विनिधिष्ट मूभियों के उपयोग के ध्रिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए ध्रिजित करने का ध्रपना ध्राजय पीषित कर विया था।

भीर यतः सन्नम प्राधिकारी ने उक्त धर्धिनियम की घारा 6 की उप-धौरा (1) के ग्राधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पक्ष्वात् इस ग्राधिसूचना से संलग्न ग्रानुसूची में विनिधिष्ट मूमियों में उपयो का ग्राधिकार प्रजित करने का विनिध्वय किया है।

ग्रन, श्रतः उनतं श्रधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ससर्कार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस ग्रधिसूचना में संलग्न ग्रमुसूची में विनिधिष्ट उक्त भूमियों में उप-योग का श्रधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा श्रजित किया जाता है।

और ग्रामे उस घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त पश्चित्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का ग्राधिकर केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिं, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

श्रमुपूरक साद श्रमुसूची एक. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेस्ट

जनपद	तहसील	परगना	प्राम	गाटा सं.	भेजफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालीम	कोच '	कोंच	देवगांव	504	0-01	

[स. O.14016/315/84जी-पी.]

S.O. 2670.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 129 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government; And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Deo- gaon	504	0 01	·—·

[No. O-14016/315/84-G.P.]

का. \$2.871.:— यतः पेट्रोलियम और खनिक पाइपलाइन (भूमि में उप योग के ग्रंधिकार का ग्रंजन) ग्रंधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रंधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ग्रंधिसूचना का. ग्रां. सं. 1296 सारीखें 13-3-86 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रंधिसूचना से संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के ग्रंधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के लिए श्रुजित करने का ग्रंपना ग्राशय ग्रीचित कर विया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त इर्ध्यनियम की घारा 6 की उप-धारा (1) के ग्राधीन सरकार को रिपोर्ट दे वी है।

और ग्रामे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम ग्राधिसूचना से संलग्न ग्रनुसूची में विनिविष्ट मूमियों में उप-योग का श्रीक्षकार ग्राजित करने का विनिध्यय किया है।

मन, मतः मधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित करती है कि इस मधिसूचना में संलग्न मनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का मधिकार पाइपलाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा मजित किया जाता है।

बार धारों उस झारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रक्षिकार केन्द्रीय सरकार में निष्ठित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण जि. में सभी बाधाओं से मुक्त करा में घोषणा के प्रकाशम की इस सारीका को निष्ठित होगा ।

धनुपूरक वाय धनुसूत्री एच. बी. जे. गैस पाइप साइन प्रोजेक्ट

तहसील	परगना	याम	गटा सं,	जे द्रफल	विवरण
2	3	4	5	в	7
जासीन			145	0-10	
		•	146	0-08	1
	2	2 3 जामीन जामीन	2 3 4	सं. 2 3 4 5 जालीन जालीन निजाम- 145 पुर	2 3 4 5 6 जालीन जालीन निजाम- 145 0-10

S.O. 2671,—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1296 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notificaction for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schodule)
H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun			0 10 0 06	

[No. O-14016/188/84-G.P.]

का. श्री. 2672: --- यतः पेट्रोलियम और खंगिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के श्रीकार का क्रजेंन) प्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की श्रीक्षसूचना का श्रा. स. 804 तारीख 19-2-86 ढारा केन्द्रीय सरकार ने उस श्रीध्सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के श्रीक्षकार को पाइपलाइनों को विछाने के लिए प्रजित करने का भपना श्रीवित कर विया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने ज़न्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चास् इस भ्रधिसूचना से संलग्न भ्रन्सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का ग्रधिकार भ्रजित करने का विनिश्चय किया है।

धन, ग्रतः खनत ग्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गर्निस का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संकार एतवृद्वारा घोषित कंचती है कि इस ग्रधिमूचना में संलग्न ग्रनुसूची में विनिदिष्ट उन्ते भूमियों में उपयोग का ग्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवृद्वारा ग्रजित किया जाता है।

आर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रैंदर्त शिक्षितमां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूभियों में उपयोग का श्रिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के सजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में भीषणा के प्रकाशन की इस तारीख की निहित होगा ।

धनुपूरक बाद धनुसूची

	'एच .	षी.	जे.	र्गं स	पाइप	लाइन	प्रोजेक्ट
--	-------	-----	-----	--------	------	------	-----------

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्र फल	विवरण
जालीन	जालीन	जालीन	ततार-	117	0-02	
	7		पुर			

[सं. 0-14016/183/84-जी, पी]

S.O. 2672.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 804 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act submited report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power-conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe line Project

District	Tahsii	Pargana	Village		Area in	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Tatar- pur	117	0 02	

[No. O-14016/183/84-G.P.]

का आ 2673. — यतः वेट्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की बारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं. 1289 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को विद्याने के लिए अजित करने का अधना आश्रय घोषित कर विद्यागा।

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिवोर्ट वेदी है।

भौर आगे यतः केन्द्रीय संकार ने उक्त रिपोर्ट पर सिवार करने के पश्चात् इस अधिमूचना से संख्या अनुसूची में सिमिविक्ट शूमिकों में ज्यायोग का अधिकार प्रधित करने का विनिध्वय किया है।

अस, अतः उक्त गिथितियम की भारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्वद्वारा घोषित करती है कि इस अधिधूषना में संस्कृत अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन ब्रिष्ठाने के प्रयोजन के निए एतद्वारा अंग्रित किया जाता है;

भीर अभे उस घारा की उपवारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेग देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के सजाय भारतीय गैस प्राधिकरण नि. में राभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक षाद अनुसूची एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ज नपद	तह्सील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेद	फल	विवरण
1	2	3	4	5		6	7
मांसी	मोठ	मोठ	चि रगांव	276	0	01	
			खुवं	299	0	08	
				319	0	02	

[सं. -O14016/3/84-जीपी]

S.O. 2673.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1289 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipchines Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50) of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that nothication for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conterred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Chirgaon Khurd		0 01 0 08 0 02	

[Na. O-14016/3/84-G]

भीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियभ को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिगोर्ट दे वी है;

भौर आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्धात् इस अधिसूचना से संलग्त अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिस करने का विनिध्चय किया है;

श्रव, अतः उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकर एतद्द्वारा करती घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त मूमियों में उपयोग का अधिकार याद्दयलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है;

भीर भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते तुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की निहित होगा।

अलुपूरक बाद अनुसूची एच.बी.जे. गैस पाक्ष्य लाइन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	भेत्र	फल	विवरण
1 -	2	3	. 4	5		в	7
भांसी	मोठ	मोठ	षेलमा	129	0	02	
				653	0	02	
				797	0	01	
				871	0	01	

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2674.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 1291 dated 13-3-36 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notificationhereby for laying the pipeline;

conforred by sub-And further in exercise of power section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shalf instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Prolect

District	Tahsil	Pargana	Village		Aren in acres	
	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Belma	129 653 797	0 02 0 02 0 01	

[No. C-14016/3/84-G.P.]

0 01

871

का . था . 2675 --- यतः पेट्रोलियस धीर खनिज पाडपसाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की खारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 807 तारीख 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट सुमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अभित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था:

भीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है,

बीर आगे यतः केन्त्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर जिचार करने के परचात् इस अधिसूचना से संजन्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अधिन करने का विनिधनम किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदुद्वारा भोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भृषियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजिल किया जाता है:

भीर आगे उस धारा की उपघारा (4) इत्रा प्रदत्त पाक्तियां का प्रयोग फरते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त मंभियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के यजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में बोयणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच बी जे. गैस पाइन आइन प्रोजेक्ट

जनपद	तष्ट्रसील	परगना	ग्राम	गाटा मं	क्षेत्र	फल	विवरण
1	2	3	4	5	 -	6	7
आलीन	कोच	कोंच	अटा	258	0	01	

[मं. 9-14016/306/84-जीकी]

S.O. 2675.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the fands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schodule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	-	Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7 -
Jalaun	Konch	Konch	At4	253	0 0	1
			íN	o. O-1	14016/305/	34-G.P.1

[No. O-14016/305/84-G.P.]

का , आ 2676 . - यतः पेट्रोलियम शीर खनिज पाइनलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1953 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के वेदं खियम मंत्रालय की अधिमूचना का. हा. सं. 1290 नारीख 13/3/86 क्मरा केन्द्रीय सरकार मे उस अधिमुखना से संख्यान अनुसूता में विकिद्धांद्र मिन्नयों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए आँगत करने का अपना आशय पोषित कर दिया था;

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियप की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन सरकार की रिपोर्ट देवी है:

भीर आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिवोर्ट पर विचार करने के परबात् इस अधियुचना से संलग्न अनुसूची थें थिनिविध्ट शुमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विजिय्यय किया है;

अब, अर्थ उक्त अजिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस मिक्त का प्रयोग करने हुए केल्दीय सरकार एसददारा घोषित करती है कि प्स अधिसूचना में सलग्न अनुमूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पादालाइन बिछाने के प्रयोजन के निए एतबुद्वारा अजिस किया जाता है ;

भीर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाव भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाद्याधों, से मुक्त रूप में भोषणा के प्रकाशन की इस सारीख ी-विदित्त होता ।

अनुपूरक बाद अनुसूची एच.ची.जे. नैस पाइप साइन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	प रगना	ग्राम	गाटा सं .	अंद्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	वरौदा	175	0	01

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2676.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 1290 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section. (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Baroda	175	0	01

[No. O-14016/3/84-GP]

का. था. 2677.—यतः पेट्रोलियम और खिनिज पहापलाइनः (भूमि में उपयोग के अधिकार का ग्रजेंन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंज्ञालय की प्रधिसूचना का. था. मं. 1288 तारी खा 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न ग्रनुसूची में िं निर्निष्ट भूमियों के उपयोग के प्रधिकार की पाइपलाईनों की विद्याने के लिए स्रितित करने का मूपना स्वास्त्रय वोषित कर दिया था;

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रक्षिनियम-की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट वे वी है;

और ग्रामें यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के परचात् इस ग्राधिसूचना से संकर्ण जनुसूची में विकिथिप्ट मूर्जियों में अपयोग का ग्राधिकार ग्राजित करने का विनिध्यम किया है;

भव, भ्रुतः उक्त मिनियम की घारा 6 की उपभारा (1) हारा प्रवक्त मक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसवृद्धारा थोक्ति करती है कि इस भविसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट उक्त भूमियों ने उपयोग का मधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव् द्वारा माजत किया जाता है:

श्रीर झागे उस घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त बिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उत्क मिसयों में उपयोग का झिंखकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय पैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

ग्रमुपूरक बाद श्रमुसूची एस.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

अनपव	सहसील	परगना	ग्राम	गटा सं ,	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मांसी :	मोठ .	मींठ	पुल ^{ग्र} हना	176	0 80	
			_	253	0 10	

सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2677.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 2288 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi .	Moth	Moth	Pulga- han	176 253	0 50 0 10	

[No. O-14016/3/84-G.P.]

गा.धा. 2072—महा हेंद्र निजय और यतिज राष्ट्रभताइम (भूमि में छपणेग के अधिकार को अर्थन) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम संज्ञालय की अधिम्चना का. आ.सं. 1292 सारीख 13/3/86 द्वारा केल्प्रीय सरकार ने उस अधिम्चना से संनग्न अनुसूची में विनिविध्य भूमियों के उपयाग के अधिकार को पाइप काइनों को विद्यान के लिए अजित करने का अपना आस्य धोषित कर दिया था.

---- और यतः भक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के ग्रजीन सरवार की रिपोर्ट दे दी हैं;

और धार्ग मनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार भरते के पत्रचात् इस अधिसुचना सं संख्यान अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपमीय का अधिकार अजिन करने का थिनिण्यम किया है:

भ्रत, भ्रत: उफ़ शिविनयम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस धिक्षसूचना में संलग्न भ्रनुसूची में जिनिहिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का ग्रीविकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा भ्रामिन किया जाता है;

और प्राणे उस धारा की उपघारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वेती है कि उक्त शूमियों में उपकोग का श्रिप्तकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय धारतीय पैन प्राधिकरण लि. में सभी याधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस सारीख को निहित होगा।

ग्रनुपूरक जाय ग्रनुसूची एच.सी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं,	क्षेत्र	দেশ	विवरण
1	2	3	4	5		6	7
शांमी	मोंठ	मोंठ	मङ्ग्रा	603	υ	10	
				624	0	0.2	
				633	0	06	
				651	υ	0.4	
				654	0	04	
				653	0	04	
				636	σ	05	

[मं. O-14016/3/84-जी.पी.]

S.O. 2678.—Whereas byb notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 1292 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Congruence thereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laving the pipeline;

555 GI/86---5

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area		Re- mark
1	2	3	4	5		6	7
Jhansi	Moth	Moth	Lada-	603	0	10	
			ware	624	0	02	
				633	0	06	
				651	0	04	
				654	0	04	
				653	0	04	
				638	0	05	

[No. O-14016/3/84-G.P.]

का॰ झा॰ 2079: -- यतः पेद्रोलियम भौर खिला पाइपलाइत (भूमि में अन्योग के प्रविकार का भर्जन प्रविक्तिम, 1962 (1962 का 50) की वारा 3 की जपधारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंसास्य की प्रधिसूचना का॰ मां , 802 तारीख 19-2-86 हारों के उन्योग के जस प्रविसूचना से संलग्न प्रनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उन्योग के प्रधिकार को पाइप लाइनों की विछाने के लिए प्रजित करने का अपना प्राथय योजित कर दिया था;

धीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उनत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोट दे दी है;

भीर भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के के पत्रवात् इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उनयोग का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है;

श्रवः अतः जनत स्रिधित्यम की धारा 6 की जपधारा (1) द्वारा प्रति काश्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा चौषित करती हैं कि इस स्रिध्यूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिट उक्त भूमियों में उपयोग का स्रिध्यार पाइपलाइन विकास के लिए एतव्द्वारा स्रिति किया जाता है;

प्रोर प्रामे उन घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस पक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि जकत भूमियों में उन्योग का घाषकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय नीस प्राधिकारण लिंक में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीया को निहित होगा।

भनुपूरक वाद भनुसूची एजव्बीवजेव गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन ् यद	तहसीस	परगना	प्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफ ल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जानीम	जालीन	जासीन	मिहौना	395	0-04	
		{	म ० O -	14016	175/84	जो पी]

S.O. 2679.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 802 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and

Minerels Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule) H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Acre in acres	
1	2	3	4	. 5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Miha- una	395	0 04	— `

[No. O-14016/175/84-G.P.]

कब्झा ० १ ६८० : - – यतः पेट्रोलियम भीर खनित पादपलाङ्ग (मूर्मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन,) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधार। (1) के प्रश्रीन भारत सरकार के पेट्री-नियम मंत्रालय की प्रश्रिसचना का० था। मं १०९ दिनांक 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस ग्रधिमुखना से संयान ग्रनुसुको में विनिधिक्ट भूमियों ये जपयोग के अधिकार को पाइपनाइनों को विखाने के लिए धर्मित करने का अपना धाय घोषित कर दिया था।

भीर यमः सक्षम प्राधिकारी ने जनत ग्राधिनियमं की भाग ६ की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

श्रीर धार्गे यतः केन्द्रीय मरकार ने उत्रप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्यात् इस अधिसूचना से मंलग्न धनुगुर्चः मे विनिधिन्छ भृशियों मे चपयोग का अधिकार अजिल करने का विनिश्चय किया है।

ग्रज, ग्रत: चक्त प्रधिनिधम की धार: ६ की उपधार: (।) धारा प्रदल शक्ति का अयोग करते हुए केरदीय गरकार एमन्द्रारा घोषिन कस्ती है कि इस प्रधिस्चना में संलग्ग अनुसूची में विनिष्टित उपत एपियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनक्ट्रारा र्द्धाजित किया जाला है ।

मीर माने उस धारा की उपधारा (4) हार। प्रवत्त सस्टियी ना प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देशी है। कि उनस भूभियों में जपयोग का अधिकार केल्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय तैस प्राधिकरण लि॰ में सभी साधाओं से मक्स अप में घोषणा ये उकार के की स तारीचा को निहित होगा।

धनुपूरक आ**र धनुगूर्व**ः

एवं पीं अंत मैस्याह्म साहन प्रोजेस्ट

जनभव	भ द्दम ेल	प्रश्ता	ग्राम	गःटा	क्षेत्रफल	विवरण
***************************************	·	·	·	푸 o 	em - specifica	
	2	.3	1 _.	5	6	
जासीन	क ेच	कॉच	निनरा- पम्भराम	-	0~-38	;
			fito (}	elarula	

[स॰ ऄ-14016/310/84-जापत]

S.O. 2680.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 809 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (6) of 1963. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schodule) H.B.J. Gas Pipe line Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Titra Paras- ram	58	0 -38	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

INo. O-14016/310/84-G.P.]

का • भा • 3681 - - यन: पेट्रोलियम की र खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के समिकार का धर्जन), भिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की भारा 3 की उपश्रासा (1) के अधीन भारत सरकार के गेडोलिक्स मंत्रालय की श्रीधमुचना का०मा० गं० 794∤दिन∣क 19-2-86 द्वारा केखीय मरकार ने उस अधिसन्तना से लंखन अनम् की में विनिविध्य भृषियों के उपयोग के मधिकार का पाइप लाइनों को बिखाने के लिए मंजित करने का भारता सरणार दोधित कर दिना था।

बार यम. सक्षम प्राधिकार, में उत्तम शक्षिमियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को विपोर्ट वे वी है।

लीर आसे मण केर्न्नाम सरकार ने स्थल, रिपॉर्ट पर विकास करने के परनात् इत अधिगुचना से बंलगा शतुभुको में विकिद्ध भूभियों में स्थमान का अधिकार प्रतित करने का निक्षिण्य किया है।

श्रम, श्रत, एवन प्रसितियम की घारा ८ का उपधार। (1) द्वारा प्रवत गरिन को प्रभाग काने हुए केन्द्रीय भरकार एतद्द्वारा भाषित है कि इन जिल्लाम से निर्माणन अनुभूता में विनिध्य इनके भूमियों से उपयोग का श्रीवकार पाद्मलाइन विछान के प्रभाजन के निर्माणन सुविधार श्रीवकार पाद्मलाइन विछान के प्रभाजन के निर्माणन सुविधार श्रीविधार का श्रीवकार पाद्मलाइन विछान के प्रभाजन के निर्माणन सुविधार श्रीविधार वास्त्रीय जाता है।

श्रीर श्रामे उस धार का उपधारा (4) द्वारा प्रदेश शिक्तवों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है। कि उपस भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय रास्कार में निहित होते के अजाम भारतीय गैस पाकितरण लि. में सभी माधामां से मुक्त कप में भोषणा के प्रक्तामान की इस सरीय की रितृत होगां।

अनुपूरक बाद धनुमुखी एच० बीठगेठ गेस पाइप साइन प्रीजेक्ट

		-				
अनगर	नहसंस्य	प्रभाषा	₹ंत्र स	ે પોટ(₩ क्परा	(ध्रह्म च का
•	•			₹.		
					-	
ঝালান	ৰ্দ) ব	# /[-1	ब्रुंडा-	t)-	- 03	
			में छन			
			[मं. (D-1401	6/310/84	- - ने.पः]

S.O. 2681.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 794 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

	·					
District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No		Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Faladn	Konsh	Konch	Mhora Bora	3	υ ს3	
	·					

[No. O-14016/32/84-G.P.]

का अ १० ४ ३३ थे १ -- स्वाः पेट्रोलियम ग्रीर खिनिक पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की पारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम गंत्रालय की अधिसूजना का अर्थन मंग्र 800 तारीख 19-2-86 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूजना से संलग्न अनुसूची में जिनिहिष्ट पूर्वियों के अयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को खिछाने के निर्धार्थिक मार्गन का अपना आपना धोषिन कर दिया था।

श्रीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

भीर आंगे यतः केन्द्रीय भरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्चय किया है।

अब, अनः उनत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेश प्रान्त का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतव्दारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संतरन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्दारा अजित किया जाता है।

मार आभे उस भारा का उपधारा (4) द्वारा प्रयत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्राय भरकार निर्देश देती ह कि उनत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्राय सरकार में निहित होने के दाजाय भारतीय भैस प्राधिकरण नि॰ में सभी साधिओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीका को निहित होगा।

अमृपूरभ काद अनुसूची

	∨,भ०वी ब	भें० गेस	पाइप लाइन	्रप्राजेक्ट		
- अनप द	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा	- श्रेष्ट्रफल	 विवरण
				₩o		
1	2	3	4	5	6	7
झांद्री	मोठ	मोठ	इम्सिया	121	0-02	
			स्टट			

[tio-O-14016/68/84-जीपी]

5.0. 2062.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 800 dated 19-2-86 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intenion to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conterred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central's Covernment hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) G B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Imalia Estate	121	0 02	

[No. O-14016/68/84-G.P.]

का० आ ० 2 68 : ---- यतः पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम भंतालय की अधिसूचना का०आ० सं० 803 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों भे उपयोग के अधिकार भी पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आक्ष्य घोषित कर दिया था।

भीर यतः प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

भीर आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिवोर्ट पर विचार करने के परवात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनिथम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलवृद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अमुसूची में बिनिविष्ट उक्त भृमियों में जपयोग का अधिकार पाइपलाइन विद्याने के प्रयोजन के लिए एतइहारा अर्जित किया जाता है।

भौर आगे उस घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है। कि उक्त मूमियों में खपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय कारतीश भैस प्राधिकरण लि० में सभी कांधामों से मुक्त रूप में वोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाव अनुसूची एप०बी०जे० रीस पाइप लाइस प्रोजेक्ट

		प्रवाद्याद्याद्यात्रम् साह्य साह्य प्राज्यक्ट					
जनपद	तहसील	परगन <i>ा</i>	प्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
जालौन	कोंच	कोंच	खकशीस	709	0-01	-	
				892	0-01		
				925	0-02		
				239	0-01		
				920	0-12		

[सं O-14016/177/84-अीपी]

S.O. 2683.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 803 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline:

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gus Piec Line Project

District	Tahsil	Pragana	Village No.	Plot No.	Area in Acers	Re- mark
- i	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Koach	Khik-	709	0-01	
			\$c3S	892	0-01	
				9.25	0-02	
				2.19	0-01	
				920	0-12	

[No. O-14016/177/84-G.P.]

का०आ० 2684: ---यतः पेट्रोलियम ग्रीर खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेदोलियस मंद्रालय की अधिसुबना का० गा० मं० 812 तारीख 19-2-86 बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविध्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइच लाइनो को विछाने के लिए अभित करने का अपना अस्य ओलिए कर दिया था।

भीर मतः सक्षम प्राधिकारी ने उनन अधिनियम की धारा 6 की चनवादा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ड दे दी है।

भीर अर्थे यतः भेरवीय भरकार ने उन्त रिपोर्ट पर विवार करने के परवात इस अधिमुचना ने संलक्ष अनुपूर्ण में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का जितिश्चप किया है।

अज, अन उना अधिनियम को धारा 6 की उनधारा (1) द्वारा प्रवत्त गनित का प्रयोग करते हुए केन्द्रोप सरकार एतयुवारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुपूची में विनिर्दिण्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइवलाइन विकान के अयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया गाता है।

श्रीर आगे उस धारा की उपजान (4) ग्रारा प्रवत गक्तियों का प्रमोग करते हुए फैब्दीय गरकार निर्देश देती है। कि उक्त भमियों में जपयोग का अधिकार फेन्द्रीय सरकार में निहित्त होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधामों से युक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिन होगा।

अनुपूरक शाद अनुसूची एव०वी०जे० गैस पाइप लाइनं प्रोजेन्ट

	'					
म नपद	तह्मोल	प रचना	ग्राम	गाटा स०	 क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	<u>-</u> 4	5	6	7
भार्तीत	₹(लीन	गली।	ब णावनी किंग्	~ - · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	1-02	
						

[स॰ ()-1 to 16/410/84-जीपी।

S.O. 2684.—Whereas by nonfication of the Government of India in the Ministry of Petrolean. S.O. 812 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petrolean and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1902 (50 of 1962), no Central Covernment declared its ministron to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sco-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land, specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by tubsection (1) of the Section 6 of the raid Act, the Control Government bereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to the notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of pager conferred by sub-se tion (4) of that section, the Central Government disjects that the right of user in the said lands shall instead of vecting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India I td. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village		Area in acers	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Bagha- wali Divara	23	102	

[No. O-14016/410/84-G.P.]

का. जा. 2865.—यतः पेढ़ोलियम और जितिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेंट्रोलियम मंत्रालय की ग्रिधिसूचना सं. का. धा. 795 तारीख 19-2-26 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संख्यान अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियी के उपयोग के ग्रिधिकार को पाइप लाइनों को विद्यान के लिए अजित करने का अपना ग्रामय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रीक्षित्रम की धारा 6 की की उपद्यारा (1) के श्रयीन सरकार को रिवार्ट दें दी है।

और धार्गे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात इस ध्रश्चिम्चना से संगम ध्रमुम्नी में विनिर्दिष्ट श्रमियों में उपयोग का प्रक्षिकार ध्राजत करने का विनिश्चय किया है।

श्रव, श्रातः अन्तर श्रीधित्यम की धारा 6 की उपधारा (1) होना प्रदत्तं शनित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्वाना घं। धित है कि इस श्रीधमूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिधित्व उपन क्षियों में उपयोग का श्रीधनार पाइनलाइन बिछाने के प्रयोजन के सिए एतव्द्वारा श्रीजन किया जाता है।

और प्रामे उस धारा की जिल्लामा (व) आरा प्रथम कि विशेष का एसेस कार कुछ केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उत्तर श्रीममें का शिकार के में स्वार सरकार में मिदिय होने के उत्तर आर्थन में, अधिकारन कि, में सभी बाधाओं के मुस्त जब के लेगान के अवस्थान की कर सामित होगा।

अनुपुरक बाद अनुसूची

एच, बी. जी, गैस पाइप लाइन श्रीजेंक्ट

ग ल्य ३	तह्मील	प्रम्मा	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	बिब रण
1	2	3	4	5	G	7
चली 	श्रीमी	भार्मा	: टगरवाहा	932	0-12	
				949	0-03	
				1148	υ 1 0	
				1461	0-04	
			[स. O−1	4016/3	7/84-जी	 . पी.]

findia in the Ministry of Petroleum. S.O. 795 dated 19-2-86 model sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Ministry Sipplifines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of loying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And turther, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said fands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from engumbrances.

Supple neatry C1s. (Schodule)
H B J. G1s Pipe Line Project

Olat trot	Tehsif		Vill2g+	Plot No.	Ar acr		R emark
1	?	3	4	5		6	7
Linsi	Jarnai	Jh (nsi	Dangar waha	932 949 11 18 1461	0 0	12 03 10 04	

[No. O-14016/37/84-GP]

सा. था. 2686.—पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपसाइन (भूमि में उनयोग के श्रिशितर का शर्जन) प्रशिनियम 1962 (1962 का 50) की श्राश 3 की उनवारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की श्रिश्चित्तम सं. का. था. 1297 तारीख 13-3-86 द्वारा के स्थीव गरकार ने उनत व्यधिनुचना में मंत्राल धनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उनयोग के श्रिशितर का पाइन गाइनों की विद्यान के लिए प्रजित करने का श्राभा धाशय पांवित कर दिया था।

र्नार पर चत्र चत्र चार्षा कारी है उस्त आधिनिश्य की आधा छ ही। আধান (1) के अधीन सरकार को स्पिटि वे दी है। भीर भ्रांगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उन्त रिपोर्ट पर विवार करने के पश्चात् इस धक्षिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का ग्राधकार भ्राजित करने का विनिष्णय किया है;

भय, भ्रतः उक्त ग्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) भ्रारा प्रदत्त शिक्त का प्रयोग करने भ्रुए केन्द्रीय सरकोर एतद्ग्रारा घोषित करतो है कि इस भ्रिक्त्यमा में संलग्न अनुसूची में विनिधित्व उपन भृत्यों में उपयोग का श्रिक्तार पाइपलाइन बिश्वाने के प्रयोजन के लिए एतद्ग्राग श्राजन किया जाता है;

भीर, धारों, उस धारा की, उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि उक्त शूमियों में उपयोग का द्यधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होंगे के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी काधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

ग्रनुपूरक याथ श्रनुसूची

एच, बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेश्ट

जनपर्व	सहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	वि वर् ण
1	2	3	4	5	6	7
जास∖म	जासीन	काल)न	एकंत	525	0.01	
			(ਸ . O	-14016/1	B G/S 4-3	r. 90. l

S.O. 2686.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1297 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Solv dul.)

H.B.J. Gos Pip Ling Project

		Par- gana			Ana in	R-mark
1	2	3	4	ج -	6	7
Jalaun	Jalaun	Jilaua	Agon	432	0,01	

[No. O-14016/186/34-GP]

का. का. 2687.— यतः पेट्रोकियम और खानेश पाष्ट्रपत्तिम (सूमि में उपयोग के श्रीक्रकार का ध्रजैंग) अिंदिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपयारा (1) के ध्रशीन भारत सरकार के पेट्रोलियम

मंझालय की घिष्मसूचमा का. आ. सं. 798 तारीय 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस घिषासूचना में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के श्रीधकार को पाइव लाइनों को शिष्ठाने के लिए श्रीजत करने का श्रपना आगय गीवित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उदत प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन रास्कार की रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उनत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चाल् इस ग्राटिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भृमियों में उपयोग का अधिकार अनित करने का विनिम्ख्य किया है:

स्वतं अतः उत्त अभिनियमं तो आगं 6 को उत्त्यारा (1) आरा प्रदत्त पंक्ति का प्रयोग करने दुए केन्द्रीय सरकार एतन्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संक्ष्य भृतूष्यी में विनिधिष्ट उत्त धूमियों में उपयोग का अधिकार पाअपलाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है:

और ग्रामें उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिलतों का प्रयोग करन हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निश्चित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी नाधाओं से मुक्त इप में भोषणा के प्रकाशन की इस तारीच को निहित होगा।

सनुपूरक बाद अनुसूची एस. बी. जे गैंस पाइय लाइन प्रोक्रोकन

जनपव		तहसील	पर्गना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1		2	3	4	5	6	7
	1	झार्सा	भांगी	रानसा	1 2 3	0-20	
					150	0-22	
					155	0-11	
					684	0-29	
					124	0-02	
					379	0-00	
					522	0-62	

[स. O-14016/66/84-जी पी]

S.O. 2667.—Whereas byy notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 798 dated 19-2-85 under sub-acction (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1902 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Connetent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said teport, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in overcise of power contened by sub-section (4) of that restion, the Central Government directs that the right of user in the exid lands shall instead of vesting in Central Government vests on this delegate of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Sappled whom the Call (school). H.B.J. Gas (ip. 1990 First ()

Di:t- rist	[ני גלני]	P gan	e Villeg	Phil No.	Astronia 1902	R. i. rl.
1	2	3	-4	5	G G	7
Jhansi	Jhan,i	Jhaasi	R 'ksha	123 130	0 02	
				155 684	0 11	
				134 379	0 02	
				572	0 67	

[No. O-I-1016/66/84-GP]

का. 2688. --- परः पेट्रोनियम शीर खिनिन पाहरते। इन (भूषि में उत्तोग के अधिकार का शर्भन, जिन्नित्म 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम जिल्ला की अधिमूचना का. आ. स. 319 तारी आ. 19-2-86 हारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुमूची ने विनिर्देश्य भूमियों के उपमोग के अधिकार की पाध्य लाहनों की विद्यान के पिन् भणित करने का अपना आस्त्र घोषित कर दिया था:

शौर वतः सक्रम प्राधिकारी ने उक्षन प्रधितियम को बारा ८ की। उपकारा (1) के अधीन गरकार को स्पिटि दे दी है:

श्रीर आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उका स्पिट पर **विया**र करने के पश्चात् इस अधिसूजना से संतरस अनुसूची में विनिदिन्द भूमियों में उत्योग का अधिकार अजित करने का चितिष्यय किया है:

— अस्त जन्म जन्म अधिताम की धारा ६ की उनधारा (1) जारा प्रक्षत पालिन का प्रयोग करते तुए केन्द्रीय सरकार एनव्यास मोपित करकी है कि इस अधिमूचना में संतरा अनुमुखी में निनिद्धित उनन धृमियों में उपयोग का अधिकार पाइम्लाइन विद्यान के प्रयोगन के निए एनव्द्रारा अधित किया जाता है;

प्रौर आगे उस धारा है। उपप्रारा (4) द्वारा प्रदन्त मिभित्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मन्कार निर्देश देती है कि उत्तर भूनियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निद्धित होते के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं ने मुक्त रूप में भंगिया के प्रकारण की दम तारीख को निह्नित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूत्री एम जी जे भैग पाइपशाइन प्रोशेयट

সন্ধর্ম	नाइगीग	परगना	गाम	गाटा मं	 क्षेत्रफल	विच <i>र</i> ण
1	2	.3	4	5	6	7
	स ा ची	अभिर	युतासती			
			कला	2566	0-04	
				2617	()~- t) <u>'</u> 2	
				2613	0- 50	
				2510	0-07	
				2598	0-11	

[मं O--14016/96/84-जी पी]

2.O. 2688.—Whereas by nonlification of the Government of the in the Ministry of Petroleum, S.D. 819 dated 19-2-86 most indissection (1) of Section 3 of the Petroleum and Manerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 196. (50 of 1962), the Central Government declared its interior to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipiline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Cis: (Schedule)
H B J. Gir Pip: Line Projet

Remerk			Plat No.	Villag	Pirgin?	Tehsil	Dir-
7	6		5	4	3	7	1
	0.4	0	2566	 Pนูบ <u>เ</u> -	Jhonei	Janai	
	02	()	7617	ıv≘li			
	50	0	2618	\mathbf{K} la			
	07	0	2510				
	11	0	2598				

[No. O-14016/96/84-GP]

का. अ. 3689.— यतः पेट्रोलियम श्रीरखितज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपयोग (1) की अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंद्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 799 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीत सरकार ने उस अधिसूचना में संचय्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप पाइनों के लिए अजित करने का अपना आण्य घोषिय कर दिया था;

श्रीर यतः सञ्जय प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा ७ की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को स्पिटिंगे वीहै;

श्रीर आने यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चान् इस अधियूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अभित करने का निनिष्णय किया है;

्राव, जा क्षण अधिनयम की धारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रवस्त कवित का प्राप्ता करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा घोषिस करती है कि इस अधिनुवना में संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट उपन भूमियों में उप-शोग का अधिकार पाउपयादन विष्ठाने के निष्ण एतद्वारा अजित किया जाता है,

श्रीर आगे उस झारा की उपधारा (४) हारा प्रयत्न णिक्त्यों का प्रश्रीम करते हुए केन्द्रीय सरधार निर्वेश देशी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बणाय भारतीय गैम प्राश्चिकरण लि में सभी बाधाप्रों में मुक्त रूप में धौषणा के प्रकासन की दूस सारीख की निहित हं.गा।

अनुपूरक याव अनुसूची एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	त	हसील	परगनः	प्राप	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	3	4	5	6	7
झांसी		झांसी	झांसी	राजापुर	484	0-19	

[सं. 0 -14016/67/84-जो पी]

S.O. 2689.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 799 dated 86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pip Line Project

Dis-	Tehsil	Pargan	a Village		Ares in R mark
trict				No	acres
1	2	3	4	5	6 7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Rajapur	484	0 19
31100.00		J.1.	#¢#J#		

[No. O-14016/67/84-GP]

का. आ. 2690.—यतः पेट्रोलियम ग्रीर खिनज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंजालय की अधिसूचना का. आ. सं. 793 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विलान के लिए अर्जित करने का अपना आध्य घोषित कर दिया था;

ग्रीर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

ग्रौर आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के वश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है;

अनं, अतः उन्त अधिनियम की बारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करतो है कि इस अधिधूदना में संजल अनुभूची में विनिद्धि उन्त भूमियों में उप-योग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है;

श्रीर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती. है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची एवं बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनगद	तहसील परगन	ा ग्राम, गाटा सं.	क्षेत्रफेल विवरण
1	2 3	4 5	6 7
Fig.	मोठ मोठ	सिरसा 238	0-02
		327	0-20

[सं. O-14016/5/84-जी पी]

S.O. 2690.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 793 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And further, whereas the Central Government has, after Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

HBJ. Gas Pipa Ling Project

Di:-	Tehtil	Pagana '	Villag Pl	ot Area	in Roman	k
trict			No	o. acro	s	
1	2	3	4	5	6 7	
Jhansi	Moth	Moth 8	Sirsa 23	8 0	02	
			32	7 0	20	

[No. O-14016/5/84-GP]

का. श्रा. 2691—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिधिकार का ग्रर्जन) ग्रिधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रिधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिमूचना का. मा. सं. 813 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस म्रिधिस्चना से संलग्न मनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के म्रिधिकार की पाइप लाइनों को विष्टाने के लिए ग्रिजित करने का ग्रिपना ग्राणय पोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उस्त ग्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के ग्रधीन गरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उनक रिपोर्ट्र पर विचार करने के पश्चात् इस श्रुधिसूचना से संनग्न ग्रनुसूची में विनिर्विष्ट मूमियों में उपयोग का ग्रुप्रिकार अजित करने का यिनिण्चय किया है।

ष्ट्रम, श्रतः उदनः श्रिकित्यम की घारा ६ की जपधारा (1) हारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस श्रिधसूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिधकार पाइपमोइन विष्ठाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा श्रिजत किया जाता है।

और श्रामे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में नभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची एच. बी. जे. गैस पाडप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्य चक दल मं० मं०		विषरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जासीन	जासीन	चांकी	594 118 116	$\begin{bmatrix} 32\\39 \end{bmatrix}$ 0.59	
			[Ħ, C)- 14016/	132/84—जी	• पी]•

S.O. 2691.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 813 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

555 GI|86---6

Supplementry Case (Schedule)

HRI	Ges.	Pin	Line	Project
11.13 J.	UG	T I D	LATIN	FIGURE

Dis- trict	Tehsil	P .rgana	Villag -	Chak		Area in copy.	Repr rķ
1	2	3	4		5	6	7
Jalaun	Jalaun	Je laun	Ch² ki	594	1187) 1169)	0,49	

[No. O-14016//37/81-GP]

का. अा. 2692 .--यतः पैट्रोलियम और खनिज पाष्ट्र लाइन (भूमि में उपयोग क्रिधकार का ग्रुजेंन) ग्रिधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रिधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम संलालय की ग्रिधिसूचना सं. का .हा. 810 सारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रिधिसूचना रो संलग्न क्षमुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के ग्रिधकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए ग्राजित करने का ग्रुपना ग्राशय योपित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की घारा 6 की उप-धारा (1) के ग्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और धार्गे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट्र पर विकार करने के पश्चात् इस ग्रक्षिसूचना से संलग्न कनुसूची में विनिद्धिट भूमियों में उपयोग का किश्वकार किला करने का विनिश्चय किया है।

अस, ग्रातः उक्त ग्राधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा घोषित है कि इस ग्राधिसूचना में संकान ग्रानुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का ग्राधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदृद्वारा ग्राजित किया जाता है।

और भ्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन होने के बजाय भारतीय— गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाद्याओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

ग्रनुपूर**क वाद ग्र**नुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	दोत्रफल ब	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालीन	जालीन	आसीन	रोमई मुस्	तिकल 754	0-08	
<u> </u>					, ,	

[सं. O-14016/313/84-जी०पी०]

S.O. 2692.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 810 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shell instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India 1.td. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

HBJ. Gas Pipe Lin Project

Dist- rict	T'ahail	P.13171	V[i] · g ·	$P^{1} \cap {}^{t} \mathbf{N}$	Aron in non-s	Remark
1	3	3	<i>A</i>	5	6	7
Jalaun	Jaleu-	Jelana	Romai Mult - kjl	•	0.08	

[No. O-14016/313/8/-GP]

कां. श्रा. 2693.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइएलाइन (भूमि में उपयोग में अधिकार का ग्रजंन), मधिनियम 1962, (1962 का 50) की श्वारा 3 की उपयारा (1) के ग्रधीन भारत नरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की श्रधिसूचना सं, का. श्रा. 797 तारीख 19-2-86 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिय भूमियों के उपयोग के ग्रधिकार को पाइप साइनों को विकान के लिए प्रजित करने का ग्रपमा भ्रास्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उदत ग्राधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के ग्राधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और श्रामे यतः केन्द्रीय भरकार ने उक्त रिकेट पर विचार करने के पश्चात् इस श्रीवसूचना से संलग्न छनुसूची में जिनिर्दिण्ट भूमियों में उपयोग का श्रीकार ग्राजित करने का विनिय्जय किया है।

धन, धनः उनत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त णन्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संख्या अनुसूची में विनिविष्ट उनत भून्यों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विकास के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) डारा प्रयत्त गिनतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहल होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि., में मभी बाधाओं से मुक्त रूप में विष्णा के प्रकाशन की इस तारीख की निहल होंगा।

भनुपूरक बाब ध्रममुची

एच.	जी.	जे.	रीय	पाउँग	यादन	प्रोजेक्ट
vq.	0.1	স .	41.00	4139	71124	अ।गपट

जनपद	सहसीन	परगना	 ग्रा म	गाटासं.	 क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	- ऐरा	316	0-03	

[सं. O-14016/3/84-जी पी]

S.O. 2693.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 797 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to accuire the right of, user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

HBJ. Gas Pip. Lin. Project

Dia trict	Tihail	Pagini	Villag		Ar-n in acres	R mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Aira	316	0 02	
- -				[No.	O-14016/3/	84-GP]

कां. छा. 2694---यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीन होता है कि लोकहित में यह ग्रायक्यक है कि गुजरान राज्य में उभराट से हजीरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन, तेल तथा प्राकृतिक गैस ायोग द्वारा विछाई जानी चाहिए!

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विष्णने के प्रयोजन के तिल् एतदपाबड़ अनुसूची में याँगत भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

इतः इत रैंद्रोलियम और खनिअ पाइपलाईक (धूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) इतिनयम, 1962 (1962 का 50) की धारां हु 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्ता सक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सन्कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाषय एतद्-द्वारा धोगित किया है।

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितवत कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने लिए छासेप मक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, हजीग प्रोजेक्ट, प्रहर, मुभावनगर सोमायटी, घोडयोडराख गूरत को इस ग्रिस्तुना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर स्रकेगा।

और ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति जिनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेना कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ध नुसूची

उभराट से हजीरा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिलाः सूरत	सास्लुकाः चोर्थासी
4		

गोव	ब्लॉक न.	हेक्टेथर	ब्रीर	सेंटीय र
भाटगोर	333	0	68	80

[सं. 12016/116/8?-प्रो. जीपी] राकेश कनकर, उप सचिव

S.O. 2694.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from UBHARAT to HAZIRA in Gujarat State pipeline should be Inid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipeline (acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar" 60, Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road. Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heared in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE Pip lin- from Ubharet to Hazine

Stot : Gujarat District : Surat Toluka : Chorasi

Villeg	Block No.	Hactr-r	Ar	Centier
1	2.	3	4	5
Bhatpore	333	0	68	80

[No. 12016/116/83-Prod./GP] RAKESH KACKER, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

कां अां 269.5.— नान्तता प्रतिनियम, 1972 (1972 का 20) के खंड 3 और 5 के उपखंड (1) द्वारा प्रवस प्राणितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रधितियम के खंड 3 उपखंड (3) की क्षारा (क) के अंतर्गत भारतीय वास्सुकला संस्थान द्वारा वास्तुकला परिषद् में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके सदस्यों में से चुने गए निस्मिलिखित पांच वास्युकारों के माम इस सरकारी राजपन्न में क्षिमुचित करती है:—

नाम

- श्री माध्य गणेण देवस्ता, माफेन नीसर्व सेन एंड पोमास्टर प्रोस्पैक्ट नीस्वर एनेट्सी, तासरी मोजन हाउडील्एन रोड फोर्ड, बस्बई 400001
- श्री सानित श्रीनिकण जिली मैसर्स एमक्प्यक किसा एंड कन्यनी 134, नियोगसन मास्टर रोड फार्ट, वस्कि-400023
- नैसम श्री एना सात्रा एम स्थितक एम. के. स्थातिक एउ एंन्सो, क्रिसेंट चैम्बर्स तामरील्ड लेस, फोर्ट, बस्बई-400020
- 4. श्री ध्रम्ण वितायक आंगले, सप्ते बनर्ने, 15, त्रुधान रोड, दला मंदिर के पास, विलेपाल (यू.) अस्बई-400057
- श्री नटनरलाल श्रमृतलाल बड़ेका, फैयरी भेनर, छड़ी गंजिल, 13 गलबे, स्ट्रीट, फीर्ट, बम्बई-400001

तयापि, के श्रीय सरकार ग्रापे यह भी बनाती है कि उन्त श्रिष्टिनियम के खंड 6 जार्यं (1) के अंतर्गत सदस्यों का कार्याकाल 24 जनवरी, 1986 में 23 जनवरी, 1989 तक तीन वर्षों को अपिश्व अपना उनके उत्तराधिकारी बुने जाने तक, भी भी बाद में हो, के लिए होगा।

> [संख्या एक 17-16/82-दी-13/दी.-3 खंड-2/ डा. घी.सी. विश्वात, भंगृत्त शिक्षा सजाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O. 2695.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 and 5 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government hereby notifies in the Offical Gazette the manes of the following five architects elected from among its members by the Indian Institute of Architects to the Council of Architecture to represent the Institute under clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, namely:—

- Shri Mahdav Ganesh Deobhakta, C/o M/c. Sane and Paymaster, Prespect Chambers Annexe, 3rd Floor, Dr. D. N. Road, Fort, Dombay-400001.
- Shri Yatish Shrinivas Kini, M/s. S. M. Kini and Co., 134, Nagindas Master Road, Fort, Bombay-400023.
- Shri Datta Shantaram Malik, M/s. S. K. Malik and Co., Crossent Chambers, Tamarind Lane, Fort, Bombay-400023.
- Shri Arun Vinayak Ogale, Sapre Bung low, 15, Hanuman Road, Near Datha Mandir, Vile Parle (E), Bombay-400057.

 Shri Natwarlal Amratlal Badheka, Fairy Manor, 6th Floor, 13, Gunbow Street, Fort, Bombay-400001.

The Central Government hereby further specifies that the members shall hold office under sub-section (1) of section 6 of the said Act for a term of three years commencing with effect from the 24th January, 1986 and upto 23rd January, 1989 or until their successors have been duly elected, whichever is later.

[No. F. 17-16|82-T. 13|7. 3 (Vol. II)] DR. D. C. BISWAS, Jt. Education Advisor (Tech.)

परिवहत मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोडं)

मई बिल्ली, 11 जुलाई, 1986

काठआठ २६९६—राजभाषा (संघ के मासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के धनुतालन में परितहन मेंत्राक्षय, रेल विभाग (रेलवे बोर्ड), दक्षण-पूर्व रेलवे के मण्डल रेल प्रवन्धक विलासपुर के कार्यालय को, जहाँ के कर्मवारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, प्रधिसुचित करता है।

. [संख्या हिंदी-86/रा. भा. I/12/3]

ए. एन. वांचू, सचिव, रेलवे वोड एवं भारत सरकार में पदेन ग्रयर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 11th July, 1986

S.O. 2696.—In pursuance of Sub-Rule (2) & (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Transport, Department of Railways (Railway Board) hereby notify the Office of the Divisional Rail Manager, Bilaspur of South Eastern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-86|QL-I[12]3]
A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board and Ex-Officio Addl. Secy.

थम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1986

का. मा. 2697.— औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. के प्रशंधतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिश्ट आद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिक्तरण, नं. 1, धनवाद के पंचाट को प्रकाशित करतीं है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th July, 1986

S.O. 2697.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Indus-

trial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 1 of 1984

PARTIES: Employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Employers: Shri A. D. Singh, Dy. C. P. M. (Admn.), BCCL/Koyla Bhavan,

For the Workmen: Shri Brahmdeo Singh Yadav, the concerned workman.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 2nd July, 1986

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012 (235)/83-D. III. A, dated 17th/19th December, 1983, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject-matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

"Whether the action of the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad in not regularising at Hindi Stenographers from November, 1980, Shri Umesh Kumar Singh, Bhatta Mazdoo; and Shri Bhanmadeo Singh Yadav, Miner, Govindpur Colliery is justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

- 2. The dispute has been settled out of Court, A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The Memorandum of Settlement shall form part of the award.
- 3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the I. D. Act.

I. N. SINGH, Presiding Officer [No L-20012/(235)/83-D. III (A)]

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF BOCL & WORKMAN NAMELY SRI BRAHMDEO SINGH YADAV, ADMN. DEPTT., KOYLA BHAYAN REPRESENTED BY BCC STAFF COORDINATION

For Management: Shri A. D. Singh Dy. CPM (Admn.) BCCL/Koyla Bhavan.

Workman: Shri Brahmdeo Singh Yadav.

An Industrial dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad with regard to the regularisation of Shii Brahmdeo Singh Yadav as Jr. Steno (Hindi). The matter having failed was referred to Central Government Tribunal No. I, Dhanbad for adjudication where the same was numbered as ref.

No. 1/84 The terms of reference was ---

"Whether the action of the management of BCCL, Dhanbad in not regularising as Hindi Stenographer from November, 1980, Sri Umesh Kr. Singh, Bhatta Mazdoor & Shri Brahmdeo Singh Yadav, Miner, Govindpur Colliery is justified? Ir not, to what relief are these workmen entitled?"

While the aforesaid reference case was pending for adjudication the workman approached for its amicably settlement. The matter was discussed on several occasions and ultimately it was agreed to settle the dispute amicably on the following terms:

TERMS OF SETTLEMENT:

- That out of the two employees namely S/Shri Umesh kumar Singh, Bhatta Mazdoor has since been died therefore, the question of his regularisation in any cadre doesn't arise.
- 2. That it has agreed that Sri Brahmdeo Singh Yadav earlier posted in Govindpur Colliery as Miner and now working in Admn, Deptt, at Koyla Bhavan will be regularised as Typist in the scale of Grade-II i.e. Rs. 678-30-918-35-1198/- immediately after Signing of this settlement without and difference of wages.
- That the concerned workman will not claim any dues or arrears whatsoever, prior to the date of the present settlement.
- That the party agreed to jointly file copy of the settlement before the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad for passing the award in terms of the settlement,
- The settlement shall be registered under Rule 58(iv) of I.D. (Central) Rule, 1947.

Brahmdeo Singh Yadav, 14-6-1986 Workman

Sd|- Illegible

Management representative

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का. था. 2698.— श्रीशीमित विवाद स्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के धनुसरण में, केन्द्रीय लरकार, गोविन्दगुर क्षेत्र नं. III, भारस कोकिंग कोल लि. के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों ने दीव धनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रभामित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 10-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O. 2698.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Limited, in Govindpur Area No. III and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 74 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES:

Employers in relation to the management of M/s.

Bharat Coking Coal Limited in Govindpur Area
No. III and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workman—Shri D. Mukhorjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers-Shri B. Joshi, Advocate.

STATE: Bihar.

INDUSTRY ; Coal.

Dhanbad, Dated the 30th June, 1985

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the 1.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012 (56)/85-D.III(A), dated the 29th May, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Collicry Kamgar Union for regularisation of S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishta in clerical Special Grade in the Govindpur Area of Messrs Bharat Coking Coal Liimted is justified. If so, to what relief are these workmen entitled and from what date?"

The case of the concerned workmen is that both the concerned workmen S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishra were Grade-I clerks working in the Finance department of Govindput Area of M/s. B.C.C.L. Three special grade Clerks of Pinance department/Accounts department retired and in their place the two concerned workmen were working as Special Grade Clerk, S/Shri R. L. Jain and K. S. Gotal special grade clerks had retired from service with called from June, 1983 and November, 1983 respectively. Since their retirement the concerned workmen worked as special grace Clerks continuously and have put in more than 240 days attendance in each calendar year. The concerned workmen represented before the management for their regularisation as special grade Clerk and accordingly the Area Finance Manager initiated a notesheet dated 29-4-84 for their regularisation. The Personnel Manager, however, forward d the notesheet with a recommendation for payment of diffeence of wages to the concerned workmen for working in higher post and it was accepted by the General Manager. The action of the management in not regularising the concerned workmen in the post of Special Grade Clerk was illegal, arbitrary and against the principles of natural itstice and also against the policy decision of the management. A number of workmen have been regularised in the higher post by the management of BCCL if they had worked in the higher post for 240 days and more. S/Shri R. P. Parameter and A. K. Sinch and M. S. Sanda Grade Challege. ser and A. K. Singh were regularised as Special Grade Clerks in the year 1983 although they were junior to many clerks. In the year 1979 the position of S/Shri R. P. Paraser and A. K. Singh and the concerned workman B. N. Jha in the senjority list was 27 and 191 and 105 respectively. Shri A. I. Parmer was also regularised in a Special Grade vide office order dated 22-1-81 although he was in Sl. No. 31 of the Seniority list. The promotional policy and job description will show that the concerned workman were performing the job of Special Grade Clerk. It is not true that Grade-I-Clerks having a special merit are only promoted to special grade and they are promoted to continue in Grade-I job only with high efficiency. The promotional policy of the management, on the other hand, will show that the job description of Clerk Grade-I and Special Grade Clerks are different. are different. As the concerned workmen have been working as a special grade clerk since 1983 against the permanent vacancy and they are senior in their cadre of Finance discipline, they are entitled to be regularised in Special Grade. The union of the workmen raised an industrial dispute before ALC(C), Dhanbad for conciliation. The management filed its comments before the consilation officer to the effect that the concerned workmen were not working as a Special Grade Clerk. The conciliation proceeding ended in failure and thereafter the present reference was sent for adjudication. On the above plea it has been submitted that reference be made in favour of the workmen.

The case of the mangement is that the two concerned workmen are Grade-I Clerks working in the Finance departners and that they have not yet been promoted Special Grade Clerks as per rule of the company, Promotion is managements function and it is done according to the procedure laid down in the promotion policy. A Departmental Promotion Committee constituted to consider the case of all eligible candidates for their promotion and on the recommendation of the names of the candidates in order of merit for promotion by the D.P.C, their promotion is The management has authorised the General effected Manager of different areas to make a stop gap arrangement and carry on the work of higher post by getting arangement whenever vacancies occurs in the higher post. The said higher post is generally to be filled up by promotion only. There is also practice of regularisation of workmen under which in a special circumstances a workman acting in higher post for a considerable period with exceptional merit, senio ity and honesty may be regularised in that post provided there will be no other senior claimant to such post and it is not going to cause several dispute on behalf of This power given to the General Manager have to be sparingly used and cannot be invoked in all case to promote junior persons by way of regularisation on the basis of notesheets depriving claim of the senior workmen from their chances of promotion. Grade-I clerks are supposed to be competent enough to perform all types of duties concerning the departmental. In normal course Grade-I clerk is the higher clerical Grade. Grade-I clerk having a special merit are promoted to a special grade and they are promoted to continue the jobs of Grade-I with high efficiency. The concerned workmen being in Grade-I are performing Grade-I jobs only. They are junior to several workmen of Grade-I clerks working in Finance department performing similar types of jobs. The concerned workman are in no way more competent or meritorious to other clerks of the Finance depariment. The concerned workmen, therefore, cannot be promoted to special grade superseding the claim of senior Grade-I clerks working in the same office and performing similar types of jobs. When any clerk of Grade-I is promoted to a special Grade he would be able to command respect of other clerks of Grade-I and should be able to exercise control over the clerks junior to him, and to supervise their duties. As the concerned workmen are junior to many Grade-I clerk who are much more competent than the concerned wrokmen, it will be different for the concerned workman to exercise control over their seniors. The concerned workmen have not worked as a Special Grade Clerk against permanent vacancy and that they have not put 240 days of attendance in a calendar year in the capacity of Special Grade Clerk. S/Shri R. L. Jain and K. S. Gorai have retired from their service and they were Special Grade Clerks at the time of their retirement. Prior to their promotion they were in Grade-I and were performing the same and similar types of jobs. Their promotion from clerical Grade-I to Special Grade did not change the contents of work but increased the efficiency and they exercise the power, control and supervision over their juniors. Area Finance Manager wrongly recommended on the basis misrepresentation of facts by the concerned workmen as well as due to lack of his understanding about the fixation of the concerned grades and promotion for up-gradation of workmen. The management did not accept his recommendation. The order for payment of difference of wages to the concerned workman was incorrect and was sanctioned on wrong notings of the Area Finance Manager. A workman acting in higher post can claim for his promotion for that post by way of regularisation on the basis of officiating in that post unless it is established that there is no other candidates to claims for the post. The claims of the workmen is unreasonable illegal and without any basis and as such it cannot be allowed.

The schedule of reference refers to the case of regularisation of S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishra. Shri B. D. Mishra did not appear and depose in the case. No evidence was adduced on behalf of B. D. Mishra. It was submitted by Shri D. Mukherjee representing the workmen that Shri B. D. Mishra was allotted some other job of Grade-I and he is not working in Special Grade and as such his case is not being pressed. It is further submitted by Shri D. Mukherjee that he would only proceed with the case of Shri B. N. Jha.

The point for determination in this case is whether Shri B. N. Iha can be regularised in Clerical Special Grade in Govindpur area of M/s. B.C.C. Ltd.

The workmen have examined three witnesses and the management have also examined three witnesses in proof of their respective case. The documents of the workmen have been narked Ext. W-1 to W-5 and the documents of the management have been marked Ext. M-1 to M-6.

Some facts are admitted. The concerned workman Shri B. N. Jha was working in Clerical Grade-I from 1980. S/Shri R. L. Jain, K. S. Gorai Special Grade Clerk retired from service with effect from June, 1983 and November, 1983 respectively and no fresh appointment was made in their place. The case of the workman is that the concerned workman was working as a Special Grade Clerk after the retirement of R. L. Jain and K. S. Gorai since June, 1983 and are continuing to work as Special Grade Clerk completing more than 240 days of atendance each year. The management on the other hand, contend that the concerned workman did not work as a special Grade Clerk and was working in Clerical Grade-1. WW-1 Nawal Kishore is working as an Accountant in Clerical Grade-I in the Finance department in Govin-Jpur area office of M/s. B.C.C. Ltd. He has stated that in 1983 Shri R. L. Jain and K. S. Gorai, Special Grade Clerk retired and after their retirement there was no post-ing of Special Clerical Grade. He has stated that the concerned workman Shri B| N, Jha used to supervise the work of 4 to 5 Grade-I Clerks working in the Finance department. In the cross-examination he has stated that the con-cerned workman used to give him the journal vouchers which he used to enter in the ledger book WW-2 Bhuwal Singh Yadav is also working as an Accounts Assistant. Ho has stated that the concerned workman works in the Accounts Section and is full incharge of store accounting. He has stated that the concerned workman looks after the work of 4 of the clerks who work along with him. He has stated that Shr B. N. Jha was working as Specical Grade Clerk, He has also stated about the work being done by the concerned workmen as a Special Grade Clerk, WW-3 is the concerned workman Shri B. N. Jha himself. He has stated that from 1980 he was in Clerical Grade-1 and from 1933 he is working in Clerical Special Grade-I against the permanent vacancy in place of Shri R. L. Jain and K. S. Gorai who were working as special Grade Clerk after their retirement in 1983. He has stated that he was dealing with inter unit reconciliation with other area headquarters and Calcutta office since 1983. He has stated that there are four clerks attached with him whose work he checks. He also does the bank reconciliation, posting of bill's, deals with purchase procedure and final accounting. He also makes entries of intricate case in the stores ledger. He supervises and controls the work of the 4 clerks attached with him. He is working continuously as a special grade Clerk since 1983 and had more than 240 days attendance in a year. He has further stated that BCCL has cadre scheme in which the description of clerical Grade-I and clerical special grade The job description of Clerical Grade-I special are given. grade are different. He has stated that he does the work which is given in the job description of clerical special grade in cadre scheme. He has further stated that the Area Finance Manager ic his immediate superior who had initiated a note dated 22-2-84 which has been marked as Ext. M-1 in this case. The said note in Ext. M-1 was approved by the General Manager Shri S. B. Roy. He has stated that the Personnel Manager Shri R. Mohan had endorsed it to the Finance Manager for payment of difference wages to him but the difference of wages as ordered vide Ext. M-2 was not paid to him. The photo copy of the notesheet was given to him by the Finance Maanger, MW-1 was working as Finance Officer and the concerned workman work under him from January, 1983 to December, 1985 and at that time the concerned workman was dealing with the stores and purposes accounts. There were staff working under MW-1 including the concerned workman and they had all been allotted different work and Shri B. N. Jha used to coordinate their work. This evidence shows that Shri B. N. Jha was doing some different work than the other staff and this work of coordination appear to be the job of superior order. He has also stated that the concerned workman used to see as to why the work of any member

staff was lagging bohind and on the instructions from the Finance Officer the concerned workman used to complete the work which was lagging behind with any staff. In his cross-examination he has stated that he does not know the job of work of clerical special Grade and that he did not always consider the grade of his staff while allotting the duties to them. He came to learn from the concerned workman and other person that the General Manager had approved the recommendation of the Area Finance Officer regarding the regularisation of the concerned workman for the post of Special Grade Clork. He had not himself seen the order of the General Manager. MW-2 Shri R. N. Prasad is attached to the Personnel Manager, Govindpur Area and deals with the file of the case. He has stated about the note of the Pesonnel Manager which was approved by the General Manager. He has stated that some clerks had objected and represented before the new Personnel Manager about the recommendation of regularisation of the concerned workman as Special Grade Clerk and thereafter the file went to the General Manager who kept the matter in abeyance till further order and thereafter no orde was passed on the said file MW-3 Shri S. C. Gour is working as a Personnel Manager. He has stated that the approval of the General Manager in Ext. M-1 was kept in abeyance for consideration of the representation of the staff and the union and the matter has not yet been decided. In his cross-examination MW-3 has stated that no individual worker had represented in writing about the so-called protest regarding the regulaisation of the concerned wokman in the special grade. He had not enquired whether the note sheet initiated by the Finance Manager was correct or false. He had to admit that if a workman of lower designation works in the higher designation, he gets the wages of the higher grade. He has also stated that the General Manager has the authority to pass order for regularisation or payment of the difference of wages. Thus it is almost admitted that the case of the concerned workman was recommended for giving him clerical Special Grade.

Ext. W-1 is dated 22-2-84. WW-3 has stated that the notesheet Ext. M-1 dated 22-2-84 was initiated by the Area Finance Manager Shri S. N. Pathak Learing his signature. It will appear from this notesheet that there were representations from the concerned workman and Shri B. D. Mishra for their regularisation in Special Grade. Shii Pathak noted that the nature of work being performed by the concerned workman entitles him to the claim as he has been dealing with intricate jobs of double entry accounting and banking and other jobs involved special responsibilities. He has further recommended that in order to boost up merale of the staff the claims made for promotion to special grade may be allowed as has been done in a few case in 1983, Ext. M-2 is a note of the Area of the Area Finance Manager Govindput Area dated 27-4-84. This note was made on receipt of reminder from the concerned workman for his placement in special Grade as per the nature of job being performed by him The Finance Manager has noted that the claim of the concerned staff is genuine and deserving consideration and he is performing the job of highly skill nature with trust and sense of responsibility independently i.e. Shri Jha is checking and scrutinising the bills and is fully conversant with purchase procedure, making proper entries in stores ledger and capable of dealing with intricate cases of stores final accounts and accounts reconciliation inter area and headquarters. He is also conversant with follow up action putting drafts or correspondence etc. He has stated that as 3 vacancies in the Finance Department has occurred due to the retirement of three special Grade Clerk a notesheet had previously been moved on 22-2-1984 (which is He recommended that the case of the concerned workman may be considered for proper placement in Special Grade. Below the said note is the note in which payment of difference of wages for working against a higher grade till some other suitable arrangement is done was recommended for G.M's approval and the G.M. approved the same on 7-5-84 Another photo copy of this potshept has been filed by the management and the same is marked as Ext. M-1. The only difference in Ext. M-1 is there is a note written "This may be kept in abeyance for further orders." There is no such note in photo copy of the same notesheet Ext. W-2. It appears therefore that this note in

red ink was noted sometime after the note Ext. W-2 was handed over by the Finance Manager to the concerned workman. In any case this notesheet show that the concerned workman had performed the jobb of Special Grade Clerk and for this reason a recommendation was made atleast for the payment of difference of wages between the clerical Grade-I and Special Grade Clerk. Thus from the very between the clerical document of the management it is clear that the concerned workman was working as a Special Grade Clerk. None of the management witnesses were able to clearly deny that the concerned workman was not performing the job of Special Grade Cick. The workmen had filed a petition asking for the copy of promotion policy for ministerial cadies in ECCL but the management did not produce the same and did not give any explanation as to why the document which ought to be in their possession have not been produced in this case. It is said that the promotion policy gives the job description of the various clerical jobs includ-ing clerical Grade I and Special Grade Clerk. It has been submitted on behalf of the concerned workman that as the job being performed by the concerned workman was the job of Special Grade Clerk as has come in evidence, the management did not produce the said promotion policy as that would have gone against the case of the management. The submission made on behalf of the workmen appears to be correct and it was for this reason the management witness were evading to specify the job performance of Clerical Grade I or special Grade Clerk. From all the evidence which has been adduced in this case, there is no room for doubt that the concerned workman was performing job, of Special Grade Clerk since the retirement of Shri R. L. Jain and S. K. Gorai in 1983.

It has been submitted on behalf of the workmen that in case of regularisation the seniority of a workman does not count. It is only to be seen whether the workman was working in the higher grade against the permanent post for a sufficiently long time and thereafter he may be regularised. It is further submitted that the case of the concerned workman is not for promotion but the case of his regulari-the job of Special Grade Clerk since 1983 when the permasation in the clerical special grade as he was performing nent incumbent on the post had retired. Some examples have been shown to establish that in the past workmen being junior have been regularised in the higher job being performed by him although there were senior clerks in the WW-1 has stated the Shri A. K. Singh is junior to the concerned workman but was regularised in Special Clerical Grade and no D.P.C. was held for regularisation in special grade. WW-3 has stated that Shri A, K, Singh who is junior to him was regularised in clerical Special Grade in December, 1983 without holding any D.P.C. The seniority list Ext. M-2 has been filed by the management. It will appear from the said seniority list, Ext. M-2 that the seniority of the concerned workman Shri B. N. Jha is 104 whereas the seniority of Shri A. K. Singh was 190. MW-3 has stated that he does not know if Shri A. K. Singh who was promoted in December, 1983 was junior to the concerned workman Shri B. N. Jha. Of course the list Ext. M-2 itself shows that the concerned workman was senior to Shri A. K. Singh in the seniority list but Shri A. K. Singh was regularised in Special Grade Clerks whereas many seniors remained in their original grade. MW-3 has stated that he does not know if Shri A. K. Singh and R. P. Paraser were promoted to clorical special grade without holding any D.P.C. Thus he does not know about the fact whereas there is positive evidence adduced on behalf of the workmen that they were promoted in Clerical special grade without holding any D.P.C. The D.P.C. is constituted for consideration of promotion of the legible candidates and regularisation of a workman on the higher post is mater different from promotion and as such it appears that the case regularisation of a workman is not considered by the D.P.C. The evidence in the case establishes that in the case of regularisation in the higher post seniority is not the criteria. The only criteria is whether he is doing job of higher grade for sufficiently longtime and because of the fact that the concerned workman has worked on the higher grade for a sufficiently longtime it was thought prudent that the said workman should be regularised in the higher post. It is for this reason that in the past also when case of regularisa-tion was considered the seniority of the workman was ignored.

From the evidence discussed above it will appear that the concerned workman had performed the job of Special Grade Clerk since 1983 regularly and at one time his case was recommended for regularisation as a Special Grade Clerk, I hold that the case of the concerned workman Shri B. N. Jha is fit for regularisation as a Clerk Special Grade.

It will appear that the management did not actually pass any adverse order against the concerned workman as it appears from the note on Ext. M-1 that the approval in notesheet Ext. M-1 may be kept in abeyance till further order. Admittedly the management has not made any decision on the matter. As the case of the concerned workman was recommended vide Ext. M-2, for giving him clerical Grade-1 and it was further recommended that he should atleast be paid the difference of wages of the higher grade, but as the matter was kept in abeyance since 23-5-84 and the matter has not yet been decided by the management, I think that the concerned workman should be regularised as Special Grade Clerk from 23-5-84.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for regularisation of Shri B. N. Jha in Clerical Special Grade in Govindpur Area of M/s, B.C.C. Ltd. is justified and that Shri B. N. Jha should be regularised as Clerk Special Grade with effect from 23-5-84. Further, since Shri B. D. Mishra was allotted some other job and is not working in clerk Special Grade and has not given his evidence in support of his case, I do not pass any Award for his regularisation as Clerk Special Grade.

This is my Award.

N. SJNHA, Presiding Officer
 [No. L-20012(56)/85-D,III(Λ)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का. मा. 2699. — औद्योगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रनुसरण में, केन्द्रीय भरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की बमंतीमाता कौलियरी के प्रवन्धवाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके धार्मधारों के बीच, प्रनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं. 2 द्यसबाद के पंचाट की प्रकाणित करती है, जो रेन्द्रीय सरकार को 16-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2699.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Basantimata Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference-No. 10 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the 1. D. Act. 1947

PARTIES: Employers in relation to the management of Basantimata Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workman.

APPEARANCES:

On behalf of the workman: Shti D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers: Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE: Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(95)/85-D. UI(A), dated, the 3rd January, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Basantimata Colliery of M/3. Bhara' Coking Coal Ltd., P. O. Mugma, Distt. Dhanbad in denying employment to Kalipada Manjhi, dependent of late Sufal Manjhi who died during the tenure of his service, is justified. If not, to what rehef is Kalipada Manjhi entitled and from which date?"

The union representing the concerned workman appeared in the case and asked for adjournment for filling the W. S. Finally on 19-6-1986 Shri D. Mukherjee representing the union filed a petition praying to pass a 'No dispute' Award in this case on the ground that the issue in reference has been resolved and the dependant of Kalipada Manjhi has been provided employment and as such the union is not interested now to contest the case.

In view of the fact that the dispute has been resolved between the parties and the dependent of Kalipada Manjhi has been given employment, I pass a 'No dispute' Award in this case.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/95/85-D. III A]

का. आ. 2700.—शैद्योगिक वियाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कीर्किंग कील लि. की भीरा कीलियरी के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच प्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विदाद में नेन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट की प्रकाशित करती है, जी केन्द्रीय सरकार की 16-7-1986 की प्राप्त हुआ था।

S.O. 2700.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Aunexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of M/s. Bharat Coking Coar Ltd, and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 42 of 1983

In the matter of industrial dispute under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen: Shri B. N. Sharma Joint General Secretary, Janata Mazdoor Sangh.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE: Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 has referred the following dispute to this tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(434)|82-D.III(A), dated the 5th May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhowra Colliery of Massis. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, Distt. Dhanbad, in dismissing Sri B. K. Sharma, Store Issue Clerk from service with effect from 4th May, 1982 is justifled? If not to what relief is the said workman entitled?"

In this case the parties filed their W. S. They were heared on the preliminary point whether the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper or not. On 15-5-86 it was held that the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper. There after Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary of Janta Mazdoor Sough who had sponsored the industrial dispute filed a petition dated 30-6-86 praying that the case may be disposed off as the workman in the union are not now interested.

In the result as the union is not interested in proceeding with this reference a 'No dispute' award is passed in this case.

I. N. SINHA, Presiding Officer, [No. L-20012(434)|82-D-IU(A)]

का. था. 2701. — श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि. की गजलीढांड कोलियरी के प्रवस्थतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और जनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्मिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाणिस करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2701.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gajlitand Colliery of Ms. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 33 of 1983

In the matter of industrial dispute under Section 10(1) (d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Gazlitand Colliery of Mesars, Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, 555 GI/86-7

APPEARANCES:

On behalf of the workmen: Shri S. Bose, Secretary, RCMS Union.

On behalf of the employers: Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY: Coal

Dated, Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vi.le their Order No. L-20012(365)|82 DIII(A) dated the 30th March|11th April, 1983.

SCHEDULE

"Whether the dismissal from service of Shri N. K. Roy Bill Clerk of Gazlitand Colliery of Mess's. Bharat Coking Coal Linsted, by the Agent, Gazlitand Colliery for the missing amount of Rs. 22,608 from the cash Box on 4|5-10-1981 from inside locked cash room, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri N. K. Roy was a permanent employee of Gazlitand Collie y of M/s. BCC Ltd. He was posted as Bonus Cle k but at the relevant time he was working as a Bill C'erk, He was entrusted with Rs. 93,200 on 4-10-81 for payment of salary wages to the employees of thre colliery for the month of September, 1981. He disbursed Rs. 68.598.00 of the employees and was required to return the balance undisbursed amount of Rs. 24,602 to the cashier towards the end of his duty. The concerned workman did not hand over the undisbursed amount to the cashier to be kept in the safe custory. He kept the wooden cash box in the cash room in the evening of 4-10-81 containing the undisbursed balance amount of Rs. 24,602. The other cash box were also kept in the said room. The cashier locked and sealed the said room and left his office. On the next day i.e. on 5-10-81 the cashier opened the room and along with him the concerned workman and other persons, who had kept the cash box in the said room entered to take their box. The concerned workman tound the lock of his wooden box broken kept on the ground. Subsequently it was found that there was Rs. 1,914 left in the wooden box of the concerned workman but the rest of the amount of Rs. 22,688 was missing from the said box. The concerned workman informed the cashier about it and thereafter the cashier informed the higher authority. rities. A case was also lodged before the Police stating that there was thest of the said money from the cash box of the concerned workman. The Manager Gajlitand Coll'ery vide his office memo dated 9-10-81 issued chargesheet to the concerned workman regarding the missing amount of money which was kept in the wooden box in the Colliery office cash room. The concerned workman submitted his explanation to the chargesheet. Thereafter the management held a departmental enquiry into the charges against the concerned workman for misappropriation of money of the management Rs. 22,688 on 4-10-81. The management examined witnesses in the departmental proceeding in presence of the concerned workman and gave him full opportunity to cross-examme them and to defend himself. After completing the enquiry the enquiry officer submitted his enquiry report holding the concerned workman guilty of the charges. Thereafter the Agent of the colliery issued a letter under his signature dated 12-1-82 without any authority dismissing him from service. The concerned workman approached the officers of the colliery at different levels and also submitted a patition in writing addressed to the Agent, Gajlitand colliery about his wrongful dismissal but no reply was received by the concerned workman. Thereafter the union of the workmen raised industrial dispute before the ALC(C) Dhanbad who took up the matter with the parties. He held the

correliation proceeding which ended in failure and thereacter the present reference was made to this Tribunal for adjudication. The concerned workman had been made a scape-goat to save the skin of some other persons responsible for the missing amount from the management's colliery cash toom. The charge against the concerned workman had not been established in the enquiry proceeding and the enquiry officer was made to submit a got up report against the concerned workman. It is submitted that the dismissal of the concerned workman by the Agent is not justified and that he should be reinstated with full back wages from the date of his dismissal till the date of his reinstatement as if he was never dismissed from service along with other benefits.

The cash of the management is that the concerned workman ought to have returned the balance undisbursed amount of Rs. 24,602 to the cashier towards the end of his duty but the concerned workman kept the amount with himself. The the concerned workman kept the amount with himself, concerned workman had kept the wooden cash bo wooden cash box on 4-10-81 without handing over the undisbursed amount to the cashier to be kept in the safe custody and left the office. the next day (5-10-81) in the morning it was reported that the wooden box of the conceined workman contained only Rs. 1914.00 and the amount of Rs. 22,638.00 was missing. The police was immediately informed to investigate the facts and circumstances under which the toss of Rs. 22,688.00 occured. After a careful consideration of all the facts and circumstances of the present case it was observed that the concerned workman had committed the misconduct their, fraud and dishonesty and was directly responsible for the loss of the amount. It was a cash of misappropriation of the amount and the concerned workman was trying to plant out a case of theft in a pre-planned manner to avoid the responsibility. The concerned workman was issued with a chargesheet dated 9-10-81 on the allegation of commission of the misconduct of theft to which he submitted his reply. Shri H. K Choudhury Personnel Officer of Gajlitand Colliery was appointed to hold the enquiry into the chargesheet. The enquiry officer after serving the notice of enquiry conducted the enquiry on 25-11-81 to 27-11-81 in accordance with the principles of natural justice. The concerned work-man along with his co-worker fully participated in the enquiry on all the dates. The witnesses of the management were examined in the presence of the chargesheet workman who was given full opportunity to cross examine the management witnesses. The concerned workman gave his own streement before the Enquiry Officer. He was given full opprotunity to produce his witness and documents in his After examination of all the materials on record the enquiry officer held the concerned workman guitly of the misconduct alleged against him. The dismissal of the concerned workman was duly approved by the competent authority. The concerned workman was dismissed from his services by a letter dated 12-1-82 issued by the Agent of the colliers who is a competent authority to dismiss a workman under the Standing Orders. The action of the management under the Standing Orders. The action of the management is legal and bounfide and the concerned workman is not entitled to any relief.

Farlier on the prayer of the parties a preliminary issue was taken up for hearing in respect of the fact whether the enquiry was fair and proper and in accordance with the principles of natural justice. By the order dated 20-3-86 this Tribunal held that the enquiry was fair and proper and that the principles of natural justice were adhered to.

Now the point for decision is whether the charge levelled against the concerned workman was established on the materials produced before the enquiry officer in the enquiry proceeding.

The management has produced napers regarding the enouity proceeding and they have been marked Ext. M-1 to M-7. The concerned workman has produced judgement of the criminal case in respect of the said allegation which is marked Ext. W-1.

Fxt. M-1 dated 9-10-81 is the charactest which shows that on 4-10-81 the concerned workman was assigned to make monthly payment to the staff for the month of Sentember, 1981 and for that purpose he withdrew a sum of Rs. 46 700.00 In the morning and Rs. 46.500 00 in the afternoon from the

cashier and thus he had drawn a total sum of Rs. 93,200.00. It is further alleged that as per existing practice the concerned workman was supposed to make payment to the staff and deposit the unpaid amount with the cashier along with paysheets with signature and account showing payment having been made. It is further alleged that on 5-10-81 at 9.30 A.M. the concerned workman along with payment clerks went to the cashier's office to collect payment box for further payment on that day and that the concerned workman reported that the lock of his box was broken and that a sum of Rs, 22,688 was stolen by breaking open the lock of his payment box and that a sum of Rs. 1914.00 was found lying in the box. It was alleged that the theft was a manipulated one and that a sum of Rs. 22,688 had been misappropriated by the concerned workman on 4:10.81 since if at all there had been any theft in the cashier's room, the other payment box should have also been broken and money stolen. Ext. M-2 is the reply to the chargesheet submitted by the concerned workman denying the allegation of mis-appropriation by him. It is stated in the said reply that other cash box of other pay clerks were also found tam-pered with along with the cash box of the concerned work-man of which the hook of lock was broken and the cash removed. It was not possible for the concerned workman to break the hook and lock of the cash box during the day hours. There is an open ventilator on the wall of the room of the cashier and probability of a thief entering inside the room of the cashier through the ventilator and committing the theft from the cash box of the concerned workman in collussion with the guard cannot be ruled out. Some foot prints and finger marks were found on the wall of the room of the cashier near the ventilator outside as well as inside the room.

Ext. M-4 is the enquiry proceeding and Ext. M-5 is the enquiry report. Ext. M-6 are the notes initiated by the Agent of Gajlitand Colliery containing the approval of the General Manager. Ext. M-7 is the dismissal letter issued to the concerned workman.

Let us now turn up to the Enquiry proceeding Ext. M-4 itself to see the evidence adduced on behalf of the management to prove the charge against the concerned workman. It is the admitted case of the parties that the concerned workman who was working as a Bill Clerk of Gailltand Colliery was entrusted with Rs. 93,200.00 on 4-10-81 for nayment of salary/wages to the employees of the colliery for the month of September, 1981. It is also admitted that the concerned workman disbursed Rs. 68,598.00 to the employees and there was a balance of undisbursed amount of Rs. 24,602 out of which Rs. 1914.00 was found in the cash box of the concerned workman in the morning of 5-10-81. It is also admitted that Rs. 22,688 was not found in the box of the concerned workman. The question therefore is whether this amount of Rs. 22.688 was misappropriated by the concerned workman.

The management examined before the Enquiry Officer Shri S. Mukherice. Cashier of Gallitand Colliery Shri D. D. Ghosh Head Clerk/Accountant Gajiltand Colliery Shri P. Choudhury. P. F. Clerk, Gallitand Colliery, Kashinath Bhandri. Havildar, Sisir Kumar Dubey, Night Guard, M. G. Philip Bill Clerk Teal Roboty Rece Level Paladar, Nick. Philip. Bill Clelrk, Tal Bahadur Peon, Jagat Bahadur Night Guard and Ramadhar Singh, Sub Inspector of Police, Katras None of these witnesses were eye wilnesses to the theft or misannronriation of the amount from the cash box of the concerned workman. It was also not possible to get ever witness in a case of this nature and it is mostly the circumstances which would establish whether the allegation made against the concerned workman has been established or not. will first take un the statement of the Sub-Inspector of Police Katras Shri Ramadhar Singh, The said Sub-Inspector. had come to investigate into the information lodged before the rolice. The Police had first registered a cash under Section 457 and 380 LP.C. on the allegation made in the FIR, but subsequently the chargesheet was submitted under Section 409 J.P.C. against the concerned workman. He has stated that on perusal of the place of occurance he did not, think the possibility of theft of money from the cush room through the ventilator on the ground that there was round the clock guard and that none of the guards stated before him about the appearance of any thief in connection with

the theft and therefore he concluded that the concerned workman had committed breach of trust in respect of money which had not been disbursed by him to the employees. It appears from his statement that he had found finger print and foot print at the place of occurrence which made allegations against the concerned workman doubtful. He has further given reasons as to why no thief would enter in the cash from through the ventilator because of its height and no support inside the room to reach the ventilator. In cross-examination he was asked about the height of the ventilator from the table inside the room which was about 8'-6". In his answer to another question be has stated that it was possible to reach ventilator after a jump from the table. He also stated that with the support of a chair and existence of projection in the wall, there was possibility of entering inside the room through the ventilator. He also stated that from the statement of the Peon he learnt that the cash room was not guarded by the guards from the eastern side.

It will appear from the evidence of S. Mukherjee, Cashier that Sudarshan Yaday informed him that hinges of his cash box which was kept in the cash room was also damaged. He has further stated that the employees were showing the foot prints inside the wall of the cash room. This witness had asked all the bill clerks to got out of the room and the eafter he went to inform his superior officer after locking the cash room. On his return and opening the cash room he had also seen the marks on the wall inside the cash room. Shri P. Choudhury had also gone along with the concerned workman and Shri M. G. Philips to take his payment box which was kept in the cash room. It will appear from his evidence that he had kept no money in his finger prints on the wall inside the cash room. D. D. Ghesh had come in the cash room when S. Mukherjee had informed him about the breaking of the lock of the cash box of the concerned workman. He has stated that Shri S. Mukherjee had told him that the broken lock was shown to Shri S. Mukherjee which was lying on the ground. In his crossexamination he has stated that when he went inside the cash room he found the hinges and the lock of the cash box of the concerned workman broken and fallen on the ground. In answer to another question he has stated that a lia and thin person can enter inside the cash room through the ventilator in the wall of the cash room. It appears therefore that there was possibility of a thief entering inside the cash 100m through the ventilator. M. G. Philip, Bill Cletk had also gone along with the concerned workman inside the cash 100m when the cashier Shri S. Mukherjee opened the cash 100m at about 9.30 A.M. on 5-10-81. He had kept his cash box above the cash box of the concerned workman and he had also kept his pay sheet on his box which was not there and it was found inside the spittoon of the cacshier He has stated that the concerned workman told him at once that the lock of his payment box was broken and is fallen on the ground and thereafter the concerned workman reported the matter to the cashier. The payment box of witness M. G. Philip was in tact. He had also found foot prints and hand prints on the wall. He had found some nails fixed in the wall of the cash room. wall of the cash room. Thus from the evidence of above witness it is clear that a man could enter inside the cash room through the ventilator from outside and that he could also go out of the room through the ventilator. The fact that the witness found foot prints and hand prints on the wall inside the cash room also suggests the truth of the fact that the thief had entered inside the cash room and had escaped through the ventilator by scalting over the wall leaving marks of foot prints and hand prints. It will also appear that as soon as the concerned workman had entered inside the cash room when it was opened by the cashier, the concerned workman immediately told that the lock of his cash box was broken and was lying down on the ground. It will also appear that Shri Philip had kept his cash box upon the cash box of the concerned workman and Shri Philip also kept his pay sheets upon his own cash box. The said pay sheet was not found upon his box and the same was found in the spittoon of the cashier at some distance from the place where the boxes were kept. It also appears from the chargesheet Fxt. M-1 itself that the hinges of cash box of Sudarshan Yadav was also damaged. There was no possibility of the concerned workman entering inside the cash box after he had kept his cash box in it as the said cash room had been locked and sealed by the cashier from outside and the said lock and seal was found intact in the morning when

the cashier opened the room. There is no explanation by the management as to how the cash box of Sudarshan Yadav was also found damaged. There are the circumstances to show that some outside agency had entered inside the room may be through the ventilator and had taken out the money from the cash box. There is absolutely no evidence to show that the concerned workman had actually taken the money out of his own cash box. His house was also searched by the police but no amount was recovered from him.

Shir Kashinath Bhandari Havildar has stated in his cross-exammation that when he went to the office at 7.30 A.M. on 5-10-81 he found the main gate open and Rajendra Singh orderly Peon who was deputed on duty at the gate was not on his duty. He had checked the lock of the omice and had found the seal in tact. Sist kumar Dubey and Jagai Bhandari were Night Guards from 10.00 P.M. to 6 A.M. in the night between 4th and 5th of October, 1981. He has stated that nothing happened in the night. He had found the seal of the cash room intact when he had joined his duty. He has stated that they did not give round on all the 4 sides of the cash room. He used to watch by peeping through the gap of the door which was closed with a rope. It appears from his evidence that the watchman did not go on the eastern side in the round and that they only used to peep through the doors on the eastern side. Thus the possiblity of thief coming from the eastern side of the cash room and committing theft from the eastern side through the ventilator cannot be ruled out.

I have discussed all the evidence on the record. The circumstances which have come in the evidence before the enquiry officer does not establish that the concerned workman had misappropriated the undisbursed amount lying with him on the contrary there is enough of evidence to show the possibility of theft inside the cash room through the ventilator of the cash room. In order to establish the charge on the basis of circumstances there must be evidence to cover all the loop holes leading to the only conclusion that it was the concerned workman who had committed the misappropriation of the money. In the present case as I have discussed above it appears that there is not much of circumstances to show that the concerned workman had misappro-priated the amount. On the contrary there is material on the record to show that the amount had been stolen from the cash box of the concerned workman from the cash room and the thief had entered inside the cash room through the ventilator. As the watchman were not giving rounds on the eastern side of the cash room, the possibility of theft from eastern side appears all the more glaring. the result, I hold that the management have not been able to establish the charge of misappropriation against concerned workman and as such he deserves to be reinstated in his job.

In the result, I hold that the dismissal from service of the concerned workman Shri N. K. Roy, Bill Clerk of Gajlitand Colliery for the missing amount of Rs. 22,688.00 from the cash box on 4/5-10-81 from inside the locked cash room is not justified. The concerned workman is therefore reinstated in his service from the date of dismissal with all back wages and other consequential benefits which might be available to him.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012(365)/82-D.HI (A)] A. V. S. SARMA, Desk Officer. मई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का.भा. 2702.—केलीय सरकार, कर्मचारी मविष्य निधि स्काम 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप पैरा (1) के प्रमुपरण में, भारत के राजपल, भाग 2, खंड 3, उप खंड (1i) मारीख 8 सितम्बर, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की प्रक्षित्वस्वास सं. का.भा. 2918 नारीख 24 प्रगस्त, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, ग्रम्बित —

उक्त भधिसूचना में,--

 (i) अम सं 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, प्रथात्:— "6. श्री ए.बी. चौधरी, श्रम सलाहकार, इंडियन चेम्बर धाफ कामर्स, इंडियन एक्सचेंज 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-700001"

(ii) जम सं. 11, 12, 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कमशः निम्निकिति कम सं. और प्रविष्टियां रखी आएंगी, भयास्:—

"11. श्री ही. पी. चक्रवर्सी, क्षी अन्तपूर्णा कटिन मिल्स एंड इन्डम्ट्रीज लिमिटेड के सबस्य को सामान्यतः पी. 10, न्यू हावड़ा श्रिक एप्रोच रोड, कलकत्ता-700001 }

12. श्री लाल बहावुर सिंह, संयुष्त महासचिव, श्राई. एन. टी. यू. सी. बंगाल, शर्माखा, 177/बी, आवार्य जगदीण बसु मार्ग, कलकता-14

[सं. वी 20012/1/83-पीएफII]

N:w D lhi, th: 14th July, 1986

S.O.2702:—In pursuance of sub-pursuar ph (1) of pare graph 4 read with puragraph 5 of the Employees Provident Funds. Scheme, 1952 the Central Government have by makes the following amendment in the notification of the Government of India in the 1ste Ministry of Labour and Richabilitation (Department of Labour) No.S.O.2918, dated the 24th August, 1934 published in the Guzett of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated the 8th September, 1984, namely ;—

In the said notification....

i) for a clad number 6 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

"6. Shri A.B. Chaudhuri,
Labbur A lvis r,
Lali in Chamb r of Comm rec,
Lali in Exchang,
4. India Exchang Place,
Calcutta—700001."

ii) for s rial numb rs 11, 12 and 13 and the entries ther to, the following s rial numbers and entries shall respectively be substituted namely:—

"11 Shri D P. Chakravarti, | Member of the Shray Annapurana Cotton Mill | Central Board of and Industri's Limited. | Trustaes, Emp-10, N w Howeth Boidg: | loyies Provid nt Approach Road, Celeutta-700001. | Fund, ordinarily \$recidents of West 12. Shri Lal Buhadur Singh, | Bengal.

12. Shri Lal Bahadur Singh,
Joint Guaral Secretary,
I.N.T.U.C., Bungal Branch,
177/B-Achary, Jugdish Bose,
Road, Colcutta-14.

[No. V. 20012/1/83-PF-II]

का. या. 2703: — मेसर्स इन्डियन एक्सप्रेस (मयुराई) प्राइवेट लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं. 509, पूर्नेन्वापेट, विजयवाड़ा (ए.पी./5636) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवस्त प्रधिनियम, 1952 (1952का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए धानेबन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्माचारी, किसी पृथक सिभदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के झधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जी कर्मचारी निक्षेप सहब्रद्ध बीमा स्कीम 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्स स्कीम कहा गया है) के अक्षीन उन्हें अनुशेय हैं।

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध भनु-सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रषि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवत्तंन से छूट वेती है।

मनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक पविष्य निधि धामुक्त, गुन्दूर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भीधिनियम की घारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के भीधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का घन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय घादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म चारियों की बहुसंख्या की माषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की प्रविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरुत वर्ज करेगा और उसकी बाबत धाबस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के भ्रामीन कर्मजीरियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रमीन कर्मेचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित कप से वृद्धि किये जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रामीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से भ्रमिक भ्रमुकूल हो जो उक्त स्कीम के भ्रमीन भ्रमुक्त भ्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के भ्रमीन भ्रमुक्त भ्रमुक्त हो हो उस्त स्कीम के भ्रमीन भ्रमुक्त हो हो उस्त स्कीम के

- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के भ्रष्टीन संदेय रकम उस रक्तम से कम है जो वर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के भ्रष्टीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के जितिक वारिस/नाम मिर्वेशिती को प्रक्रिकर के रूप में दोनों रक्तमों के भ्रन्तर के बराबर रक्तम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोजन प्रादेशिक भित्रिष्य निधि प्रायुक्त, गुस्तूर के पूर्व भनुमोबन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिहून प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त प्रभाव प्राप्ता देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रापना वृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मवारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने अपना बुका है भक्षीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अपोन कर्मवारियों की प्राप्त होने बासे फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवन्न मियोजक उस नियम तार्राख के भीतर जी भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने भें भसकल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, खूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकार की वशा में उन मृत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते बीमा कायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधान प्राने बाले किसीं सबस्य की मृत्य होने पर उसके हक्तदार नाम निवेंशितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम क्षा संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर धुनिश्चित करेगा।

[सं. एस 35014(134)/86एस एस 2]

S.O. 2703.—Whereas Messrs Indian Express (Madurai) Private Limited, Post Box No. 509, Poornandapet, Vijayawada Pin Code No. 560016 (AP/5635) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Guntur and maintained such accounts

- and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to tune.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount poyoble under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, whilin the duc date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lance, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

नई बिल्सी, 15 जुलाई, 1986

का. अ. 2704---कर्मवारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त गिन्तयों का प्रयोग भरते हुए केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा 16 जुनाई, 1986 को उस सारीख के रूप में नियत करती है, जिसकी उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 धौर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रकृत की जा चुकी है) धौर अध्याय 5 धौर 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 धौर 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त को जा चुको है] के उपबन्ध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थान्:--

"जिला संगरूर में संवेरा राजस्य ग्राम हृद बस्त नं. 49."

[संख्या एस-38013/23/86-एस एस-1]

New Delhi,, the 15th July, 1986

S.O. 2704.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th July, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Section; 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely:—

Revenue village of Sanghera, Had Bast No. 49, in the District Sangrur."

[No. S-38013/23/86-SS I]

का. अा. 2705.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की घारा 1 की उपघारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जुलाई, 1986 को उस तारीख के रूप में नियंत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 भीर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) भीर अध्याय 5 भीर 6 [धारा 76 की उपधारा (1) भीर धारा 77, 78, 79 भीर 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखत क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"कोट्टायम जिले के कोट्टायम तालुक में पैक्सबैकाड राजस्व ग्राम (कुमारानैलूर नामक क्षेत्र को छोड़कर) तथा कैयूका राजस्वताम (अरपूकारा नामक क्षेत्र को छोड़कर) के अन्तर्गत अन्ते वाले क्षेत्र ।"

[संख्य एस-38013/24/86-एस एस-1]

S.O. 2705.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th July, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following greas in the State of Kerala, namely:—

"The areas within the revenue village of Perumbaikad (excluding the area known as Kumaranellure) and revenue village Kaipuzha (excluding the area known as Arpookara) in Kottayam taluk of Kottayam District."

[No. S-38013/24/86-SS. 1]

का.आ.2706.—मैंसर्स नेणनल खेरी डिवेल्पमेंट बोर्ड, आतन्द (गुजरात) (जी जै/6775) (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्त स्थापन करात्रसाहै) ने कर्नवारी भवित्य नित्रि प्रोर प्रकोर्ग उन्त्रस्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपयारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए अविदन किया है।

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्न जारो, किसी पृयक अभिदाय या प्रोमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुसूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेष हैं।

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रवत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर हमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट णतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूत्री

- 1 जन्न स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक मिलिब्स निधि आयुक्त, अहमदाबाव को ऐसी विवर्णियां भेजीया ग्रीट ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम को घारा 17 की उपधारा 3-क के अधीन खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृतिक बोमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवःय, लेखायों का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने वाले सभी अपयों का वहन नियोजक द्वारा किया आएगा।
- 4. तियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के भूचना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्नेवारी जो कर्मेवारी भविष्य निधि का या जक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की मिल्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्म करेगा ग्रीर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीत कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाय जाते हैं, तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से बृद्धि किये जाने को ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीत उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अदीन अनुक्षेय हैं।
- 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अत्रीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस वशा में संदेय होती अब वह उक्त स्कीम

के अधीन होता तो, नियोजक कर्मजारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकनों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में गोई भी संगोधन प्रादेणिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाव के पूर्व अनुभोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संमावना हो, यहां प्रायेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यथि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारमीय जीधन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायबे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस तारीख के भीतर को भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असकल रहता है भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम दिशातियों या विधिक पारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाते बीमा फायदों के संदाय का उसरवायिस्त नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसों को भीमाकृत रकम का संवाय तत्परना से और प्रस्पेक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीसर सुनिश्चित करेगा।

[एस 35014(193)86-एम एस-2]

S.O. 2706.—Whereas Messrs National Dairy Development Board, Anand, (Gujarat) (GJ/6775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and publicat to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- I The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the opployees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Issurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

^{*} [No. \$-35014/193/86 (\$\$-П)]

का. ग्रा. 2707.— मैससे घ्रो. एम. सी. कम्पूर्टज लिमिटेड, पांचर्यी मंजिल, चिनोय ट्रेड मेस्टर 116. पार्कलेन, मिकन्दराबाद, (ए. पी./12895) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मजारी पांकट्य निधि घ्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रीधनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भ्रिधनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (2क) के भ्रधीन छट दिए जाने के लिए भावेदन किया

भीर केलीय सरफार का तंमाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भिन्नदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम दी सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहअब बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त स्कीय कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें अनुक्षिय हैं।

भतः केन्द्रीय सरकार, उन्तर भिष्टियम की घारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवत्त गस्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाग्यद्ध भनुसूची में बिनिर्विष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की धनिर्वि के लिए उन्तर स्कीम के सभी उपधन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

धनुसूची

- उपन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि झायुक्त, झान्छ्र प्रदेश को ऐसी वियरिषयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधार्ये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिश्ट करें ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के भ्रधीन रामय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रकार्गन लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियस का संदाय, लेखाओं का मन्तरण, निरीक्षण प्रभागें संदाय आदि भी है, होने वाले सक्षी अवयों का महन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति भीर अब कभी उनमें संशोधन किया आए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्य की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनृषाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यिव कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिवल्य निधि का या उबत प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम हरून दर्ज करेगा धौर उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबन करेगा।
- 6. यदि जनत स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृष्टित क्य से बृद्धि किए जाने की न्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध कायदे उस कायदों से श्रधिक श्रवकृत हो जो उदह रकीम के श्रधीन श्रवकृत हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के घटीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती जम बा उक्त स्कीम के घटीन होता हो, निमाजक कर्मचारी ने सिश्चित कारिस/नाम निर्देणिती को प्रतिकर के कम में दोनों रक्षमों के शन्तर के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन प्रादेशिक प्रित्य निधि प्रायुक्त, प्रान्ध धदेश के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएना धौर जहां किसी संबोधन से कर्मनारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक पविष्य निधि प्रायुक्त प्रभम प्रमुपेदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रथमा नृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवस्त विभा ।

- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी धारतीय जीयन कीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है भधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के ब्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवय नियोजक उस नियस तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ध्यतिक्रम की क्या में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न वी गई होती तो, उक्त स्कीम के धन्तगंत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उसत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के मधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाइन्त रकम का संदाय तत्परता से ग्रीर प्रत्येक देशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन्त रकम प्राप्त होने के एक मास भे भीतर सुनिश्चित करेगा।

[रॉ॰ एस. - 35014 (192) 86-एस. एस. -2]

S.O. 2707.—Whereas Messrs O.M.C. Computers Limited, 5th Floor, Chenoy Trade Centre, 116, Park Lane, Secundrated (Andhras-Pradesh) (AP/12895) thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tarourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the contribons specified in the Schedule annexed hereto, the femial Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Schedule for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from tune o time
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borned to the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Where 25 an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to be employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstending anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/noraince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adposted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are teduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]192|86-PF-II (SS.II)]

का. भा. 2708.— मैसर्स दुर्मापुर स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन, दुर्मापुर-713201, जिला नर्भमान, (बेस्ट बंगान) (डबस्यू. की./11732) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध मिशियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मिशियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए मावेदन किया है।

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्तत स्थापन के कर्मवारी, किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायवे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मवारियों के लिए ये कायवे उन कायदों से प्रधिक अनुकूत हैं जो कर्मवारी निपेक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पृथ्वात् उनत स्कीम कहा] गया है) के ग्रधीन उन्हें भनुक्रेय हैं

मतः केन्द्रीय (सरकार, पंडकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावक अनुसूची 555 G1/86-8 में त्रिनिधिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उनत स्थापन की सीन वर्ष की अवधि के लिए उनत स्कीम के सभो उपबन्धों के प्रकृति से छूट देती है।

प्रनृ*भू*ची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक शिवध्य निधि श्रायुक्त, कलकता को ऐसी विवरणिया गेंग्रेगा और ऐमे लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधार्थे प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे । ;
- 2. नियोग त, ऐपे निरोग्नग प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्त के 15 दिन के मीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड -क के मधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे क्रिं
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके छन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, शिखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय भावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का घटन नियोजक द्वारा विधा जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविक्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामृहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन नीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से श्रधिक श्रनुकूल हो जो उपत स्कीम के श्रधीन भ्रनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधीन संदेय एकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के भधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विश्विक वारिस/नाम निर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अस्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीय के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निश्चि मायुक्त, कलकला के पूर्व मनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जड़ा किसो संशोधन से वर्मवारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने का संभावना हो, यहां प्रावेशिक भविष्य निश्चि ध्रायुक्त घपना मनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का यिक्तमुक्त ध्रवसर बैगा ।
- 9. यदि किसी कारणवर्षा स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना भुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रह की जा सकती है । अ
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस नियत तारीख के भीतर को भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे; प्रीमियम का संदाय करने में ससफल रहता है भीर पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रहकी जा [रुकती है।

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वक्षा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के भन्तगंत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन धाने बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों/ विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से धीर प्रत्येक बसा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[त. एस. 35014 (191) 86-एस. एस. -2]

S.O. 2708.—Whereas Messrs Durgapur State Transport Corporation Durgapur-713201, Distt. Burdwan, West Bengal (WB/4732) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds, and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of cection 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident band Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the contral Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount poyoble under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. West Bengal, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to tapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal hoirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/191/86-PF-II (SS-II)]

का. आ. 2709 — मैससं दि नारंप एरकोट जिला को. ह्यो. स्पर्तिग मिल्ज लिमिटेंड, पोस्ट बोक्स नं. 1, आरीपूर तामिलनाड् (टी. एन./5505), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

मीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अक्षीन जीवन जीवन जीवा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उक्हें अनुक्रेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूधी में विनिधिष्ट कर्तों के अधीन रहतें हुए, उक्त स्थापन की तीन दर्य की अविग के लिए उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

 अक्त स्थापन के सम्बाख में नियोजक प्रादेशिक मविष्य निधि आयुक्त, तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा प्रौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, रामय-समय पर निविष्ट करे।

- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के गीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आवि मी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय भरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामृष्टिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी धाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीम निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उनत स्कीम के अधीन अनुनेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्काम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के कप में दोनों रकनों के अस्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक शिवय निधि आयुक्त, तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मनारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिफ बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सवती है।
- 10. मिंद किशी कारणवंश नियोजक उस नियंत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियंत करे, श्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है भीर पालिसी को क्यमगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए जिसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सबस्यों के भाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को को यिव यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते ! कीमा कायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने बासे किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हरूदार नाम निर्देशितियों/

विधिक बारिसों को बीमाक्कत रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[तं. एस. 35014(190)86-एस. एस.-2]

S.O. 2709.—Whereas Messrs The North Arvcot Distt. Cooperative Spinning Mills Limited, Post Box No. I, Ariyur-632055 (Tamil Nadu (TN/5505) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed nereto, the Central Government hereb/exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Prevident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection is the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu

and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/190/86 (SS-II)]

का. था. 2710.—मैसर्स पंजाब झलकालिज एण्ड केमिकल लिमिटेड, एस. सी. भी. 125-127, सेक्ट्र 17-बी, पीस्ट बाक्स नं. 152 चण्डीगढ़-160017 (पी.एन./9900) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त झिंधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए झाबेदन किया है।

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपत स्थापन के कर्मजारी, किसी पृथक ध्रमिवाय या प्रोमियम का संदाय किये बिना ही, धारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के ध्रमित जीवन बीमा के रूप में कायवे उठा पहे हैं भौर ऐसे कर्मजारियों के लिये ये कायवे उन कायवों से घ्रमिक धनुकूल हैं जो कर्मजारी निक्षेप सहब्द्य बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ब्राधीन उन्हें धनुक्षेय हैं।

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा एदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावत प्रनुसूची में विनिधिष्ट भारों के प्रधीन रहते हुए, उनत स्थापन की तीन वर्ष की सबिध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट वेती है।

धनुसूची

- उफ्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि धा-युवल, अध्दीगढ़ को ऐसी विदर्शियां भेजेश भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुधिधार्ये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के ग्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृष्टिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके बन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का बन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय घावि भी है, होने वाले सभी ब्ययों का बहुन नियोजक द्वारा विया जाएगा।

- 4. नियोजन, केट्डीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति श्रीर अब कभी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में नुख्य बातों का प्रमुखाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त चित्रियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में निश्रोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूपे में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत भावश्यक प्रीमिथम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उपत स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुज्ति रूप से वृद्धि किये जाने की स्ववस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में श्रधिक सनुकूल हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन धनुवेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसा बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मवारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोक्तक कर्मवारी के विधिक वारिस/नाम निवेशितों को प्रतिकर के रूप में बीमों रकमों के अस्तर के बरावर रकम का संवाय करेगा।
- 8. नामूहिक बीमा स्टीम के उत्तबन्धों में कोई मा संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के विना महीं किया जाएगा श्रीर जहां किसी संशोधन से कर्मवारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त भपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मवारियों को भपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर होगा ।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मबारो भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना अका है प्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मबारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो आते हैं, तो यह खुछ रद्द की जा सकता है।
- 10. यदि किसी कारणवस नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बोमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में प्रसफल रहता है भीर पालिसी को स्थमगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकम की दला में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक बारिसों को को यदि यह छूट न वी गई होती तो, उन्त स्कीम के प्रस्तर्गत होते । वीमा कायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन प्राप्त वाले किसी सबस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशितियों/विधिक वारिसों की बीमाइन रकम का संवाय सत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निर्मा से बीमाइन रकत प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सिं. एस. 35014(189)86-एस.एस.-2]

S.O. 2710.—Whereas Messrs Punjab Alkalies and Chemicals Limited, S.C.O. 125-127, Sector 17-B, Post Box 152, Chandigurh-160017 (PN/9900) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Contral Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and nay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the <u>legal</u> heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/189/86 (\$S-II)]

का. था. 2711.—सैगर्स पंजाब बूलकाम्बरज लिमिटेड, धंटारी कलान, जी. टी. रोड, लुधियाना (पी.एन./5950) (जिसे इसमें इसके पश्धात् उक्त स्वापन कहा गया है) ने कर्माचारी भविष्य मिधि झौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 जा 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सिवियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के प्रधीन छूट विये जाने के लिए आनेबन किया है।

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मकारी, किसा पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन वीमा निगमकी सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायबे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मकारियों के लिये ये फायबे उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मकारी निक्षेप सहबद्ध बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधान उन्हें अनुजेब हैं।

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त सिवित्यम की छारा 17 की उपधार-2क द्वारा प्रदरत सक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनसूची में विनिधित्य सतों के सधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की सबधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट वेती है।

मनुसुधी

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रविक्रिक भविष्य निधि धा-युक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीजिंग के लिए ऐसी सुविक्षायें प्रदान करेगा जो कैन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा को केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक नीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके घन्तर्गत लेखायों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, क्षेश्वायों का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय धावि थी है, होने बाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया आएगा।
- 4. नियोजन, केम्ब्रीय सरकार द्वारा अनुमेखित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति घीर अब कधी उनमें संजोधन किया जाये, तब उसे संजोजन की प्रति तथा कर्म्यारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुवाद स्थापन के सुखना पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा फर्मवारी जो कर्मवारी भविष्य निश्चि का या उक्त धिनियम के मधीन छूट प्रान्त किसी स्वापन की भविष्य निश्चि का पहले ही तरस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के का में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा भीर उसकी बाबत भावस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदक्त करेगा।

- 6: यदि उक्स स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध पायदों में समुवित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक हो जो उक्स स्कीम के प्रधीन मनुनेय हैं।
- 7. सामूहिक घोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस के प्रधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम हैं को कर्मचारी को उस दणा में गंदेय होती जब वह उक्त स्कीम के भ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्येशिक्षी को प्रतिकर के हप से दोनों रक्तमों के भ्रम्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि, भ्रायुक्त, पंजाब के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के दित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त भपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रापना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यवि किसी कारणवश्च स्थापन के कर्मकारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका है मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायबे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणक्य नियोजक उस नियह तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में मसफल रहता है भीर पालिसी को व्ययत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा कायदों के संवाय का उत्तरदायिस्य नियोजक पर होगा ।
- 12. उसर स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन आने बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों को भीमाकृत रंकम का संदाय तत्यरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से भीमाकृत रंकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिध्वित करेगा।

[सं• एस. 35014(195) 88-एस.एस. 2]

S.O. 2711.—Whereas Messrs Punjab Wool, combers Limited, Dhandari Kalan, G.T. Road, Ludhiana (PN/5950) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Iddia in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment said submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall paj such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of teturns, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to layse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promot payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

का. आ. 2712. — मैसर्स स्टील आशीरिटी आंक इंडिया, लिसिटेड, एलॉय स्टील्म, प्लाट, दुर्गापुर (बर्खयात) (इब्ल्यू.बी./12646) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भयिष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम करा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

धौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उभन स्थानन के कर्मचारी, किसी पुणक धिमताय या प्रीमियम का संदाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्काम के घाडीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं धौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से धावक प्रानुकृल हैं जो कर्मचारी निक्षीप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976) जिसे इसमें इसके पण्यान् उम्त स्कीम कहा गया है) के धावीन उन्हें प्रानुत्रीय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और उससे उपानद्ध अनुसूची में विनिद्धिट शर्तों के घधीन रहते हुए, उन्स स्थापन को तीन वर्ष की सबिध के लिए उक्त स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

धनुषुची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक मंत्रिष्य निधि
 मायुक्त, पिक्सिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा
 तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुखिधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार,
 समय समय पर निर्दिष्ट करें।
 - 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय समय पर निविष्ट करें।
 - 3. नामृतिक दीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घल्तगैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का घल्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय घावि भी है, होने वाले सभी ध्यां का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्रनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये. तब उस संशोधन की प्रति तथा क्ष्मेंचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी पिक्य निधि का या उक्त स्रधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहलें ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत श्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6, यदि उक्त स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक गामृहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से घ्रधिक घनकुल हो जो उक्त स्कीम के घ्रधीन घनुकैय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रक्षम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्षत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमीं के प्रनार के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन प्रार्थिक भविष्य निधि सामुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व सनुसोदन के बिना नहीं किया

- जाएगा मौर जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भागुकत मणना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भगना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का मृतिवयुक्स मबसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारभवा स्थापन ने कर्मचारी मारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले याना चुका है मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले पायदे किसी रीति से कम हो जाले हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम सारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भसकल रहता है भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है सो, छट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विश्विक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उन्त स्कीम के प्रस्तर्गत हीते । बामा फायदों के संदाय का उत्तरवायित नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियालक इस स्कीम के अर्धाप आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मृतिश्चित करेगा।

[सं. एस. -35014(194)86-एस. एस. 2]

S.O. 2712.—Whereas Mesars Steel Authority of India Limited, Alloy Steels Plant, Durgapur-713208, District-Burdwan, West Bengal (WB/12646) (hereinafter refetred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such reteins to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer thall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. West Bengal, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. \$-35014/194/86-(SS-II)]

का. था. 2713:— मैसर्स मुकेरियन लिमिटेड, थी. टी. रोड, मुकेरियन (गंजाड) (पी. एन./9901) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की छारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रष्टीन छूट विये जाने के लिए भ्राबेदन किया है।

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्स स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रशिवाय या प्रीमियम का संवाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रष्टीन जीवम बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फायवों से भ्रष्टिक भ्रमुकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध भीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उन्त स्कीम भ्रष्टा गया है) दें भ्रष्टीन उन्हें भ्रमुक्केय हैं।

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ध्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवत्त सन्तियों का प्रयोग करते हुए धीर इससे उपावद्व धनुसूची में विनिर्विष्ट सर्तों के ग्राधीन २६से हुए, उक्त रक्ष.पण की तीन दर्घ की स्नाक्षांक के लिए उक्त स्कीम के सभी उपकक्षों के प्रवर्तन से कूट देनी है।

श्रनुसूची

- उस्त स्थापन के तंत्रं में नियोजक प्रादेशिक सविष्य निधि भायुक्त, चण्डीयक को ऐसी विवरणियां मेजेगा भौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गुलियायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. निवोजज, ऐसे निरोक्षण प्रजारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 बिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सानृहिक बीमा स्कीम के प्रकासन में, जिसके घरतांत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, धीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का धरतरण, निरीक्षण प्रमारों संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी अपने का बहुन नियोजक द्वारा विया जाएगा .!
- 4. नियोजन, फेल्ब्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, सब उस संधोधन की प्रति तथा कमैचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुक्प बातों का धनुवाय स्थापन के सूबना पट्ट पर प्रव-धित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मजारी जो कर्मवारी गविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबसा है, उसके स्थापन में नियोजत किया जाता है तो, नियाजन सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा श्रीर उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कोम के प्रधीन प्रनु- क्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीन में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कमैवारी की मृत्यू पर इस स्कीम के ब्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कमैवारी को उस दक्ता में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के ब्रधीन होता सो, नियोजक कमैवारी के विधिष्ठ वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के क्य में दीनों रकमों के घरतर के बरावर रकम का संवाय करेगा ।
- 8. सामूहिक बीमा कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भिविष्य निधि मायक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व मनुभावन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यहां प्रादेशिक भिविष्य निधि मायुक्त प्रपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मवारियों को प्रपना दृष्टिकांण स्पष्ट करने का युक्ति-, मुक्त सबसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणबंध स्थावन के कर्मभारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस जामृद्धिक बीला रक्षीन के, 'जिसे स्थापन पहले अपना सुका है अबीन नहीं रह जाता है या इस स्क्रीम के अधीन कर्मशारियों को प्राप्त होने बासे फायदे किसी रीति से कम हो जासे हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणबक्त नियोजक उस नियत तारीख के मीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसक्तन रहता है घोर पालिसी को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो, खूट रह्द की जा सकती है।

- 1.1. नियोजक हारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिकम को दला में उन मृत सदस्यों के नाम निवेंशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दीं गई हीती तो, उक्त स्काम के अन्तर्गत हैं।ती बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायिस्य नियोजक पर होगा ।
- 12. उसत स्थापन के संबंध में नियं।जक इस स्कीम के झधीन झाने बाले किसी सबस्य को मृत्य हाने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीवाकृत रकम का संदाय तत्परता से झौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन जीमा निगम से बोमाकृत रकम प्राप्त हाने के एक मास के भीतर सुनिध्वित करेगा ।

[सं०एस. 35014/188/86-एस. एस. 2]

S.O. 2713.—Whereas Messrs. Mukerian Paper Limited, G. T. Road, Mukerian, (Punjab) (PN|9901) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, wi hout making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the s li nt features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Gorp Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that valud be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No arrendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adve sely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Cornoration of India, and the notice is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of Insurance benefits to the nominees or the leval heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the reactet of claim complete in all respects.

[No. S-35014]188[86-(SS. H)]

का. प्रा. 2714 में 14 रागे (मग्राप) लिगिटेड, 61, यैनाचरी रोड मद्राम-60003 (टील्एन० 1142) (जिसे इसके प्रशात उक्ष स्थापण कहा गया है) ने कर्मचारी भ्वित्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके प्रकान स्थितियम कहा प्राया है) की बारा 17 की उपधारा 2क के ग्रधीन छूट दिये जोने के लिए भीवेदन किया है।

भीर भैन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपन स्थापन के कर्मणारी, किपी पुत्रक प्रांनदाय या प्रीमियप का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा । नगम की सामृद्धिक बीमा स्कीम के ध्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमचारियों के लिए ये कायदे उन कारों से यिक्षक प्राृह्त हैं जो कर्मवारी निक्षेत्र सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ध्रधीन उन्हें धन्त्रीय हैं।

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए भ्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्दिष्ट गर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की भ्रवधि के सिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

ग्रन्मुची

- 1. जक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राविशिक धविष्य निधि झायुक्त, तामिलनाडू को एसी विवरणियां भेजेगा झौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के किए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें ।
- नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यैक मास की सामप्ति
 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम

557GT/31—9

की घारा-17 की अपधारा 3-क के खण्ड-क के ब्राष्ट्रील समय-समय दर निविद्य करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रस्तांत लेखाओं का एखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का ग्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय जादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोचन, केस्ट्रीय सरकार द्वारा अनुनोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों की बहुतंत्र्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का समुवाद स्थापन के सूचमा पट्ट पर प्रयक्षित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त ग्रिक्षिनियम के भ्रिष्ठीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भिवत्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उजका नाम दुक्त दर्ज करेगा भौर उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निशम की संदल करेगा।
- 6 यति उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध पायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के प्रजीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुखित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यपस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के द्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में द्रधिक धनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन धनजीय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए मी यदि किस कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के ब्राधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वशा में संदेय होती अब बह उक्त रकीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिल/नाम निर्देशितो को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के ध्रस्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उत्पारकों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निश्चि सामुक्त, सिमलनाकू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी एशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रशिकुल प्रमाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निश्चि मायुक्त भवना मनुमोदन वेने से पूर्व असंवारियों को प्रपत्ता दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्तियुक्त भवसर वेगा ।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कमैंबारी भारतीय जीवन थीमा निगन की उस तामूहिक बीमा स्कीम के. असे स्थापन पहले भ्रपना चुका है अधीन नहीं एह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कमैंचारियों की प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है ।
- 10. यदि किसी कारणवण त्रियोजक उस नियक्त तारीख के भीसर जो भारसीय जीवन बीमा निगम नियल करे, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रसफल रहता है भीर पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11. वियोजक द्वारा प्रीमियम के लंबाय में किये गये कियी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यां के नाम निर्देशितियों था विश्विक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उत्तत स्कीम के मन्तर्गय होते जीवा कार्यों जी नंदर का उत्तर्यापिक वियोजक पर होगा
- 12. उक्स स्थापन के सम्बन्ध में नियोगक इन स्कीन के ध्रधीन ध्राने बाके किसी संबस्य की मृत्यु होने पर इसके हकदार नाम निर्देशिनियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्यरता मैं ग्रीर प्रत्येक

वसा में भारतीय जीवन बीजा जिल्हा से बीकाकार एकम प्राप्त होने से एक माग के सीता मुलेफियर करेगा ।

[स॰एम.-3501 1/205/86-एस.एस-2]

S.O. 2714.—Whereas Messrs. Rane (Madras Limited, 61. Valachery Road, Madras-100032 (TN|1142) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is ratisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Dejosit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Ceutral Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tansil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month
- 3. All expenses involved in the administration of the G-oup Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwth a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable upder this scheme he less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Inturance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the Lengths to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in rayment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of india shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]205[86 (SS II)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1986

का. प्रा 2715 :- मैसर्स महमदाबाद प्यूपल्स की-आपरेटिय बैंक लि., प्यूपलस बैंह बिल्डिंग, करकें, पो, बो, नं-133 महमदाबाद (जी जो./ 4656) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कह गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रधीन छूट दिए जाने के लिए आयेदन किया है;

ष्मीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक श्रिष्ठाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उटा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से श्रीमक श्रमुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निजेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रीमीन श्रमुक्तेय हैं;

भतः केन्द्रीय सरकार, उपन प्रधिनियम की धारा 17 की उपभार (2क) द्वारा प्रदल्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधमुचना संख्या का. था. 3230 तारीख 24-8-82 के भ्रमुसरण में श्रीर इसमे उपावक धनुमुची में विनिर्दिष्ट णतों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-9-1985 से तीन वर्ष की प्रविध के लिए जिसमें 10-9-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

धनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक मिवष्य निधि भायुक्त गृजरात को ऐसी विवरिषयां भेजेगा प्रौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार सगय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निष्टिट करे

- 3. सामृष्कि बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्गत शेखाघों रक्षा जाना, मिकरणियों का प्रस्तृत किया नाना, कीमा प्रीमियम का संवाय शेखायों का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रावि की है, होने यह ते सभी व्ययों का बहुन सियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियाजक, केन्द्रीय सरकार क्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम नियमों की एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसक्या की भाषा में उसकी मुख्य दातों का ग्रज्ञाद, स्थापन के सुवना-गर्ट्ड पर प्रयोगत करेगा।
- 5. यांच काई एमा कर्मजारी, जो कर्मजारी भिषय निधि का या उक्त अधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो नियोजक समृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि मामूहिक बीमा स्कींग के भक्षीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं ता, नियांक्रक उक्त स्कीम के मधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित कर्म ने वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के भक्षीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक ध्रानुकृष्ण हो, जो उक्त स्कीम के भ्रधीन समुचेश है।
- 7. सामूहिक बीमा म्हीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सेदेय होती जब वह उनत स्कीम के प्रधीन होता तो, तियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देक्तिती का प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएना भौर जहां फिसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाध पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों की श्रपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का यूक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणक्षण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अर्धान नहीं रह जाते हैं, था इस स्कीम के शामित कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले कायंद किसी रीति से कम हा जाते हैं, तो यह छट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणभया, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियस सारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को ज्ययगत हा जाने दिया जाता है तो छूट रह् की आ सकती है।
- गा नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में फिए गए किसी व्यक्तिक की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के ग्रन्तगंत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 1.2. इस स्कीम के अधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर भारतीय जीवन बीमा निगम, गीमाकृत राशि के हकदार नामिन्दें-शिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से धौर प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मृश्यियमत करेगा।

[सब्या एस-35014/10/82-पी, एफ.-2/एस, एस-2]

New Delhi, the 21st July, 1986

S.O. 2715.—Whereas Messrs. The Ahmedabad People's Co-operative Bank Limited, People's Bank Building, Karank, P. B. No. 133, Ahmedabad (OJ|4656) (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (ZA) of section 17 of the employees Provident Funds and Mis-cilaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) he cinatter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in edjoyment of tenents under the Group Institute Scheme of the Lite institute Scheme of the Lite instrance Corporation of India in the nature of the life instrance which are more tavourable to such employees than the beneats admissible under the Employees' Depost Linked Institute Scheme, 1976 (nereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 1/ of the said Act and in continuation of the notineation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3230 dated the 24 8-1982 and subject to the continuous specified in the 5-heddle annexed heleto the Central Government hereby exempls the said establishment from the operation of all the provisions of the said centre for a further period of three years with effect from 11-9-1985 upto and inclusive of the 10-9-1588.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such tachines for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, troin time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an ensployee, who is afready a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwith randing anything contained in the G.oup Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employee shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat

- and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of Inoia as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|10|82-PF. II(SS. II)]

भा० भा० 2716:—-मैसमे पू. बी. एस. पब्लिश से जिस्ट्रीय्यूटर्स खि. 5. असारी राज, पोस्ट बाक्स नं.7015, नई दिल्लं:(इं. एल/1061) (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त स्थापम कहा पया है) में कर्मकारी भविष्य निश्चि भीर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त प्रधिनियम कहा पया है) की धारा 17 का उपधारा(2क) के अधीन खूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जया है कि उक्त स्वापन के कर्मनारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निराम की जीवन बीमा स्कीम की समृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायबा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मनारियों की उन कामवी से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मवारी निर्भेष सहबद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय हैं;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) धारा प्रवल शिक्षमों का प्रयोग करते हुए भीर भारत सरकार के कम मंजालय की अधिसूनना संख्या का आ . 3945 तारी क १-11-1982 के अनुसरण में भीर इससे उपावद अनुसूची में विभिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-11-1985 से तीन वर्ष की स्वधि के लिए जिसमें 26-11-1988 भी सम्मितित है, उक्त स्कीम के सभी जप-बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक अविष्य निष्ठि भागुक्त नई विक्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा भीर ऐसे सेखा एखेए तथा निरोक्षण के लिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक ऐसे निरीकण प्रभारों का प्रस्येक मास का समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्राय सरकार, एक अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-धमय पर निविद्ध करे

- 3. सानूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अस्तर्गत रेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रभीयम मा सन्दाध नेखाओं का अन्तरण, निर्दाक्षण प्रधारी की सन्दाय अदि भी है, हुनी बाले सभी क्यों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएना।
- 4. नियोजक केर्न्याय सरकार द्वारा थया अनुमोदित सम्मृक्ति स्मा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर अब वर्भा इसमे स्वाहित किया एए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसस्या भी भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुखन, पट्ट पर प्रदक्षित करें करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी, जो कर्मवारी भिविष्य विधि का या जिल्हा स्थितियम के अधीन छूट प्राप्त किसी रवापन का अधिय निधि का पहले हो सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजित सामूहिक वीसा कोम के सवस्य के रूप में उसका नाम हुएकत वर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावस्था। ये सियम भारिकीय जंबन बीसा दिवर, को सन्दल करेगा।
- 6. यदि सामूहिण बीमा रकीम के मधीन कर्मनारियों की उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक एक स्कंम के मधीन कर्मनारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की स्वयस्था करेगः जिससे कि कांजारियों के लिए गापूहित बीमा स्कीम के मधीन उपलब्ध फायदे उन-कायदों से मधिक अनुकूस हों, जो इक्त स्कीम के मधीन अनुकेस है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में थिसी बात के होते तुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम इस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दक्षा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिवेंशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के बराबर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक शिष्ट ज्य निधि भागुक नई दिल्लों के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि भागुक, भगना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भगना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्ति श्रूक भवसर देगा।
- 9- यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को जस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले क्रपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के सधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट पहल की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तरीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यमगत हो जाने विया जाता है तो छूट रव्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी ध्यक्तिप्रस की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामिविधितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यहु, छूट १ दो गई होती तो उक्त स्कीम के सन्तर्भत होते, कीमा कायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन वीमा, नियम बीमाकृत राशि के हंगदार नामनिवेंगिली/विधिक बारिसों को उस राशि का संखाय तत्परता से मीर प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा ।

[संका: एस-35014(93)/82-गी, एक-2/एस. एस-2]

S.O. 2716.—Whereas Moser, U.B.S. Publishers Distributors Limited, 5, Ansari Road, Post Box No. 7015, New Delhi-110002 (DL|1061) (hierafter referred to as the said establishment) have applied for exemption 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3945 dated the 8-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-1980 upto and inclusive of the 26-11-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time t_{Ω} time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premis, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immedia ely enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Groups Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Insia as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|23|82-PF. II(SS. II)]

का. मा. 2717. — मसर्स पाजरा गियस पाइवट सि., स्टेशन रोड, वेनास, मध्य प्रदेश— 455001 (ए. बी./902) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्था-पत्त कहा गया है) ने कर्मबारो अविध्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की जपधारा (2क) के प्रधीन छूट विए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक श्रीभवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो कोग्रदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन कायदों से श्रीधक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निश्रेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रीम अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की लपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त गर्लियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिसुवना संख्या का. भा. 2313 तारीच 6-5-1983 के मनु-सरण में और इससे जपाबद प्रमुखी में विनिधिष्ट शतों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्वापन को, 21-5-1985 से तीन वर्ष की प्रविध के लिए जिसमें 20-5-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से सुद्ध देती है।

प्रमृश्ची

- अक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक शविष्य निर्धि प्रायुक्त
 मध्यप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तका
 निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समयसमय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीकण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्बाध करेता आं केम्ब्रीय सरकार; उक्त मधिनियम की बारा 17 की जप-धारा (3क) के खण्ड (क) के मधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सानृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्भत लेखाओं का रखा। जाना, विवर्णाणमें का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का सन्दाय, सेखाओं का प्रन्तरण, किशिषण प्रभारों का सन्दाय धादि भी है, होने वाले सभी क्यायों का बहुन निशेजक द्वारा किया जाएगा।
- 4.. नियोजन, केन्द्रीय संग्कार द्वारा यथा सनुमोदित सामृहिक वीमा इक्कीय-के निकर्मीकी एक प्रति, धीर अध ककी समने संबोधन किया जाए,

- त**व** नसं संशोधाः की प्रति संधा कर्मनारियों की ्युमंख्या कः आया में असको मुख्य वार्षों का प्रभुतः इ.स्थापन के सुचनाः पर्ट पर शदिति करेते ।
- 5. यदि कोई ऐसा कांचारी, जो कर्ननारी ५,विष्य त्निध का या जन्म मिनियम के मधीन धूट प्राप्त फिसी स्थापन की सिविय निधि का यहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक मामूहिक बीमा स्कीम के सरस्य के रूप में उपक्रा जीम तुरस्य दर्ज करेगा और उसकी बाबत भावण्य ह प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सस्थत करेगा।
- 6. यदि संसृष्टिक बीता स्कीम के ब्रधीन कर्नवारियों की उपलब्ध फायरे बडाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के ब्रधीन कर्नवारियों की उपनब्ध फायदों में समुचिन का में बुद्धि की जाने कर ध्यानक्या हरेगा जिससे कि हर्नबारियों ह निर्माहिक बीना स्कीम के ब्रधीन फायने उन फायदों ते ब्रधिक ब्रमुकून हों, जो उक्त स्कीम के ब्रधीन ब्रमुकेय हैं।
- 7. सामूहित बीमा स्काम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रवीन सब्देग रकम उस रकम के से कम है जो कर्मवारी को उस दशा में सन्देग होती जब वह उक्त स्कीम के प्रवीन होना तो, नियोग क कर्मवारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिकी की प्रतिकर के क्य में बोनों रकमों के प्रस्तर के बरागर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहित स्कीम के उपवन्धों में काई भी ने गाधन, प्रावेशिक भविष्य निर्धे मामूक मध्य प्रवेश के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्राधिक भविष्य निश्चित्रायुक्त, प्रपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भवना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त भवसर देगा।
- 9. यदि िहती कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमां स्कीम के, जिसे स्थापन पहले धपना चुका है, प्रधीन नहीं पह जाते हैं, भा इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होते बाले फाय: किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रह्द की जा सकती है।
- 10. यदि, किसी कारणवश्च, नियोजक भारतीय जोवन बीमा निगम द्वारा नियत अपरीक के भीतर प्रीमियम का सन्याय करन में श्रमकत रहता है, और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रा्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किनो व्यतिक्रम दशा में, उन भूत सदस्यों के नामनिर्देशितियां या विश्विक लारिसों की जी यदि यह, छूट न दी गई होता तो उक्त स्कीम के श्रवार्गत होने, बोमा फायबों के सन्दाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के झाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिवेंशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्ताय तत्परता से और प्रत्येक बणा में प्रर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिष्यित करेगा।

[संच्या एस-35014(30)/82/पी, एफ-2/एस, एस-2]

S.O. 2717.—Whereas Messrs. Gajra Gears Private Limited, Station Road, Dewas, Madhya Pradesh-455001 (MP|902) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corpo ation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Minstry of Labour, S.O. 2313 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-5-1985 upto and inclusive of the 20-5-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhva Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Institute Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance prema, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a memoer of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to available to the employees under the said Scheme are henefits available under the Group Insurance available under the Group Insurance so that the benefits available under the Group Insurance so that the henefits available under the more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstan ling anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employee shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[30]82-PF. II(SS. II)]

का. शा. 27)8. — मैमर्स गोयद्राज (इन्डिया) लि., तेज बिल्डिंग, बहातुरलाह जकर मार्ग, हुई दिल्ली (बी. एल. /743) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबाध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) भी धारा 17 भी उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अपवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म बरी किसी पृथक अधिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के ध्वीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा २१ है वे ऐसे कर्म बारियों को उन फायदों से घछिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्म बारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम, 1-73 (िंट इसमें इसके प्रश्वात् उक्त स्कीम कहा गया है)के अवान अनुनेय है ।

यतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिविनयम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंजालय की ग्रिविस्था संख्या का ग्रा. 3035 तारीक्ष 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपायद अनुसूची में विनिद्धित शर्तों के श्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वय की ग्रविध के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

छनस ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निष्ठि भ्रायक्त विल्लो को ऐसी विवर्णियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुनिधां प्रदान करेगा जो केंग्ब्रीय सरकार समय समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समान्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उप-घारा (3क) के खण्ड (क) के ग्रिधीन समय-समय पर निर्दिग्ट करे
- 3. सापृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके ग्रन्तर्गत लेखाओं का रस्ता जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्वाय लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृत्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कमचारी भविष्य निधि का या उक्तं ग्रिधिनियम के ग्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सथस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है हो नियोजक सम्बृहिक बीगा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम गुरस्त वर्ज करेगा

भीर उसकी बाबत क्षावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सम्बल करेगा।

- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मधारियों को जपलब्ध फायदे बढ़ाये जाने हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिम-से कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदां से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृथ्यू पर इस स्कीम के ध्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारा भी उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के ध्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के क्य में दोनों रकमों के ध्रश्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिकष्य निधि भ्रायुक्त, देहली के पूर्व भ्रतुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और भही किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रिकृत प्रभाव पक्षने की संभावना हो बहा, प्रावेशिक, भविष्य निधि भ्रायुक्त, भपना ध्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृद्धिक बीमा स्कीम वें, जिसे स्थापन पहले अपना जुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीस के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्भ की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारजवण, निवोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के मीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है सो छूट रद्व की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीसिपम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामिवेंशिनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम ने शन्तर्गत होते, बीमा फायतों के सन्दाप का उत्तरदाधिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस रकांभ के छ्रधीन श्राने वाने किसी सदस्य भी मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीभा निगम, बीभाकृत राणि के हकदार नामनिर्वेशिती/ विधिक वारिसी को उस राणि का सन्दाय तत्परना से और प्रत्येक दशा में इर प्रकार से पूर्ण दावे की प्रान्ति के एक मास के भीतर सुनिन्तित करेगा।

|मंख्या एम-35014(52)/82/पी.एफ.-2/एस.एस-2]

_S.O. 2718.—Whereas Messrs, Goetge (India) Linkted, Tel Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 (DL 743) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employers than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinster referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of rection 47 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3035 dated the 17-8-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed

hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8 1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the henefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an engloyee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirhominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure profiffed payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in

any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|52|82-PF. II(SS. II)]

का. धा. 2719.— भैसर्स न्यू कोरोक मिल्स की-भाषरेटिव कर्जुमर्स सोसाइटी लि., नावेज (जी. जे./4823) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए भावेदन किया है;

और केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म नारी किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमिय का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्मीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायवा उठा रहे हैं ऐसे कर्म नारियों को उन कायदों से प्रधिक धनुकूल हैं जो उन्हें कर्मथारी निक्षेप सहब्य बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन धनुक्रेय हैं;

घत: केन्द्रीय सरकार, उक्त धिंतियम की धारा 17 की उपधारा (क्ष2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भीम भंजालय की धिंससूनना संख्या का. धा. 3039 तारीखा 17-8-32 के धनुसरण में और इससे उपाबद्ध धनुसूची में निर्निदिष्ट गर्तों के धर्धान रहते हुए उक्त स्थापन की, 28-8-1985 से तीन वर्ष की धवांध के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मितित हैं, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से खूट देती हैं।

प्रमुख्यो

- उक्न स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भजेगा और ऐसे शेख रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निविध्ट करें ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समान्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करेगा जी केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के प्रवीत समय-समय पर निविष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भन्तर्गत लेखाओं का एखा जाना, विवर्णणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रनारीं का संवाय भाषि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा सथा घामोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब क्रमी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मबारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐमा कर्मनारी, जो कर्मनारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन खूट प्राप्त किसी स्थापन भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुप्त्त करेगा और उसकी बाबत ग्रावयका प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के घर्धान कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के घर्धान कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों मे समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन फायदों से घर्धिक धनूकूल हों, जो उक्त स्कीम के घर्धीन घनुक्रेय हैं।
 555 GI|86—10.

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मबारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मबारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मबारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपवधों में कोई भी संधोधन प्रावेशिक भविष्य निधि भागुक्त गुजरात के पूर्व भनुभोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कमंचारियों के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि भागुक्त भगना भनुभोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को भगना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन कीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीप्ति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवार, नियोजक क्षारतीय जावन बामा निगम द्वारा नियत तारीख के मीतर प्रीमियम का संवाय करने में ध्रमफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवास में किए गए किसी व्यक्तिकम की वशा में, उन मृत सवस्यों के नामनिर्वेशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायवों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के घंधीन घाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन नीम निगम, नीमाहत राशि के हकवार भामनिर्देशित /विधिक नारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में हर प्रकार से पूर्ण दाने की प्राप्ति के एक मास भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संस्था एस-35014/82/84-पीएफ- :/एस एस-2]

S.O. 2719.—Whereas Messrs New Shorock Mills Co-operative Consumers Society Limited, Nadiad (GJ|4823) (he cinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3039 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1981.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment—shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Gularat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Guarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to now the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Cornoration of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is lightly to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corroration of India shall ensure prompt navment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014!84|82-PF. U(SS. II)]

का. घा. 2720: मेमर्ग सावरमांचा डिस्टिक कोआपरेटिव मिल्क प्रोडय्सर्म यश्यत लि. (सावर हैरी) हिस्मतनगर (जे. जी./3558) (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपस्थ्य प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मेंचारी किसी गुथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के कप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मवारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मवारी निर्मेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (िशे इसमें दसके पश्चान् उन्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुकेष।

श्रतः केन्द्रीय भरपार, उक्त श्रविनियम की श्रारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त मिल्यों का प्रयोग करते हुए भारत स्वकार की श्रम मंत्रालय की श्रिष्मसूचना संख्या का. श्रा. 3044 तारीख 17-8-1982 के मनुमरण में और इसके उपावद श्रनुमूची में विनिद्धिट मर्तों के श्रवीन रहते हुए उक्त स्थापन की, 28-8-1985 में तीन वर्ष की श्रविष के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के समी उपबन्धों के प्रवर्तन में सूट देती है।

पनसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोधक प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त गुअरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरिक्षण के लिए ऐसी मुविष्ठाएं प्रवान करेगा को कैक्ट्रिय सरकार समय-समय पर निर्दिश्ट करें।
- 2. नियोअक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रस्पेक मास की समापित को 15 दिन के भीक्षर संदाय करेगा जो केन्द्रीय रास्कार, उकत प्रधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) को खण्डा (क) को प्रधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. साथूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुस किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रशारों का संदाय प्रावि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रनुमीदिल सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन विध्या जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मत्रारियों की बहुपंत्रमा की भाषा में उसकी सुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन से सुधनाषट्ट पर प्रदेशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा फर्मनारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रश्नीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक योमा स्थीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सबस करेगा।
- 6. प्रदि मानूहिक बीमा स्काम के प्रजीन कर्मबारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं तो, नियंत्रक उक्त स्कीम के प्रजीन कर्मबारियों को उपलब्ध फायवों में अमुखित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मधारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपनव्ध फायवे उन फायदों से प्रशिक प्रतुक्त हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रवजिय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में थिसी बात के होते हुए मी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इक्ष स्कीम के अधीन संदेय रक्षा उस रकम से कम है जो कर्नचारी की उस दला में संदेय होती अब वह उक्स स्कीम के अधीन होता तां, नियोजक कर्मचारी के बिधिक घारिस/नामनिर्देशिती का प्रतिकर के क्य में दोनों रक्षमों के ब्रन्टर के ब्राह्म राम्म का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिष स्कीभ के उपवंधों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात से पूर्व अनुमोदन के विशा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि मायुक्त, प्रपत्ता असुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपत्ता बुव्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर वेगा।

- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मभारी, भारतीय जोवन बीमा निगम की उस भामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना भुका है, अर्धान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्धान कर्मगारियों की प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि फिसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत नारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में अशकल रहता हैं और पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियाणक द्वारा प्रीमियम के संबाय में किए गए किसी क्यतिक्रम की वंशा में, उन भृत सथस्यों के नामितिर्देशितियों या विधिक बारिसों की जो यदि यह, छूट न दा गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12 इस स्काम के अधीन जाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि -क हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसीं को उस राशि का सदाय सत्परता से और प्रत्येक दणा में हर अकार से पूर्ण दावे का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।
 - [स. एस-35014/97/82-पेर. एक.-2/एस. एस.-2]
- S.O. 2720.—Whereas M|s. Sabarkantha District Cooperative Mills Products Union Limited, (Sabar Dairy), Himatnagar (GJ|3558) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3044 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause(a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

- his establishment, the employer shall, immediately emol him as a member of the Oroup Insurance someone and pay necessary premium in respect of him to the Life misurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioer, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|97|82-PF. U(SS.II)]

का. आ. 1721 — मैंसर्स पांडीचेरी डिस्टिलरीज, गोऊवर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी (पी. सी./26) (जिसे इन्जें इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इतमें इसके पश्चान् उकत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अधिदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गता है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय था प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्थाम की मामूहिक बीमा स्थीम के अक्षीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्थीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त स्कीम कहा गया है) के अवीम अनुजेय हैं;

अत: केन्द्रीय परकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त प्राक्तियों का प्रयोग करने हुए धीर भारन सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3724 लारीख 11-10-82 के अनुसरण में और इससे उपादक अनुसूची में विनिध्चिट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की. 30-10-1985 से तीन वर्षे की अविध के लिए जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से कुट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक शिवष्य निधि आयुक्त तमिल नाडू को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा लया निराक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का मत्येक मास की समाध्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार, उक्त अग्निनयम की घारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अग्नीम समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी क्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिल सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाब, स्थापन के सुचना पट्टूपर प्रविश्वि करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिक्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्य दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधी "चारियों को उपलब्ध फायदों में सामूजित रूप से वृद्धि की जाने की ध्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृष हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृष हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृष हों
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मनारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवैय रकम उस रकम से कम है जो कर्मनारी को उस दशा में संवैय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मनारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई की संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तिमलनाडू के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रति कूल प्रभाव पड़ने की संभावना हों वहां, प्रावेशिक मिवष्य निधि आयुक्त अवना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारण वशा, स्थापन के कर्मवारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बोमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुका है, अभीन नहीं रह जासे हैं, या इस स्कीम के अभीन कर्मवारियों को प्राप्त होने वासे फायदे किसी रीति से कम होजाते हैं को यह खूट रब्ब की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को अपपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किय गए किसी अ्यतिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामिनिर्शितियों या विधिक वारिसों को

- ओ यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन लीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिवंशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से भीर प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा:
 - [सं. एस.-35014/123/82-पंr. एफ.-2/एस. एस.-2]
- S.O. 2721.—Whereas Messrs. Pondicherry Distillerles, Goubert Avenue, Pondicherry (PC|26) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such ensployees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3724 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

(No. S-35014]123[82-PF. II(SS.II)]

का. धा. 2722:—मैसर्स इम्बोलोबनबराऊ ब्रेवरीज लिमिटि इ. 13/1 मबुरा रोड, फरीवाबाद (हरियाणा) (पी.एन. 4913) (जिसे इसमें इमके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविषय निधि धौर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 मा 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क (1) के अधोन छूट दिये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

ग्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है. कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी प्रथक धिमदाय या प्रीमियम का संदाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं ग्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से भ्रधिक धनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके प्रश्नात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्षेय हैं।

मतः केन्द्रीय सरकार, उन्त भिवितयम की धारा 17 की उपधारा (2क) धारा प्रवक्त भिवतयों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबद्ध भनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के भधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की भविष के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से छट देती है।

मनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त, फरीवाबाद को ऐसी निवरणियां भेजेगा बीर ऐसे लेखा रखेगा । तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड क के प्रधीन समय-लमय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणसन में, जिसके धन्सर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय धादि भी है, होने वासे सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया आएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा भनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का भनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मबारी थो कर्मधारी धविष्य निधि का या उज्जत प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा ग्रीर उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदश्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के भ्राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं तो. नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्राधीन कर्मधारियों को उपलब्ध फायदों में समु चित हुए से बद्धि किये जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के भ्राधीन उपलब्ध फायवें उन फायदों से भ्राधिक भ्रानुकूल हो जो उक्त स्कीम के भ्राधीन अनुक्षेप की मुन्तेय है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मजारी की मत्यू पर इस स्कीम के घ्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मजारी को उस दणा में संदेय होता है वह उस्त स्कीम के घ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मजारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में बोनों रकमों के भन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई घी संशोधन प्रावेतिक भविष्य निधि प्रायुक्त फरीदाबाद के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया उत्तरणा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संमावना हो, वता प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त प्रपता प्रमुमोदन देते समय पूर्व कर्मचारियों को धपना दिस्टकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त आवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी मारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, 'जिसे स्थापन पहले प्रपता चुका है प्रधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त फोने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह घूट रह की जा सकती है ।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत सारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निर्णम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रमफल रहता है भीर पलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सबस्यों के नाम निर्वेशितियों या विश्विक बारिसों द्वा को जो यदि रह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायबों के संवाय का उत्तर वायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन धाने। बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकतार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से भौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संबंधा एस-35014/196/86-एस-एस.-2]]

S.O. 2722.—Whereas Messrs. Indo Lowenoran Brewerles Limited, 13/I Mathura Road, Faridabad (Haryana) (PN/4913) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, whitout making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of premium, and enjoyment of premium and the Group finantance Scheme of the Life Institute Computation of the listing in the nature of the institute which are more favourable to such employees than the benchts admissible under the employees than the benchts admissible under the employees begond miked insurance Scheme, 1970 (hereinarter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 1/ of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Covernment hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Fandabad and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amenced, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Reigonal Provident Fund Commissioner, Faridabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adonted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assyrance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the

said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|196|86(SS.II)]

का था 2723. — मैससं विल्ली स्टेट इंटस्ट्रियल हिंबलपमें ट कारपोरेणन लि. एन ब्लाक, बस्बई लाईन विल्डिंग, कताट सकैन नई दिल्ली (की.एस. 3277) (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्व निधि श्रीर प्रजीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उका श्रिधिनियम कहा गया है) की श्रास 17 की उपधारा 2फ के श्रिधीन शृह विसे आने के लिए श्रामेदन जिला है।

श्रीर केन्द्रीय मण्यार का सवाधान हो नहा है कि उत्त स्थारा के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीवदाय मार्श्वाचित्रक हा मंदाय किये जिना ही, भारतीय श्रीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे है श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों ने अधिक धनुकृत है शो अर्मचारी निक्षेप सञ्ज्ञ बीमा स्कीम, 1976 (जिसे क्ष्मों प्रकृत प्रकृत स्कीम कहा गया है) के स्रधीन उन्हें श्रनुक्रीय है।

प्रतः केन्द्रीय भरकार उत्तर घितियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपावद्ध प्रत्नुसूची में विनिर्दिष्ट जर्ती के अधीन रही हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उत्रवस्थों के प्रवर्तन से छूट देती है।

यन्स् वी

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगक प्रादेशिक पविष्य निधि प्रायुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवास करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्धिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसं निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड क के प्रधीत समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीभ के प्रशासन में, जिनके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का प्रन्तरण निरीक्षण प्रभारों संवाय यादि भी है, होने वाले मभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के निथमों की एक प्रति धोर जब कभी उनमें संगोधन किया आये, तब उस मंगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुबाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारों जो कर्शवारों भविष्य निधि का या उस्त चिवित्यम के चधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही नवस्य है, उसके स्थापन में नियंजित किया जाता है तो, नियोज के सामृष्टिक बीमा स्कीम के सदस्य के द्वार में उसका नाम हुएत्त वर्ष करेगा और उसकी बाबत आवश्यक श्रीमियन भारतीय जीवत बीमा निगम को संदन्त करेगा।
- 6. गदि उक्त स्कीम के प्रश्नीन कर्यचारियों को उपनब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक थोमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारयों को उपलब्ध फायदों में समुचित कप से बद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा

जिनक्षे कि कर्मवारियों के लग् नामृहिक वीमा स्कीम **के अधी**न उत्तरूप कार्यदे एक कायदों से अधिक अनुकृष हो <mark>जो उसन स्कीम के</mark> अधीन अनुजेस है।

- 7. साम्हिक जीवा स्हीम में किसी बात के होते हुए भी यदि हिसी कार्यवारी की मृत्यु पर इव स्कीम के व्यक्षित अवेय रक्षम उच स्कम से फन है जो कर्मचारी को इस दबा में संदय होती जब वह उक्त स्वीम के प्रवीत होता तो, नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रविक्षण के यद में धीनीं रक्षमी के प्रवार के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- ह. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, दिल्ली के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने का संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त स्थाना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रमना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का संस्तयक्त इत्तमर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृत्कि बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले भ्रपता चुका है प्रधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भासकल रहता है और पालिसी को व्यवगत हो जाते दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 1: नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक विशित्सों को जो यदियह छूट न दी गई होता तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायवीं के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के श्रधीन धाने वाले किसी सदस्य की भृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाइन्त रक्षम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन्त रक्षम प्राप्त हाने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(197)/86-एस-एस-2]

S.O. 2723.—Whereas Messrs. Delhi State Industrial Development Corporation Limited, N-Block, Bombay Life Building, Connaught Circus, New Delhi-110001 (DL|3277) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-

- missioner, Delhi, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exempion shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the assurance benefits to the nominees or the legal heirs of Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in assurance benefits to the nominees or the legal heirs of payment of premium the responsibility for payment of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INo. S-35014[197[86-(SS.H)]

का.ग्रा. 2724 .---मैसर्ज श्री प्रकाश टैनस्टाइत्स (गुजरात) प्रा लि. लक्ष्मी विजय होजरी मिल्ज कम्पाऊस्ड, नरीदा रोड, झहमदाबाव 380025 (जी. जि/2644) (जिसे इसमें इसके पण्चात उनन स्थागक्ष-कहा गया है) ने कमेचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपजन्त स्थिमियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात उनन श्रीविषयम कहा

गया है) की बारा 17 की उपबारा (2क) के ब्राबीन छूट दियें जाने के किए कायेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उबत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक धृभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये विमा ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मधारी निकेष सहबय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के स्रधीन उन्हें सनुक्रेय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारो 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनुसूची में विशिद्धिय शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवधों के प्रवर्तन से छूट वेती

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि ायुक्त, गुजरात को एँसी विषरणियां मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविद्याएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा थी केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्डुक के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गतः लेखाओं का रखा जाना, विधरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमिथम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा विया जाएगा ।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्वापन के सूचना पट्ट पर प्रवक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मगारी मिविष्य निश्चि का या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अविष्य निश्चि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मधारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मधारियों को उपलब्ध फायदों में समृधित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मधारियों के लिए सामृहिक थीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उम फायदों से अधिक अनुकृत हो जो उनत स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मबारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मबारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मज़री के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिसी को प्रतिकर के क्य में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई घी संबोधन प्रादेशिक श्रीक्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व धनुमोदन के बिका नहीं किया जाएका और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने

- की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त ग्रथना ग्रनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवास स्थापन के कर्नवारी भारतीय जीवन वीमा निगम की उस सामृहिक वीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवज्ञ नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, खूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियन के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सवस्यों के नाम निर्वेषितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट म वी गई होती तो, उक्त स्कीम के ग्रस्तर्गत होते बीमा फायवों के संवाय का उत्तरवाधिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. उसत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन श्राने वाले किसी सबस्य की मृत्यु हीने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रस्पेक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014 (198)/86-एस. एस-2]

S.O. 2724.—Whereas Messrs. Shree Parkash Textiles (Gujarat) Private Limited, Laxmivijay Hoslery Mills Compound, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/2644) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedulg annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|198|86 (S.S.ID]

कावआंव 2725.—मैसर्स मुजाल गेजीज, जीवटी रोड, (हिरो नगर), लुसियाना-141003, (पीवएनव/2539) (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचःरी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के सधीन छूट दिये जाने के लिये सावेदन किया है।

भीर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उन्ति स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभियाय अधिनियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के भाषीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए से फायदे उन फायदों से प्रधिक भनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के सधीन उन्हें अनुजेय हैं।

धतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा-2 को द्वारा प्रयक्त मक्तियों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपाधक भनुसूची में विनिद्धित मतों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तील वर्ष की धविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

प्रनुसूची

 उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विदर्गियां मेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 555 GI|86—11

- के लिए ऐसी मुर्विधार्ये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के मीतर संवाय करेगा जो कैन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया ज्याना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय भावि भी है, होने बाले सभी अपयों का अहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदिश सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का धनुबाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रविश्वत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी मित्रप्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भित्रष्य निधि का पहले सदस्य हैं उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सागृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरत्त वर्ज करेगा और उसकी बावन प्राययक प्रीमियम भारतीय जीयन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यिव उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायवे बक्रायें जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मवारियों को उप-लब्ध फायदों में समृजित रूप से बिद्ध किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायवे उन से ग्रधिक ग्रमुकूल हो जो उक्त स्कीम के ग्रधीन ग्रमुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मकारी की मृथ्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मकारी को उस दक्ता में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मकारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दौनों रक्तमों के प्रस्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भिष्य निधि भायुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व धनुमोदन के बिमा नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भिष्य निधि आयुक्त भपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रयना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त धवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा मगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले घपना चुका है भ्रष्ठीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भ्रष्ठीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदै किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह खुद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस नियस सारी के भीतर जो भारतीय जीवन भीमा नियम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में भारकल रहता है भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने वियाजाता है तो, छूट रहद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकक्ष की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के धन्तर्गत होते। बीमा फायबों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्राचीन झाने याले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से झौर प्रश्येक

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्रुत रकम प्राप्त होने के एक नास के भीतर सुनिश्चत करेगा।

[सच्या एस-35014(199) 86-एस.एस.-2]

S.O. 2725.—Whereas Messrs. Munjal Gases, G. T. Road (Hero Nagar), Luchiana-141003 (PN/2530) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/199/86-(8S.II)]

का. घा. 2726. — मैसर्स पंजाब एसो इन्डिस्ट्रीज कार्पोशन लि.एस.सी. श्री. नं. 315-16, सैक्टर-35-बी, चण्डीगढ़(पी.एन./2827) (जिसे इसमें इसके परचात उक्त स्थपान कहा गया है)ने कर्मेचारी भविष्य निधि श्रीर प्रकीण उपबन्ध श्रक्षित्रियम 1952(1952 का 19)(जिसे इसमें इसके परचात उक्त अधिनियम किहा गया है)की धारा 17 की उपधारा (2क)के श्रधीन छूट दिये जाने के लिए शाबेदन किया है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीभदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे श्रधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहब्रख बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है)के श्रधीम उन्हें श्रीमुहीय हैं।

धतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 क द्वारा प्रवत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए, घौर इससे उपबाद धनुसूची में विनिर्विष्ट गर्नों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तोन वर्ष की घषधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्म से छूट देती है।

अनसची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त
 भण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां मेंजेगा घौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण
 के लिए ऐसी मुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर
 निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके मन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, जिवरणियों का प्रम्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्राप्त भी है, होने वाले सभी क्यों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा घनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति जब कभी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भावा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद स्थापन के सुवना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- यदि कोई ऐसा कर्मणारी जो कर्मणारी भविषय निधि का या उक्त ग्राधिनियम के ग्राधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा धौर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा ।

- 6. यदि उक्त स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाये जासे हैं। तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध का-यदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक प्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्तेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम स कम है जो कर्मचारी को उस दया में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीम होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक भीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सकोधन प्रादेशिक भिक्य निधि भागुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भागुक्त भपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्ति गुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणयग स्थापन के कर्मकारी भारतीय जीवन बोमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले मपना कुका है मधीन नहीं यह जाता है या इस स्कीम के प्रधीन कर्मकारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीर्ति से कम हो जाते हैं, तो यह खुद की जा , सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, को भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में श्रमफल रहता है श्रीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सदाय में कियं गये प्रिक्तिता है व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते बीमा कायदों के संदाय का उस्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाक्षत रकम का संदाय तत्परता से धीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीसर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(200)/86-एस.एस-2]

5.O. 2726.—Whereas Messrs. Punjab Agro Industrics Corporation Limited, SCO No. 315-16, Sector 35-B, Chandigarh (PN]2827) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to us the said Act);

And whereas, the Central Governmen, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corpn, of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heremafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by emb-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall suomit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarn and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Covernment may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- the establishment, a copy of the rules of the Group Insulation as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exemped under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol ... a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the permium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee

or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|200|86(SS II)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1986

का. द्या. 2727:—मैसर्स रीटा मैकैनिकल वकसं, 416, इण्ड-स्ट्रीयल एरिया-ए, लुधियाना (पंजाब) (पी एन./167) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिषय्य निधि भीर प्रकीर्ण जपबन्य प्रधिनियम, 1952(19का 1952) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की अपधारा 2क के ध्रधीन खुट विथे जाने के लिए ध्रायेवन किया है;

शीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे जन फायदों से भाधिक भनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इन्नमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुन्नेय हैं;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रमोग करते हुए घोर इससे उपावक धनुमूची में विनिधिष्ट शर्तों के घंधीन रहते हुए, तक्त स्थापन को तीम वर्ष की प्रविधि के लिए तक्त स्कीम के सभी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट देशी है।

सनुसुवी

- 1 उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निश्चि धायुक्त, जंडीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेंगा भीर ऐसे केसा रखेंगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केखीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के धर्घान समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके मंसर्गत लेखामों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखामों का अन्तरण, निरंक्षण प्रभारों संवाय प्रावि है, होने बाले समी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा किम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में ससकी मुख्य बानों का अनुबाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी घिषण्य निधि का या जनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजिंग किया जाता है तो, नियोजिंक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरुक्त वर्ज करेगा और उसकी बांबत आवश्यक प्रीमिथम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6 यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपसम्ब फायदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियाजन सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उनत रकीम के अधीन अनुकेश हैं।
- 7 सामृहिक कीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मबारी को मृत्यू पर इस स्कीम के भर्मान संदेय दक्षम उस रक्षम से कम है जो जो कर्मबारी की उस दक्षा में संदेय होती जब वह उपत स्कीम के भ्रमीन होता तो, नियोजक कर्मबारी के विश्विक बारिस/माम निर्देशिती

को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के ग्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा सर्क म के उपयन्थीं में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त, चंडींगढ़ के पूर्व अनुमोदम के बिना मही किया जाएगा भौर जहां किमीं संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य किछ भ्रायुक्त भपमा भनुमोदम देने से पूर्व कर्मचारियों की धपन। दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्नकार भारतीय जीवन बीभा निर्माम की उस सामूहिक बीमा स्थीम में, जिसे स्थापन पहले घपना चुका है घडीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम में घडीन कर्मधारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह २६ की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियांजक उस नियस तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भमकल रहता है और पालिसो को व्यवगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक म की दशा में उस मृत सदस्यों के नाम सिंशितियों या विधिक वास्सि। की जो यदि यह छूट न दो गई होती तो, उनत स्कं.म के फन्तात हीते बीमा कायदों के संदाय का उत्तरदायिस्य नियोजक पर होगा।
- 12. जबत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधिम भाने वाले किसी सबस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशितियों/ विधिक वारिसों को वीभाकृत रकम का संवाय तत्परता से भीर प्रत्येक वणा में भारतीय जीवन बामा नियम से वीभाकृत रकम प्रात होने के एक मास के कीतर सुनिश्चित करेगा।

[संबत एस.-35014 (201)/86- एस. एस. -**Ш**]

New Delhi, the 21st July, 1986

S.O. 2727.—Whereas Messrs. Rita Mechanical, 416, Industrial Area-A, Ludhlana, (Punjab) (PN|167) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is saisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government necessity even; is the said establishment from the operation of all the provisings of the said Scheme for a pariod of three years.

- 1. The employer in relation to the sait establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for the tion as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall ray such name tion charges as the Central Government may, from time to time, direct ander clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the rominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|201|86(SSII)]

का. ग्रा. 2728 — मैसर्स मोपेड इन्डिया लिमिटेड, रेनी गुनता रोड, नेटोपली, पोस्ट, लिपित-517506 (ग्राम्ध्र प्रदेश)(ए पी/2824) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवस्थ संजिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त श्रीविन्यम कहा गया है) की बारा 17 की उपवारा (2क) के संधीन कुट विये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मवारी, किसी पथक स्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बोमा स्कीम के बाबीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मनारियों के लिए ये फायवे उन फायबों से भाधिक अनुकूल हैं जो कर्मनारी मिकीप सहबद्ध बीभा स्कीम, 1976) (जिसे इसमें इसके पश्चात उवत रकाम कहा गया है) के बाबीन उन्हे अनुजीय हैं।

भतः भैन्द्रीय सरकार, उक्त भिनियम कः धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबद्ध भनुसूची में विनिधिष्ट मतौं के भधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्रनुमुखी

- गुज्यस स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, भान्त्र प्रदेश को ऐसी विषरणियां भेजेगा धीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. निर्याजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के प्रधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके घट्तगंत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का घन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय छादि भी है, होने नाने सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमंदित सामूहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जासे, तथ उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुबाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मवारी भिष्ठिय निधि का या जबस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की मिष्ठिय निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्स दर्ज करेगा भौर उसकी बाबत भावक्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचिरियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं, सो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचिरियों को उपलब्ध फायदों में समृदित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचिरियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूष हो जो उक्त स्कीम के अधीन अपीन अनुकूष हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूष हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूष हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उबत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोमों रकमों के प्रन्तर के वराधर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संघोधन प्रावेशिक धीषण्य निथि प्रायुक्त, प्रान्ध्य प्रदेश के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संघोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त प्रपना प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।

9. यदि किसी करणवश स्थापन के कर्मजारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है भ्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने बाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।

10. यांव किसी कारणवण नियोभक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे; प्रीभियम का संदाय करने में यसकत रहा है भीर पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

- 11- नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किसे गर्ये किसी व्यक्तिकम को वसा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विश्विक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बोमा फायवों के सदाय का उत्तरवायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियाजन इस स्कीम के प्रधीन माने वाल किसी सदस्य की मृत्यु होन पर उसक हकदार नाम निदीशांतयां/ विधिक निरिसों का बानाकृत रकम का सदाय तत्परता स म्रीर प्रत्येक देशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बानाकृत रकम प्राप्त होने क एक मास क भीतर मुनिश्चित करगा।

[संख्या एस-35014(202)/86-एस एस-2]

S.O. 2728.—Whereas Messrs. Mopeds India Limited, Renigunta Road, Settipalli Post, Tirupati-517506 (Andhra Pradesh) (AP[2824] (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is saitsfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Incia in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features hereof, in the language of he majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed

- in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014 202 86 (SS-II)]

का.धा. 2729.— मैसर्स करीम केटररज, वसीरवाग, हैदराबाद 500029 (ए.पी./6320) (जिसे इसमें इसके पण्यात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रिविनयम, 1952) 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्यात उक्त प्रधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारों (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए प्रावेदन किया है।

ग्रीर केस्त्रीय सरकार का समाधान हो गर्मा है कि उक्स स्वापन के कर्मजारी, किसी पृथक ग्रामेवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा मिगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मजारियों के लिए ये फायदे उन पायवों से भश्चिक ग्रनुकूल हैं जो कर्मजारी निक्षेप महत्वद्व बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें ग्रनुकेय हैं।

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उनत घष्ठिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबद्ध धनु-सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उनत स्थापन को तीम वर्ष की भवधि के लिए उनत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्त्तन से छूट देती है।

घनुनुनी

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेणिक भविष्य निधि सामुक्त, श्रान्ध श्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा सौर ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवास करेंगा जो केन्द्रीय सरकिर समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कैन्द्रीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के ग्राधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. साभूहिक धीमा स्कीम के प्रणासन में, जियके ग्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, धीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय घावि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा विधा जायेगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमीवित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संबोधन किया जाये, तब उस संबोधन की प्रति सया कर्मच।रियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बासों का प्रनुषाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रविशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी जो कर्मकारी पिवाय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ती, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये आते हैं तो, नियौजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायवें उन फायवों से प्रधिक प्रमृक्त्य हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमृक्तिय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेय रकम उस रकम मे कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संवेय होती जब वह उकत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम-निर्वेषिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के घन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीमं के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक शिवध्य निधि ग्रायुक्त, शास्त्र प्रवेश के पूर्व मनुमोदन के बिना महीं किया जाएगा ग्रीर जहाँ किसी संशोधन से किमीनारियों के हित पर प्रसिक्त प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त ग्रपना; जनुमोदन देने से पूर्व कर्मजारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्वष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मकारी भारतीय जीवन श्रीमा शिशम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका हैं ग्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मेचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणविश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे; प्रीमियम का संवाय करने में धमफल रहता है धौर पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है, तो जूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजकां द्वारा प्रीमिसम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की वंगा में उन मृत सवस्यों के नाम निर्वेणितियों या विश्विक वारिसों

- को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त रथापन के सम्बन्ध में नियोजिक इस स्कीम के मधीन शाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर जलके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रस्थेक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या गस-35014(203)/86-एस एस 2]

S.O. 2729.—Whereas Messrs. Cream Caterers, Bashisbagh, Hyderabad—500029 (AP|6320) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And webereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposits Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance pretrain, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Groun Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Groun Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of

the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the henefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and In any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]203]86-SS.III

का. आ. 2730. — मैसर्स पूड, प्लांट, बीकालेर, ए यूनिट आफ राजस्थान को. भो., डेरी फैंड्रेशन लि., नियर गांधी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर (आर. जे./2904) (जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस्त स्थापन के सर्मचारी किसी पृथक भिष्ठाय या श्रीमियम का सन्ताम किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम के सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो कायवा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायबे उन कायवों से भिष्ठक भनुकून हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके हुमश्चास उक्त स्कीम कहा गया है) के भन्नीन उन्हें अनुक्षेप हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपधारा-2 क द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्स स्थापन की तीम वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

पनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक मिल्य निधि प्रायुक्त राजस्थान को ऐसी विवरिषयां भेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्स्रीय सरकार, उनत अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घरतर्गत लेखाघों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का

- सन्दाम लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दार प्रादि भी है, होने बाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बीना स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्यापन के मूचना-पट्ट पर प्रशिव करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो ियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरस्त वर्ज करेगा भीर उसकी बाबत भ्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दल करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मबारियों को उनलब्ब फायने बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मबारियों को उपलब्ध फायदों में समुबित रूप से बृद्धि की जाने की ब्यनस्य करेगा जिससे कि कर्मबारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमिक्त प्रमुक्त हों.
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मकारी को उस देशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता सो, नियोजक कर्मकारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के प्रस्तर के बरावर रक्तम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिविष्य निश्चि श्रायुक्त राजस्थान के पूर्व भनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पक्षने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त, भ्रपना कनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना वृष्टिकीय स्वष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने प्रश्ना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं, नो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यवि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता है, भीर पालिसी को व्यपनत हो जाने विया जाना है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्ताय में किए गए किसी व्यक्तिका की दशा में, उन मृत सबस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट, न वी गई होती तो उक्त स्कीम के धन्तर्गत होते.
 बीमा फायदों के सन्ताय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितयों/ विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संवाय तत्परता से भौर प्रत्येक सक्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम का संदाय प्राप्त होने भै एक मास के भीतर सुनिश्चिक करेगा।

[संख्या एस-35014 (204)/86-एम. एस-2]

S.O. 2730.—Whereas Messre. Cattle Feed Plant, Bikaner, A unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur (RJ|2904) (hereinafter referred to as the said establishment) have aplled for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintainance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respeit of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees available under the said Group Insurance Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the sald Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased rembers who would have been covered under the said Scheme but for grant of which exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme of Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month fro mthe receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|204|86(SS.II)]

का. आ...2731—मैंसर्स पिनाकिनी भ्रामीण बैंक, भी. दी. रोड, ए. की. नगर, नैलीर, आध्य प्रदेश (ए. पी./14126) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापम कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चिमीर भीर प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2 क) के अधीन छूट विये जाने के लिए आवेदन किया है।

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म-धारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भार-तीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के दप में फायदे उठा रहें हैं भौर ऐसे कर्म बारियों के लिए ये फायदे उभ फायदे से अधिक अनुकूल हैं जो कर्म चारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम गया है) के अधीन उन्हें अनुत्रेय हैं।

शत: भेन्तीय सरकार, जक्त अधिनियम की घारा 17 की उपघारा-2 क द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट मती में अधीन रहते हुए, जक्त स्थापन की तीन वर्ष की स्रविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपधन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन हैं सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक विषय निधि आयुक्त, आन्द्र प्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा धौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केखीय केट्यीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्प्रीय सरकार, उन्त प्रधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के धारीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुम नियोजक द्वारा वियाजाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जायें, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा मैं

555 GI/86-12

उसकी मुख्य वालो का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदेशित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कमंचारी जो कमंचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका भाम पुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायदे बहाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था कहंगा जिससे कि कर्म चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बास के होते हुए भी यदि किसी कर्मकारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्स स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशितों को प्रतिकर के रूप में दोगों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्म वारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवाम स्थापम को कर्मचारी भारतीय जीवन जीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10^{3} यवि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में बसफल रहता है भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है सो छूट रह की जां सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तित्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के भाम निर्देशितियों या विधिक आरिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदायका उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्तर्िस्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के घडीन धाने बालें किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के सीतर सुनिश्चित करेगा।

[संक्या एस-35014(207)/86-एस एस-2]

S.O. 2731.—Whereas Messrs. Pinakini Gameena Bank, G.T. Road, A.K. Nagar, Nellor (Andhra Pradesh) (AP|14126) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Mis-

cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refered to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grass of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-24014|207|86 (SS. II)]

का. भा. 2732.—मैसर्स श्री राम रेथान्स, भाकाण दीप, बाराखम्भा रोड़, पोस्ट बोक्स नं. 445, नई विल्ली-110001 (बी.एल/5817) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमंचारी भविष्य निधि भौर प्रकोणें उपबन्ध मधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपभारा (2क) के मधीन छूट विए जाने के लिए भावेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधन हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक घिषवाय या प्रीमियम का सन्धाय किए जिना हो, घारतीय जीवन जीमा निगम की जीवन जीमा स्कीम की सामृष्ट्रिक जीमा स्कीम के स्थीन जीवन जीमा के रूप में जो कायदा उठा रहें हैं जे ऐसे कर्मचारियों को उन कायदों से घिषक प्रमुक्त हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सह्तद्ध जीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गवा है) के घड़ीन धनुक्रैय हैं ;

मतः कैन्द्रीय सरकार, उक्त मिधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदेश प्रक्रित प्राप्ति सरकार के भ्रम मंत्रालय की भ्रधिसूचना संख्या का.मा. 2950 तारीख 4-8-1982 के मनुसरण में भीर इससे उपावय मनुसूची में विनिधिष्ट मतों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-8-1985 से तीन वर्ष की मवधि के सिए जिसमें 20-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवक्तों के प्रवर्तन से छूट देती है।

- 1. अनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक प्रविष्य निधि प्रायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां घेजेंगा धौर ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रीधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के भ्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धक्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, श्रीमा प्रोमियम का सत्वाय, श्रेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय भावि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविशत करेगा!
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भाविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका

नाम तुरन्त वर्णं करेगा झौर उसकी बाबत भावस्थक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत्त करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रमुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए शी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधीम सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब बह उक्त स्कीम के मधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्भों के मस्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक मिक्य निश्चि प्रायुक्त देहली के पूर्वप्रतुमोदन के बिता नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कममँचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रमाव पढ़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक पविषय निश्चि प्रायुक्त प्रपान प्रतृमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपान वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवर्ग, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्म वारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सक्रशय करने में प्रसफ्त रहतां है, चौर पालिसी को व्यव^{ग्}त हो जाने दिया जाता हैतो छूर रह् की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिकम की वशा में, उन भृत सबस्यों के नामिविधितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह; छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्राप्तीन प्राप्ते वाले किसी सवस्य की मृत्यू होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाइटत राशि के हकदार नामनिर्दे शिती /विधिक धारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से धीर प्रत्येक वणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014(208)/86-एस एस-2]

S.O. 2732.—Whereas Messr. Shri Ram Rayons, Akash Deep, Barakhamba Road, Post Box No. 445, New Delhi-110001 (DL/5817) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2950 dated the 4:8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule an-

pexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-8-1985 upto and inclusive of the 20-8-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee of the Legal heirs of the deceased member entitled for it and

in any lase within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]208[86(SS. II)]

कार्ज आर्ज 2735:—मैससं अधिनाय क्षेत्राटाईल लिमिटिंड गांव मोलापुर, डा॰ माहबामा चर्ण्डागड़ रोड, लुधियाना (पीं० एत्र्ण्ज / 7534) (जिसे इसमें इसके पश्चात उपत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिष्ठिय निधि श्रीर प्रकीण उपवस्त अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इनके पण्चात उपत अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

भीर केन्द्रीय रारकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवास या प्रीमियम का संदास किसे बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए से फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध दीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के मधीन उन्हें अनुश्रेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उनत अधिनियम की घारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धीर इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उनत स्वीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट बेती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक प्रविद्य निश्चि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसे विवरणिया भेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविद्यार्थे प्रदान करेगा को केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाध्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय भरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, वियरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों संवाय आवि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वार। विया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति श्रीर जब कमी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचायिों की बहुमंद्र्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुषाद स्थापन के सुखमा पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी धविष्य निधि का यह उबत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सपस्य है, उसके स्थापन में नियोजिन किया जाता है तो, नियोजन सामृष्टिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बादत आचम्यक प्रीभियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उदल स्कीम के अधीन कर्मेचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की अवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मवारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रक्षम से कम है जो कर्मवारी को उस दक्षा में संदेय होती जब बहु उक्त स्कीम के

अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक शारिस / नाम निर्देशितो की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रक्ष्य का संवाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भिविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं फिया आएगा ग्रीर जहा किसी संशोधन के कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पक्षने की संभावना हो, कहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्वष्ट करने का प्रक्रियक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारो : भारतीय जीवन बीमा . निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवस नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है भीर पालिसी की व्ययनत हो जाने दिया जाना है तो छट रहद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के माम निर्वेशितियों या विधिक्त वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उसन स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार पाम निर्वेशितियों/ विधिक बारिसों को बीमाइन रकम का संवाय तत्परता से मीर प्रत्येक थया में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन रकम प्राप्त होने के एक मास की भीतर सुनिविक्त परेगा।

सिंच्या एस-35014/206/86-एस॰एस-II]

S.O. 2733.—Whereas Messrs Adhinath Textiles Limited, (PN/7534) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub-

mission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Frovident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/206/86-(SS. II)]

का० वा० 2734:— मैंसमें वेहली इलैक्ट्रिक स्पलाई अध्यारटेकिय शिक्त सवम, मई देहली—1100002 (ही० एस०/138) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गहा है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि शौर प्रकीर्ण उपबन्ध किंतियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) में अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

घौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही, कारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के वधील जीवन बीमा के रूप में जो कायवा ग्रहा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन कायवों से अधिक अनुकृष्ट हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप

सहबक्क बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुत्रीय हैं

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत रारकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4256 तारी व्र 26-11-1982 के अनुसरण में भीन इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिद्दिट शतीं के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधिन रहते हुए उक्त स्थापन की, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवक्षों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निरिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 विन के भीतर सन्ताय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की खारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का एखा भाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का सन्दाय आवि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, कैन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीम स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कंभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति संधा कर्मजारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी, जो कर्मजारी भविष्य निधि काया उक्त बिधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापम की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नान मुस्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सम्बक्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मनारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दबा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारों के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के क्प में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्बाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त वेहुली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मश्रारियों के हिंदा पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोवन वेमे से पूर्व कर्मश्रारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का शुक्तियुक्त अवसर वेगा।
- पदि किसी कारणवस, स्थापन के कर्मकारी, भारतीय जीवन बीमा किसम की उस सामृहिक बीमा स्काम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका

- है, अधीन महीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के <mark>अधीन कर्मचारियों</mark> को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्गा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम हारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, भीर पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए पए किसी, ध्यतिकम की दशा में, उन मृत सबस्यों के नामिवर्देशितियों या विधिक धारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्रुत राशि के हकदार नामनिर्वेशिती/विधिक बारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से भीर प्रत्येक दक्षा में हर प्रकार से पूर्ण वाने की प्रास्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (257)/82/पी . एफ-2-एस . एस.-2]

S.O. 2734.—Whereas Messrs Delhi Electric Supply Undertakings, Rajghat Power House, Shakti Sadan, Delhi-110002 (DL/138) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under aub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4256 dated the 26th November, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18th December, 1985 upto and inclusive of the 17th December, 1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect udversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S, 35014/257/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 2735. — मैंसर्स जुक्तरी एयो कैमीकस्स लि., जय किसाम भवन, जुआरी नगर, गोवा (एम. एच / 9969) (जिसे इसमें इसके पक्कात उक्त स्थापक कहा गया है) ने कर्म जारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पक्काल उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आयेदन किया है;

मौर के बीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म चारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म चारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्म चारी निक्षेप सहयद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अमुझेय है,

अतः कैंन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए घीर भारत मरकार के अस मंत्रायसय की अधिसूचना संख्या का. आ. 738 तारीख 18-12 1982 के अनुसरण में घीर इससे उपायद्ध अनेंसूची में विनिर्विष्ट गर्ती के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की, 29-1-1986 से सीम वर्ष की

अवधि के लिए जिसमें 28-1-1989 भी समिस्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनु सूची

- 1. उक्त स्थापम के सम्बन्ध में नियोजक प्रविधिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां मेजेगा भीर लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवास करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समयसमय पर निविष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा रेकीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखामीं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का सन्वाय लेखामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय आवि भी है, होने भाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संगीधन किया आए, सब उस संगीधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य चातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदक्षित करेगा ।
- 5. यदि कौंद ऐसा कर्माचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्वस्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायबे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायबों में समूहित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्म वारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायबें उन फायबों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीक के अधीन होता तो नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. साम् हिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रावेशिक मिबया निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोबन के बिना नहीं किया आएगा और जहा किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वह, प्रावेशिक भविष्य निधि अयुक्त, अपना अनुमोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन भीमा निगम की उस सम्मूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कार्य द किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रख्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तरीख के भीसर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहतां है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जासकती है।

- 11. नियोजन द्वारा प्रीमियम के सत्थाय में भिए गए भिली व्यक्तिकम नी दशा में चन मृत सदयों के नामनिर्देशितियों थी विशिक्ष वारियों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उनत स्कलम के अन्तर्गत होते। नीमा कायदों के सन्धाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, कीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्वेशिती / विधिक वारिसों को उसराशि का सन्वाय तत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वाबे की प्राप्ति के एक भास के भीतर सनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (292)/82-पी. एफ-2 /एस. एस- 2]

S.O. 2735.—Whereas Mess's Zuari Agro Chemicals Limited, Jai Klssan Bhavan, Zuarinagar, Goa (MH/9969) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 738 dated the 18-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of the 28-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, us and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establisheman exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

banefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empolyee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Gommissioner, Mahatashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to inpac, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the reponsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have ben covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/292/82-PF.II(SS.II)]

का. ग्रा. 2736. मैसलं भेशनल एप्रीकल्वरण को-आपरेटिव मार्किटिंग फैंडेशन आफ इन्डिया लि., सपना बिल्डिंग, 24 ईस्ट ग्राफ कैसाश पी. जी. मं. 3580, नई विस्ती (डी एल /1507) (जिसे इसमें इसके परचाल उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी, मिक्य निश्चितीर प्रकीण उपजन्म प्रशिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचाल उक्त प्रशिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्राधीन छूट दिए जाने के लिए धारेव न किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाझान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम का सन्धाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्राचीन जीवन बीमा के रूप में जी फायवा उठा रहे हैं व ऐसे कार्मचारियों को उन फायवों से प्रक्षिक प्रमुक्त हैं जो उन्हें कर्मचारी निजेप सहबग्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्वीम कहा गया है) के प्रधीन प्रमुक्त हैं;

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, जनत प्रधिनियम की धारा 17 की उपधार (2क) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भ्रम मंत्रालय की भ्राधिमूचना संख्या का. भा. 617 तारीज 13-12-1982 के अनुसरण में और इसके उपायद भ्रनुसूची में विनिधिष्ट कर्तों के प्रधीन रहते हुए उनन स्थापन की, 22-6-1986 से तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलिस है, उनत स्कीम के राभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

ग्न**न्**स्ची

 उक्त स्थापन के उपबन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भागुक्त बहुती को ऐसी विवरणियां भजेगा और ऐसे क्षेत्रा रखेगा तथा निर्दाक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धिष्ट करें।

- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निरिष्ट करें।
- 3. साल् हित बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ब्रन्सर्गत लेखाओं का रखा जाना, निव लियों का प्रस्तुत किया लना, बीमा प्रशिमयम का सन्याय, लेखाओं का अन्यरण, निर्देशिय प्रभायों क सन्दाय प्राप्ति भी है, होने निले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएक।।
- 4. नियोज त, केक्ट्रीय नरफार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमी की एक प्रसि, और जब कथी उनमें संशोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मनारियों की बहुसंख्या की माण में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी, जी कर्मबारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अर्थान छूट प्राप्त किसी स्थापन की अथिष्य निधि का पाष्ठले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया आता है तो नियोजिक मामृहिक बीमा स्काम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबस्त सरगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये आते हैं, ती, निर्माजक उक्त रकीम के प्रधीन क्षामंचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचिंग रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हों, जी उक्त स्कीम के प्रधीन अमुक्तेय हैं।
- 7. सामृहिक कीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मजारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मजारी की उस दक्षा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मजारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के धन्तर के बराबर रक्तम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कीई भी संबोधन प्रादेशिक भविष्य निर्धि भ्रायुक्त देहली के पूर्व भ्रतुमीदन के बिमा नहीं किया आएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो बहा प्रादेशिक भविष्य निर्धि भ्रायुक्त, भ्रपना भ्रतुमीदन देने से पूर्व कर्मचारियों की भ्रपना बुष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ध्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना बुका मधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों की प्राप्त होने बाले कालदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियस सारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विश्विक वारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के श्रम्तगंत होते, बीमा कायवों के सम्बाय का उत्तरशायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के भ्राधीन भाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राश्चि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों की उस राश्चि का सन्दाय तरपरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्व दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुविश्वित करेगा।

[गं. एय-35014 (296) /82 पी.एफ. 2/एम. एस 2]

S.O. 2736.—Whereas Messrs National Agricultural Coope ative Marketing Federation of India Liimted, Sapan Building, 24 East of Kailash P.B. No. 3580, New Delhi (DL/1507) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without makings any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Colphation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 617 dated 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed here to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of the 21-1-1989.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The emologer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exemnted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Groun Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The empolver shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Groun Insurance Scheme annronizately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No anyindment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the Interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said es ablishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal helps of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the northnee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/296/82-PF,II(SS.II)]

का. भा. 2737. मैंसर्स वी भारतीय एप्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेसन, कामघेनु सेनावित वापत मार्ग, पुजे-411016 और इसकी सांखाएं जो मधिनियम के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से नहीं जाती है (एच/15684) (जिसे इसमें इसके पत्रवात उक्त स्थापन कहा गया है) में कर्मवारी मिविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पत्रवात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के सबीन छट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

और चैनीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमिथम का सन्दाय किए बिमा ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जी फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हैं जो उन्हें कमचारी निक्षेप सहब्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ध्रवीम प्रकृत हैं;

चल: कैन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मारत सरकार के अम मंत्रालय की धिक्षपूचना संख्या का मां. 1620 सारीख 5-3-1983 के धनुसरण में और इससे उपाबद अनसूची में विनिधिष्ट गतौं के घर्षान एहते हुए उक्त स्थापन को, 19-3-1986 से तीन धर्ष की ध्रवधि के लिए जिसमें 18-3-1089 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्रनुसुची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवर्णियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान भरेगा जो कैसीय सरकार समय-समय पर निविष्ट करे।
- मियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति
 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो कैन्द्रीय सरकार, उक्त भिधिनियम

- को धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामृहिक कीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके भ्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विकरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का तक्वाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय भ्रादि भी है, होने बाले सभी स्पयी का बहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संघोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यवि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कमचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रिमियम के भविष्य निधि का या उक्त प्रिमियम के भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज नरेगा और उसकी बाबत प्रावण्य प्रीमियम पारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदें बढ़ाये जाते हैं, सो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्य। करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से ग्रधिक ग्रमुकूल हों, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन ग्रमुक्त हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यिव किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के ग्रधीन सन्देय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में सन्देय होती जब वह उक्स स्कीम के ग्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोगों रक्षमों के ग्रन्तर के बराबर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम भे उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना सुका है, अर्धान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह खूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवस, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने विया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वंशा में, उन मृत सदस्यों के मामनिवेशिक्तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूटम दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रस्तांत होते, बीमा फायदों के सन्वाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्क्षीम की मधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय रुत्परता से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण वाले की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चिस करेगा।

[संख्या एस-35014 (310)/82-प्रा. एफ. 2 एस. एस.-2]

S.O. 2737.—Whereas Messrs The Bhartiya Agro Industries Foundation, Sanapati Bapat Marg, Poona-411016 and its branches not covered under the Act independently (MH) 15684) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Empolyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinatter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable, to such employees' than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1620 dated the 5-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 19-3-1986 upto and inclusive of the 18-3-1939.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilties for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, sub-unission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an empolyce, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more fearourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a rea-

- sonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/310/82-PF.II(SS.II)]

का. धा. 2738.— मैससं सालीम टैक्सटाइस्स लि., सैज्यायपालियम, नर्रासहापुरम, पो. भा. भातूर, तालुक, जिला, सालीम-636108 (टी. एन. / 6517) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध धींधनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मिश्रिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदक किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के यमंचारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो कायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्षेय हैं;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम महालय की श्रिष्ठ पूजना संख्या का. भा. 4278 तारीख, 26-11-1982 के भ्रनुसरण में और और इससे उपावक भनुसूची में विनिधिष्ट भर्ती के श्रिष्ठीन रहते हुए उक्त स्थापन की, 18-12-1985 से तीन क्यें की भ्रविधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सिम्मिलित है, उक्स स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदिक्षिक भविष्य निधि प्रायुक्त, तमिलनाडू की ऐसी विवर्णियां संजेगा जीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थेक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के चंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रसासन में, जिसके ग्रन्तगैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का शत्त्ररण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मादि भी है, होने बाले सभी व्ययों ता बहुन नियोजक हारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, के बीच सरकार द्वारा यया धनुमोतित सामृष्टिक कीभा स्क.म के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन दिया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्म कारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचनापट्ट पर प्रवशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी प्रथिष्य निधि का या एक क्रीवित्यम के क्रवीन छूट प्राप्त पिसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित क्रिया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्काम की सबस्य के क्रय में उसका नाम नुरस्त बर्ज करेगा और उसकी बायत भावक्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत्त करेगा।
- 6. यवि सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीत मर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजन उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमंबारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से प्रधिक प्रतुक्त हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमृक्तेय है।
- 7. सामृहिक कीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्लाकारी की मृत्यू पर इस स्कीम के प्रधीन सम्देय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मकारी की उस दशा में सम्देय होती अब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मकारों के विधिक वारिस/नामनिवेंशिती की प्रतिवार के रूप में दोनों रक्षमों के प्रभार के बराजर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से वर्भचारियों के हित पर प्रिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना प्रनुसीवन देने से पूर्व कर्भचारियों को धपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवस्त देगा।
- 9. यदि किसी कारणक्षण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मबारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक भारतीय जीवन श्रीमा निगम हारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्धाय करने में असफल रहता है, भीर पालिसी को व्यवस्त हो जाने विया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए किसी क्यतिश्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्काम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आरतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राजि के हकदार नामनिर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस राजि का सन्दाध तत्परता से भीर प्रत्येक दक्षा में हर प्रकार से पूर्ण वाने की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(342)/82-पी. एफ. - 2/एस. एस. 2]

S.O. 2738.—Whereas Messrs Salem. Textiles Limited Selliampalayam, Narasingapuram, P.O. Attur, Taluk, Salam District-636108 (TN/6517) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Ensployees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4278 dated the 26-11-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 1/-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tanal Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under chause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transf-r of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insuranie Scheme as approved by the Central Government and, as and when an ended, alongwith a translation of the salient leatures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced to that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group rance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendments likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the duc date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to Iapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in anycase within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/342/82-PF.II(SS. II)]

का.आ. 2739. — मैंसर्स अगन्त फाइन आर्ट नियोवनर्स, मनोहर कालोनी रोड, गोंडिया, जिला बान्द्रा (एम.एन/3549) (जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) नै कर्मजारी भविषय निधि मौर प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपघारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान होगया है कि उस स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिनूचना संख्या का आ, 616 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में भीर इससे उपावद अनुसूची में विनिष्टि शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-1-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सिम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपधन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी जिवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा. निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रस्यैक मास की समाध्ति कै 15 दिन के भीतर सन्ताय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके असार्गत लेखाओं का रखा जाता, विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, शिखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं होने वाले सभी व्यथों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, कैन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुगोवित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर शब कभी उनमें संबोधन किया जाए तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मवारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यथि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिज्ञष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन खुट अस्त किसी स्थापक की भिज्ञष्य निधि

- का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीन के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरस्स दर्ज करेग। भीर उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन नीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यवि सामृहिक बीमा स्कीम के अधील धर्मशारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मबारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मबारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी,बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में सन्देय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबच्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मजारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुसोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश्न, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जोवन बीमा निगम की किसे सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायरे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह खूट रहु की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणक्या, नियोजक बारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असकल रहता है, भौर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो छूट रह् की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्वेशितियों या विधिक वारिसीं को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्ताय का उत्तरवायस्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम भे अधीन आने बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि भे हकदार नाम- निर्देशिती/विधिक धारिसों को उस राणि का सन्दाय तत्परता से धीर प्रत्येक वणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास भे धीसर सुनिश्वित करेगा।

[संख्या एस-35014(382)/82/पी .एक .-2/एस .एस . 2] ए.के. भट्टाराई, वर सनिव

S.O. 2739.—Whereas Mesars Vasant Fine Art Litho Works, Manchar Colony Road, Gondiya-441614, District Bandara (MH/3549) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible

under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 616 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of the 21-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The empolyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and mtaintain such accounts and provide such facilties for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shal display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and whenamended, alongwith a translation of the saltent features thereof, in the language of the majority of the semployees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give areasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the sight Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/362/82-PF.IJ(SS. II)] A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का. अत. 2740.— भीदोगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, कैन्द्रीय सरकार मैंसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरहस लिमिटेड, बीकानेर द्वारा 61 ग्रामीण पीस-रेटिड कर्मकारों की छटनी के लिये अनुसति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, अनुबंध में निर्दिष्ट, श्रीबीगिक अधिकरण, जयपुर के प्रवाट को प्रकाणित करती है, जो कैन्द्रीय सरकार को 9 जुलाई, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2740.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, relating to the request of M/s. Rajasthan State Mines and Minerals Ltd., Bikaner for permission to retrenen 61 village piece-rated workers, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

ANNEXURE

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. C.I.T. 16|86.

Ms. Rajasthan State Mines and Minerals Limited, Bikaner;

VS

Their Workmen. PRESENT

Shri R. S. Verma, R.H.J.S.

For the Workmen: Shri J. L. Shah. For the Employer: Shri V. P. Agrawal.

Date of Order:

26-4-86.

ORDER

The Government of India, being the appropriate Government in the matter, has made this reference under Sub-section 6 of Section 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter called "The Act," vide its notification No. L-29024(1)|86-II(B) dated 28th Feb., 1986.

"Whether the request of M|s. Rajasthan State Mines and Minerals Limited, for permission to retrench 61 village piece-rated workers, whose particulars are given in the annexure, is justified? If so, to what relief are the workmen concerned entitled."

2. The reference was received in this Tribunal on 7-3-86 and was placed before me on 10-3-86. Since correspondence was pending between the Tribunal and the Ministry of Labour. Government of India, regarding issue of notification under section 8 of the Act, and no final reply had been received from the aforesaid Ministry, the matter was posted to 7-4-86 so as to enable the Tribunal to have a final reply from the aforesaid Ministry. However, since no final reply

whatever, was received from the aforesaid Ministry and time was running out, the Tribunal proceeded with the hearing of the reference. Shri J. L. Shah, appearing on behalf of the workmen filed his claim on 7-4-80. On being pointed out that the claim was to be filed by the employer, the parties agreed that the employer may file its claim and claim filed by Shri Shah may be treated as reply to the claim, in addition to such reply, as Shri Shah may choose to file after the claim has been filed by the employer. Accordingly, Shri V. P. Agrawal filed the claim on behalf of the employer on 9-4-86. Shri J. L. Shah filed reply on behalf of the workmen on 16-4-86.

- 3. In his claim petition, the employer has raised a number of objections to the legality and maintainability of the reference, as also regarding jurisdiction of this Tribunal to proceed with the reference. Both the parties wanted these objections to be tried as preliminary issues, hence on 16th April, 1986 itself, following preliminary issues were framed. Both the parties agreed before the Tribunal that these issues did not require any evidence. As such, these issues have been heard as preliminary issues:
 - (i) Whether the reference is without jurisdiction because appropriate Government Specified authority has not passed an order under section 25-N of the Industrial Disputes Act?
 - (ii) Whether the reference could have been made only to Central Industrial Tribunal and refrence to this Tribunal is abinitio void?
 - (iii) Whether this Tribunal has no jurisdiction because no notifications have been issued under section 8 of the Industrial Disputes Act?
 - (iv) Whether this Tribunal has no territorial Jurisdiction to hear the matter?
 - (v) Whether the Tribunal has no jurisdiction to proceed with the matter since it did not enter into reference within 30 days of the date of order of reference?
 - (vi) Whether this Tribunal is not the correct forum to decide competence of the reference and jurisdiction of the Tribunal.
 - (vii) Whether under the circumstances of the case, it is to be deemed that Government, had refused to grant permission to the employer to retrench the workman?"
- 4. I have heard Shri V. P. Agrawal for the employer and Shri J. L. Shah for the workmen at some length since the issues go to the very root of the matter. I have also perused the material available on record. I have given my earnest consideration to the arguments of rival sides.
- 5. Before, I deal with the issues, I may be briefly narrate the undisputed facts of the case, Mls. Raiasthan State Mines and Minerals Limited is a State controlled company, duly registered under the Indian Companies Act with head-quarters at Bikaner. It has gypsum mines at Tamser in the district of Bikaner. It decided to retrench 61 workmen, working at the Jamser mines and submitted an application to the

Central Government for permission to retrench such workers under section 25-N of the Act. This application was moved on 1sf|2nd Jan., 1986. The Government of India also received representations against the said application. No specific order, granting or refusing the application appears to have been passed by the said Government. However, it chose to make a reference to this Tribunal, as stated above.

- 6. To appreciate the rival contentions, it would be useful to have a look at provisions of section 25-N of the Act. It reads as follows:
- "25-N. Conditions precedent to retrenchment of workman:---
 - (1) No workman employed in any industrial establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until:—
 - (a) the workman has been given three months' notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, for the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and
 - (b) the prior permision of the appropriate
 Government or such authority as may be
 specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereafter
 in this section referred to as the specified
 authority) has been obtained on an application made in this behalf
 - (2) An application for permission under subsection (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workman concerned in the prescribed manner.
 - (3) Where an application for permission under sub-section (1) has been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen concerned and the persons interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and adquacy of the reasons stated by the employer the interests of the workmen and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.
 - (4) Where an application for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of 60 days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

- (5) An order of the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (6) be final and binding on all the parties concerned and shall remain in force for one year from the date of such order.
- (6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under subsection (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a Tribunal for adjudication.

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of 30 days from the date of such reference.

- (7) Where no application for permission under sub-section (1) is made or where the permission for any retrenchment has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of retrenchment was given to the workman and the workman shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if not notice had been given to him.
- (8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions this section, the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or the like, it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such establishment for such period as may be specified in the order.
- (9) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under sub-section (4) every workman who is employed in that establishment immediately before the date of application for permission under this section shall be entitled to received at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to 15 days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months."
- 7. The first contention of Shri V. P. Agrawal is that the reference is without jurisdiction since the appropriate government has not passed a reasoned and speaking order as envisaged by section 25-N (3) of the Act. This contention is the subject matter of per-liminary issue No. 1. Shri Agrawal contends that passing of an order under sub-section (3) of section 25-N of the Act, is a condition precedent to the making of the reference, Shri J. L. Shah, on the other hand contends that passing of an order under sub-section (3) is not and cannot be a condition precedent for making a reference under section 25-N (6) of the Act. However, he agrees with Shri Agarwal that this reference was bad in as much copies of application

- of the employer were not served on individual workman as required by sub-section (2) of the above section. He contends that service of copy of the application on each individual workman was mandatory and in absence of compliance with the said provision, there was no proper application before the Union Government. Without a valid application, the Union Government was not competent to make this reference.
- 8. Shri V. P. Agrawal states that he does not conceed but is not in a position to take the stand that copies of the application had been served on individual workmen.
- 9. A bare reading of the section shows that an application by the employer is the very foundation for action under this section. Provisions of sub-section (2) of the section are very categorical and clear and mandate that "a copy of such application shall also be served simultaneously on the workman concerned in the prescribed manner." There is a clear cut object behind this rule of law. Sub-section 3 of the section envisaged quasi-judicial administrative enquiry before the appropriate Government and a workmen can adequately meet the application, only when he has been supplied with a copy of the same. I, therefore, agree with Shri Shah that service of the copy of the application on each workman is a sine qua non for the further action in the matter. In the present case, though some representations appear to have been made before the appropriate Government, it does not appear from the reference that copy of such application had been made available to each and every induvidual workman. I am, therefore, of the view that the appropriate Government did not acquire proper jurisdictional foundation to make a reference to this Tribunal and on this short ground, the reference is liable to be rejected.
- 10. However, I find it difficult to agree with Shri Agrawal that a reasoned order is a condition precedent to make a reference. Suffice it to say that in appropriate case, the appropriate Government may not pass any order at all what to say of a reasoned order and in that case, after expiry of period of 60 days, application of the employer shall be deemed to have been granted by virtue of sub-section (4) of the aforesaid section. I decide the issue accordingly.

11. ISSUE No. 2 and 3,

Shri V. P. Agarwal contends that the matter could have been referred only to a Tribunal constituted by the Central Government and not to a Tribunal constituted by the state Government. He contends that the reference does not indicate as to which Tribunal the matter was referred. If it is assumed that the reference was made to the Tribunal constituted by the Central Government, then Constitution of the Tribunal is invalid, since no notification has been issued under section 8 of the Act. Shri Shah contends that reference does not indicate that it was referred to a Tribunal constituted by the Central Government, hence it may be assumed that it was referred to the Tribunal constituted by the State Government and the reference is valid.

12. Hero, I may state that this Tribunal has been constituted by the State Government. This Tribunal

has also been functioning as a Tribunal constituted by the Central Government but since no notification has been issued under section 8 of the Act, cases referred to the Tribunal by the Central Government are not, making any progress. As indicated at the outset, the correspondence made the Tribunal with the Labour Ministry, Government of India has not borne any fruit.

- 13. Shri Agrawal is right that the reference does not explicitly indicate to which Tribunal it has been made. It would have been better if the reference would have specifically said to which Tribunal the matter has been refrred, viz. to one constituted by the Government or to one constituted by the Central Government. However, all official acts are presumed to be done correctly, hence, I assume that the reference has been made to the Tribunal constituted by the State Government, because it is this Tribunal which has been validly constituted so far.
- 14. The contention of Shri Agrawal is that Central Government is the appropriate Government for purposes of this matter, as per definition of "appropriate Government" given in section 2(a) of the Act. Prior to amendment made by Act No. 46 of 1982, all references, whether under section 10, or section 25-N used to be made by the appropriate Government to corresponding Tribunal constituted by appropriate Government. So far as section 10 was concerned, the position was changed by the aforesaid amendment and a third proviso was inserted in section 10, so as to enable the Central Government, to make a reference to a Tribunal constituted by the State Government. A similar amendment was not made in section 25-N and hence, it can be safely assumed that the Parliament did not envisage any change, so far as references to be made under this section were concerned. He submits that under section 10 of the Act, it is industrial dispute which is referred to a Tribunal but under section 25-N (6), an industrial dispute is not referred rather only an application of the employer is referred. This is a function to be performed under amended section 7A by a Tribunal constituted by the appropriate Government. Shri J. L. Shah contends that section 25-N refers only to 'a Tribunal' hence, the Central Government was competent to refer the matter even to a State Tribunal.
- 15. I have given my earnest consideration to the rival contentions and must say that contention of Shri Agrawal stands on a sound footing Section 7 (A) (1) of Act read as follows:
 - "7-A. Tribunals-(1) The appropriate Government may by notification in the official Gazette, constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes relating to any matter, whether specified in the Second Schedule or Third Schedule (and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act)."

A bare reading of this section shows that the approriate Government constitutes one or more Industrial Tribunals for adjudication of industrial disputes, as also for performing such other functions as may be assigned to them under the Act. It is a settled position 555 GI|86—14.

that prior to the amendment mentinged above the Central Government could refer the industrial dispute and ask performance of other functions, only by a Tribunal constituted by it. By the amendment under reference, a third proviso was added to section 10 and this proviso now enables the Central Government to refer an industrial dispute to a State Tribunal also. No similar amendment has been made in section 25-N (6) of the Act. Hence, it is obvious that so far as section 25-N (6) is concerned, no change was contemplated in the forum by the Parliament. This is true that section 25-N (6) refers to 'a Tribunal' but this reference has to be read in context of the provisions of section 7A of the Act. It may be stated that no industrial dispute has been referred under section 10 of the Act but only a matter has been referred by the appropriate Government, which falls within the purview of 'such other functions' of the Tribunal, as envisaged by section 7A of the Act and hence, the Central Government could have referred the matter only to a Tribunal constituted by it under section 7A. of the Act. Reference, assuming it to be a State Tribunal is bad in law. The Central Tribunal has not been duly constituted by the issuing a notification u|s 8 of the Act and as such the reference is not entertainable. The issues are decided accordingly.

16. ISSUE NO. 4,

Assuming for the sake of arguments that the reference was to a State Tribunal and not to a Tribunal constituted by the appropriate Government, Shri Agarwal contends that this State Tribunal does not have jurisdiction over Division, where the Mines are situated. Shri Shah contends that the appropriate Government may refer the dispute to any Tribunal irrespective of territorial jurisdiction, Section 7A of the Act, as such does not expressly stipulate that an industrial Tribunal may be constituted for a particular area, but perhaps the very scheme of action 7A empowers the appropriate Government to constitute a Tribunal for any limited time or for a particular case or a number of cases or for a particular area.' (Please see O. P. Malhotra. The Law of Industrial Disputes, Fourth Edition, Page 544). If a Tribunal has been specifically constituted for a specific area, then it may be argued that it has no jurisdiction beyond its territorial limits. But in the present case, no notification has been brought to my notice, which confines territorial limits of this Tribunal to any geographical area. Hence, this objection of Shri V. P. Agrawal deserves to be noticed only for the sake of rejection. Issue is decided accordingly.

17. ISSUE NO. 5 :

The contention of Shri Agrawal is that even if for the sake of arguments, it is assumed that this Tribunal had jurisdiction, the jurisdiction has come to an end by effluxe of time. He contends that proviso to section 25-N (6) mandates that the Tribunal shall pass an award within a period of 30 days from the date of reference. The reference was made on 28-2-86. Thirty days expired on 30-3-86. Hence, no award can be passed now. He submits that by virtue of section 25-N (5), a disability attaches to the employer and he may not make a fresh application for a period of one year Shri Shah contends that section 25-N(5) does not create any disability, whatsoever. The pro-

visions of proviso to section 25-N (6) are directory and not mandatory. The term of one month, looking to the volume of work in the various Tribunals is impracticable.

18. I have considered the rival contentions. To my mind provisions of section 25-N (5) do not create any disability and the order of the appropriate Government has been made specifically subject to the provisions of sub-section (6) when the order made by the Government is subject to provisions of subsection (6), it is obvious that the operation of the order would comence from the date of final order made under sub-section (6). To my mind, the provision fixing the period in the proviso to sub-section (6) is only directory and not mandatory. I am supported in my view by the observations in O.P. Malhotra's. "The law of Industrial Disputes" Fourth Edition, Page 1425 when the learned author observers;

"The proviso prescribes the time limit of thirty days from the date of reference during which the Tribunal should pass its award. From the use of the word 'shall' it would appear that the requirement of the proviso that the award should be made within thirty days from the date of reference, is mandatory. Furtharmore, there is no power vested in the Tribunal to extend the period of adjudication. But can it be said that an award made beyond thirty days will be invalid and inoperative. From the scheme of the Section the answer should be in the negative. Though making of the award is mandatory, the requirement to make the award within thirty days appears marely to be directory.

Shri J. L. Shah has referred to certain rulings also but since I have accepted his contention, I need not refer to those rulings. Hence, I decide the issue accordingly.

19. ISSUE NO. 6.

This issue has not been pressed before me. I am of the view that this Tribunal can decide if the reference was valid or not. It can also determine if it has jurisdiction to hear the matter or not. Therefore, decide the issue accordingly.

20. ISSUE NO. 7:

Shri Shah contends that the appropiate Government did not pass any order as envisaged by section 25-N (3) but has referred the matter. Hence, it should be presumed that the application of the employer has been rejected. Hence, the reference itself does not survive. I think that the argument is not sound. Rather, when the appropriate Government has not made any order under section 25-N (3), then by virtue of section 25-N (4), the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of sixty days from the date of making application by the employer under section 25-N(2). However, since in this case it has not been shown that copies of application, had been served on each individual workmen, it is not free from difficulty to spell out if the consequence mentioned in section 25-N(4) will flow

from the act of not passing any order by the appropriate Government. I decide the issue accordingly.

21. In view of what I have said above, this reference is invalid and incompetent and fails. Let a copy of this order be sent to the appropriate Government for such action, and is deemed proper at that end.

R. S. VERMA, Judge [No. L-29024|1|86-D. III (B)] V. K. SHARMA, Desk Officer

नई विल्ली, 15 जुलाई, 1986

का. आ. 2741 — भौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, कैन्द्रीय सरकार व राजरप्पा प्रोजेक्ट मैससें सी सी लि. डाक राजरप्ता जि. हजारी बाग, के प्रवश्वतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों भीर उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निविष्ट भौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौदोगिक अधिकरण, नं. 2, धनवाद के पंचाट की प्रकार को प्रकार को प्रकार को प्रकार को प्रकार को प्रकार हुआ था।

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2741.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajrappa Project of Central Coalfields Limited, P.O. Rajrappa, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 173 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Rajrappa Project of M/s. C. C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES

On behalf of the workmen.—Shri Lalit Burman, Vice President, United Coal Workers Union.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

State: BIHAR Industry: COAL

Dated, Dhanbad, the 30th June, 1986

AWARD

The Govt. of India. Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(24) 85-D:IV(B), dated the 3rd December, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Rajrappa Project of C. C. Ltd., P.O. Rajrappa, Distt. Hazaribagh in terminating the services of Shri Lalan Tiwari, Driver is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Lalan Tiwari was appointed as a driver in Cat. V. vide letter dated 9 12-4-1983 in a permanent vacancy. As usual he was kept on probation for a period of 6 months for verification of his character and antecedents. Subsequently by an order dated 26-5-1983 he was posted in excavation section of Rajrappa Project with effect from 26-5-1983. There was never any complaint regarding his conduct and services during the period of his employment in the excavation section of Rajrappa Project. The management issued a chargesheet dated 11-9-1983 against the concerned workman making certain allegations and the workman was put under suspension with effect from 11-9-1933. The concerned workman submitted his explanation dated 13|16-9-1983 denying all the allegations made against him in the charge and pleaded not guilty of the alleged misconduct. The management by memo dated 2|4-10-1983 proposed to hold enquiry into the charges against the concerned workman and by further memo he was allowed to resume his duties with effect from 22-10-1983. The enquiry officer held the enquiry on 10-10-1983 at 10.00 A.M. The said enquiry was neither just nor proper. The concerned workman asked for the copies of the enquiry proceeding and the enquiry report from the management but the management refused to furnish the same to him. The management terminated the services of the concerned workman with effect from 9-11-1983 vide memo dated 9-11-1983 without giving any reason whatsoever. The concerned workman lodged a protest against the said action of the management. The case of the workman was taken up by the union before the ALC(C) Hazaribagh. The conciliation proceeding was started which ended in failure. Thereafter the dispute was referred to this Tribunal for adjudication.

The management had not asked for a report about the performance of the concerned workman in the first week of November, 1983. There was never any adverse report against the concerned workman and the alleged report was prepared just on the eve of the termination of the services of the concerned workman and after the conclusion of the disciplinary proceeding. The management adopted a circuitous and questionable method to get rid of the services of the concerned workman. The action of the management in terminating the services of the concerned workman is neither legal nor justified as it amounts to colourable exercise of the powers and victimisation in total violation of the provision of the Standing Order. The action of the management is mala fide.

On the above plea it is submitted that the workman is entitled to get the relief of reinstatement with full back wages and other benefits with effect from 9-11-1983 as also the full wages for the period of suspension from 11-9-1983 to 21-10-1983.

The case of the menagement is that the reference is bad in law in as much no dispute was raised by the 555GI/86-15

workmen directly with the management demand was made by the workmen on the management at any time before raising the dispute before the ALC(C) Hazaribagh. The reference is barred by the express contract of service between the concerned workman and the management. The workman had been issued with an appointment letter dated 9|12-4-1983 odering him appointment as a probation Cat. V subject to the terms and conditions specified therein. He joined the duty on 10-5-1983 after accepting the said terms and conditions. He was appointed only for a period of 6 months and was placed on propation during the period his retention in the service for a further period was to depend on the receipt of the report about his work during his period of probation. In the event of a report declaring him not fit for employment, his services on probation were liable to be terminated without assigning any reason during the probationery period. His retention for a further period was to depend on receipt of the report about his work during the period of probation. In the first week of November, 1983 a report about his performance was obtained. The report was called for which indicated that the concerned workman lacked devoation to his work and indulged in indecent behaviour and was also not amenable to discipline. It was also reported that he was undesirable workman. On consideration of the said report and considering the terms and conditions of his appointment it was decided by the management of Rajrappa area that the services of the concerned workman should be terminated. In the meantime an enquiry report relating to disciplinary case in which the concerned workman was found guilty was also placed before the General Managr C.M.E. Rajarappa area and having regard to the enquiry report as a result of the domestic enquiry, the General Manager CME decided that since the concerned workman is considered to be undesirable element he should not be continued in the services of the management. The fact that the concerned workman was en probation at that time was also taken into account while coming to the said decision. Accordingly the management issued an order on 9-11-1983 terminating the services of the concerned workman from the said date. It was alleged in the charge in respect of which domestic enquiry was held against the concerned workman that on 10 9 1983 the concerned workman was on duty in 3rd shift starting from 10.00 P.M. At about 10.15 P.M. on that day he went in Rajrappa Project canteen in drunken condition and broke the glass panes by hitting it with his fist. He was also shouting abusive, filthy language at that time in the canteen. He was prevented from further damaging the canteen materials by the employees present there at that time who took the concerned workman out of the canteen. As the concerned workman was completely drunk and was unable to perform his duties he was sent back by truck by the shift incharge at about 11.00 P.M. On receipt of the said report the concerned workman was issued with a chargesheet dated 11-9-1983 to which he submitted his explanation. The explanation was found to be unsatisfactory by the Project Officer Agent of Rajarappa Project and he ordered a detailed enquiry into the charges framed against the concerned workman. Shri A. K. Das, S.O. S.O.M. (M.S) was appointed as enquiry officer. The enquicy officer held the enquiry in which

the concerned workman fully participated being associated by a co-worker during the enquiry. The management's witnesses were examined in their presence and the concerned workman was given full opportunity to cross examine the management's witnesses. The concerned workman was also given an opportunity to make statement and to produce his witness in defence. The enquiry was held in accordance with the principles of natural justice and all possible and reasonable opportunities were given to him to defend himself. The enquiry officer found the concerned workman guilty of the charges framed against him except the charge of being in a drunken state. The result of the domestic enquiry was also sufficient to administer that the concerned workman was not a fit person to be allowed further continuance in the services of the management beyond the initial period of 6 month; for which he was employed on probation. On the above facts it is submitted on behalf of the management that their action in terminating the services of the concerned workman is legal and justified and that he had not right to continue in the employment of the management beyond 9-11-1783.

The only question to be determinated in this case is whether the termination of the services of the concerned workman was legal and justified with effect from 9-11-1983.

The management examined two witnesses and the workmen examined one witness in support of their respective cases. The documents produced on behalf of the management have been marked Ext. M-1 to M-16 and the documents of the workmen have been marked Ext. W-1 and W-2.

Admittedly the concerned workman was appointed as a driver in Cat. V on probation for a period of 6 months. Ext. M-1 dated 9/12-4-1983 is the appointment letter which sets out the terms and conditions of his appointment. It appears from Ext. M-1 that the appointment was purely on probation for a period of 6 months and subject to the satisfactory verification of character and antecedents. His probation may have to be extended till a report verification of his character and antecedents is received from the District Magistrate Dv. Commissioner within the period of his probation. It is further stated that his retention in service for a further period was to dependent on receipt of the report about his work during his period of probation, and in the event of a report declaring him not fit for employment his services on probation was to be terminated without assigning any reason during the period of probation. The case of the management is that when the concorned workman was to complete his probationery period the Dv. P.M. (R) asked for his performance report for his probationery period and thereafter Sr. Executive Engineer under whom the concerned workman was working submitted his report on 5-11-1983. Ext. M-10 is the note by Dy. P.M. had asked for a performance report of the concerned workman and thereafter the executive submitted his engineer Shri Om Prakash Kakroo report to the following effect. "He lacks devotion to work and indulges in indecent behaviour. He is not amenable to discipline also. It may be summed up that Shri Lalan Tiwary is an undesirable workman. Necessary action on the basis of the above

may be taken." MW-1 is Shri Om Prakash Kakroo who has given this report about the concerned wor man. The said report of Shri Kakroo was considered and in view of the performance report and the report reviewed by the Dy. C.M.E(F) and Personnel Officer (RP) it was confirmed that the work performance and behaviour of the concerned workman was not good. The report was submitted to the General Manager for necessary orders and the General Manager ordered that as the work performance etc. of Shri Lallan Tiwari has not been found to be satisfactory during the probationery period, his services may be terminated on expiry of the probationery period. All these notes are contained in Ext. M-10 and it has been proved by MW-1. It will thus appear from Ext. M-10 and the evidence of MW-1 that the services of the concerned workman were terminated as his work performance and behaviour was not found satisfactory during the period of probation, M-7 is the memo dated 9-11-1983 by which the services of the concerned workman was terminated. Ext. M-7 shows that the concerned workman was purely on probation for a period of 6 months and as such his services were terminated with effect from 9-11-1983 and accordingly he ceased to be in the services of CCL with immediate effect. It has been submitted on behalf of the management that in accordance with the terms and conditions of his services as laid down in Ext. M-1 the services of the concerned workman was terminated as the report was obtained showing that he was not fit for employment. Admittedly the concerned workman was working under MW-1 Shri Kakroo and there is nothing in the evidence of MW-1 to show as to why he would make any false report against him.

The certified standing orders Ext. M-11 has been filed by the management which is applicable to all the workmen of CCL. In S.O. 3(c) probationer is defined as one who is provisionally employed to fill a vacancy in permanent post and has not completed 6 months in that post. The other part of the definition is not relevant for the purpose of our case. From the terms and conditions of services stated in Ext. M-1 it will appear that a probationer does not automatically attain permanent status on the expiry of his period of probationership. If a probationer is neither discharged nor confirmed he continues to serve as probationer until otherwise dealt with. It rests with the satisfaction of the employer whether a probationer had put in satisfactory service or not. Such satisfaction cannot be objectively decided and an employer is not bound to give any reason if he does not confirm a probationer on the expiry of the period of probationership. If an employer acts within his discretionary right it is difficult to ascertain mulafides against him. An employer need not given any reason for discharging a probationer. Even if certain reasons given by the employer does not appeal to the Tribunal, it cannot take away or detract the employer from such right. Thus as admittedly the order of termination of the services of the concerned workman was passed prior to the completion of the probationery period of 6 months. The employer was quite within its competence and authority to terminate the services on the ground that the performance of the probationer was not satisfactory.

Admittedly a chargesheet had been submitted against the concerned workman for misconduct and

the concerned workman had given his reply to the chargesheet. It will also appear from the evidence of MW-2 who was the enquiry officer that the concerned workman along with his co-worker had participated in the enquiry and that all the management's witnesses were examined in his presence and he was given an opportunity to cross-examine the management's witnesses. On perusal of the enquiry proceeding Ext. M-13 it appears that the concerned workman and his co-worker had cross-examined the management's witnesses and they had signed on each page of the enquiry proceeding indicating that they were present in the enquiry proceeding although. It will also appear from the enquiry proceeding that the concerned workman had given his statement and had also examined witnesses in his defence. On perusal of the evidence of the three witnesses examined on behalf of the management in the enquiry it appears from the evidence of MW-1 who was working as a canteen boy that the concerned workman had used abusive language and had broken glass panes and thrown other materials of the canceen. MW-1 has stated that the concerned workman himself had thrown glass and water and that the ground of the canteen was not slippery. The other two witnesses examined on behalf of the management did not fully support the management's case and the management witnesses No. 2 had almost turned hostile and gave his statement supporting the defence version. However, the fact that the concerned workman had broken glass panes etc. is established by the reply of the concerned workman in Ext. M-3. The concerned workman has stated in Ext. M-3 which is the reply to the chargesheet that "He had entered local canteen of project for getting some refreshment. He has tened to the counter with the ticket and slipped before the counter and to save himself he had stretched his hand and with the body weight on his hand the glass panes on he counter was broken and he was injured in his hand and that when he tried to stand up some aluminium glass on the counter slipped down due to his body touch.". He has also stated in Ext. M-3 that he had abused the canteen employees after he got the inqury by fall. In his statement before the enquiry officer the concerned workman answered to question No. 10 that he had abused the canteen employees when he had got bleeding injuries. Although the evidence before the Enquiry Officer was meagre and was supported by the evidence of canteen by only nonetheless there was evidence to the effect that the concerned workman had broken the glass panes of the show case of the canteen and he had thrown some materials and that he had also abused the employees of the canteen. It cannot therefore be said that the finding of the enquiry officer was perverse and was not based on the evidence on the record.

It will appear from Ext. M-7 that the concerned workman was not dismissed on the basis of the finding of the Enquiry Officer but it appears that the enquiry was taken into consideration as a material to show that the conduct of the concerned workman was not satisfactory so as to confirm him after the period of probation. The concerned workman WW-1 himself has stated in his examination-in-chief that the management did not take any action on the basis of the chargesheet but terminated his services on the basis of Ext. M-7. Thus there is no room

for doubt that the services of the concerned workman was terminated because of his unsatisfactory performance during the probationery period. As the management was within his authority to terminate the services of a probationer during the probationery period for unsatisfactory performance, I do not think it to be a fit case where the Tribunal can interfere with the said order of the management.

In the result, I hold that the action of the management of Rajarappa Project of Central Coalfields Ltd. in terminating the services of the concerned workman Shri Lallan Tiwary, Driver is legal and justified and consequently he is not entitled to any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer. [No. 1.-24012(24)|85-D.IV(B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1986

का. आ. 2742.— प्रौजोगिक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मिलिट्टी बेरी फार्म के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उसके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्विष्ट श्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भीद्योगिक अधिकरण, के नई विस्ती के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 4/7/86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th July, 1986

S.O. 2742.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Fribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Military Dairy Farm and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th July, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

I. D. No. 28|86

In the matter of dispute between:

Shri Amar Singh c|o Shri Naresh Kumar, 1098 Bengalli Mohalla, Ambala Cantt.

Versus

Assistant Director, Military Dairy Farm, Ambala Cantt.

APPEARANCES:

Shri Charan Dass Kamra UDC—for the management.

None-for the workman.

AWARD

The Central Government, in the Ministry of Labour vide its notification No. L-13012(13)|84-B.II (B) dated 29 January, 1986 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the Management of Military Farm, Ambala Cantt, in terminating the services of Shri Amar Singh, a monthly rated Farm Labour working at Military Farm, Ambala Cantt, with effect from 3rd May, 1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled to and from what date?"

Notice of the reference was sent to the parties. The workman had put in appearance on 7-5-86 and also on 10-6-86. However, he is not present today nor has he filed any statement of claim. Therefore, it appears that the workman is not interested in pursuing this dispute. Hence this reference is disposed of for non-prosecution and 'No I spute' award is given.

G. S. KALRA, Presiding Officer Central Govt. Industrial Tribunal New Delhi

June 25, 1986.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

June 25, 1986.

[No. L-13012|13|84-D.II(B)]

मई विल्ली, 17 जुलाई, 1986

का. मा. ?743: → भौचोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रतुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाच निगम के प्रवंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के धीच अनुवंध में निर्दिश्ट भौचोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौचोगिक धिक करण, जवलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 9-7-1986 को प्रान्त हुंमा था।

New Delhi, the 17th July, 1986.

S.O. 2743.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUS-TRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT|LC(R)(65)|1985.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Nagpur and their workmen represented through the Secretary, Food Corporation of India Employees Association, C|o Food Corporation of India, Nagpur (M.S.).

APPEARANCES:

For Union—Shri N. K. Shukla.

For Management-Shri N. Sunderam.

INDUSTRY: Food Corporation—District: Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated: June 27, 1986.

The Central Government vide Notification No. L-42012(53)|84-D.V. Dated 30th July, 1985 referred the following dispute, for adjudication:—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Nagpur in terminating orally the services of 12 casual workers mentioned in Annexure below with effect from 14-8-1984 is justified? If not, to what relief are they entitled?"

ANNEXURE

- 1. Shri Suresh Jarulkar
- 2. Shri Ramesh Ambade
- 3. Shri Suresh Rakshit
- 4. Shri Mahendra Kamble
- 5. Shri Siddharth Mandape
- 6. Shri Pandurang Padal
- 7. Shri S. P. Nihare
- 8. Shri R. G. Kswade
- 9. Shri Bhaiyya Sudam
- 10. Shri Narendra Gaikawad
- 11. Shri M, B. Rana
- 12. Shri Baba Balekar.
- 2. Non controversial facts of the case are that the applicants were working as casual labourers in the Engineering Wing of the Food Corporation of India and their services were dispensed with orally with effect from 14-8-1984.
- 3. The case of the applicant further is that the management manipulated the attendance of the workmen applicant in such a way (by giving break in service after about 15 days of service) that the workers were not allowed to qualify the prescribed eligibility of completing 240 days in a year or 120 days in six months. They were not paid overtime though the provisions of the Bombay Shops and Establishments Act and the Minimum Wages Act apply to the management. They have also not been paid bonus and wages for national holidays in the year 1983-84. The job of the workmen in the Engineering Department was of regular and permanent naure. The management terminated the services of these 12 workmen and appointed other labourers through the Contractors which is in contravention of the following provisions:—
 - (a) Unfair labour practice within the meaning of item no. 10 of Schedule V of the I.D. Act;
 - (b) Change within the meaning of item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV of the I.D. Act; and
 - (c) the provisions of the Contract (Abolition & Regulation) Act.

- 4. The case of the management is that the workmen in question were working as casual labouters on "no work no wages basis". They were engaged depending on the availability of the work which were not of perennial and permanent nature. The work was of casual nature such as cleaning of gutters when they were blocked. The management employed these casual labourers when they required and when they were available. It is not true that the major civil work in Engineering Division was not being done by the Civil Contractor or it has been wrongly introduced.
- 5. The management has not contravened any lawful provisions and the workmen are not entitled to any relief.
- 6. It is the case of the workmen that the nature of work for which they were employed as casual labourers was of perennial nature. But the management employed them in such a fashion that they could not complete their statutory period of 240 days in a year. On 14-4-84 the management terminated their services orally and started getting the work Thus the first act of done through the contractor. the management amounts to unfair labour practice within the meaning of Clause 10 of Schedule V and the second act amounts to change of service conditions within the meaning of Item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV of the I.D. Act. Thus they have contravened the provisions of Sec. 9A read with item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV clause 10 of Sch. V of the I.D. Act. In support of this plea the workmen has filed the copies of tender notice issued to the contractor and pronouncement made in the case of Workmen of Food Corporation of India Vs. MJs. Food Corporation of India (AIR 1985 SC 670). I have gone through the provisions and the authority relied on by the workmen and I find that the contention is correct that it amounts to unfair labour practice and change in service condition as alleged provided the workmen were working on perennial and not casual nature of work. In that case they would have the moved for prosecution and of punishment provided under the I.D. Act But if the nature of their employment, was purely for the temporary or casual nature of work the story would be different.
- 7. I, therefore, proceed to examine the nature of employment of the present workmen. In support of Shri Ramesh Nilkhand Ambare their case only (W.W.1) workman has been examined. He stated that he used to clean gutters, put tar plaster over grain, help the electric department, cut grass and do other miscellaneous work. In his crossexamination he has admitted that the grass cutting was done only for 2-3 days in a month and gutter cleaning was done once in a year. He has further stated that tar plastering was done over roofs of godown during mansoon season. He does not specify the nature of help he gave to the electric department and what was the miscellaneous work. In view of this admission and circumstance it is difficult to hold that the workmen were employed on a - perennial nature of work. The work was of purely temporary and casual nature and not perennial.
- 8. In this connection, it is partinent to note the following definition of 'workman' given in the 1st

Schedule to the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 :--

- "2(e) A "temporary" workman is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period.
- (f) A "casual" workman is a workman whose employment is of a casual nature."

As pointed out from the evidence above the work for which the applicants were employed was of temporary nature and they were admittedly casual workmen. Therefore they come under the above definition.

- 9. It is the admitted case of the applicants themselves that they did not work for 240 days in a year. Therefore they cannot swim into the harbour of Section 25F of the I.D. Act as has also been held by the Presiding Officer of New Delhi in D.O. No. 150|81 dated 17th August, 1933.
- 10. It has been contended as a last resort that the management employed so many casual labour and made them permanent which amounts to discrimination. Simply because others have been treated differently it does not give the right to the applicants to insist that they be re-employed or absorbed as permanent workmen as of right. Looking to the nature of their employment, as already pointed out had they been employed on a work of perennial nature their rights would have been protected.
- 11. In view of my finding above, I answer the reference as under :---

That the action of the management of Food Corporation of India, Nagpur in terminating orally the services of 12 casual workers mentioned in the Annexure to the reference order (named above) with effect from 14-8-1984 is justified and the 12 workmen are not entitled to any relief. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer.

27-6-1986

[No. L-42012|53|84-D.V.]

- का. मा. 2744.—श्रीयोगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के मनुसरण में केन्द्रीय सरकार, नार्वन रेलबे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियीजकों भीर उनके कर्मकारों के बीच, मनुबंध में निर्विष्ट मौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक मधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट की प्रकाशिक करती हैं, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-86 की प्राप्त बुधा था।
- S.O. 2744.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PESIDING OFFI-CER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU-NAL, NEW DELHI

I.D. No. 45 86

In the matter of dispute between:

Shri R. K. Mahajan through The Assistant General Secretary, Uttar Railway Karamchari Union, 5239, Ajmeri Gate, New Delhi.

VERSUS

The General Manager, Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

APPEARANCES:

None for both sides.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide notification No. L-41012(39)|85-D.II(B) dated 18-3-1986 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the action of the Senior Personntl Officer, Head Quarters, Northern Railway in dropping out name of Shri R. K. Mahajan from the confirmation list of Clerks, is justified. If not to what relief Shri Mahajan is entitled to?"
- 2. Notices of the reference were sent to the parties. The workman had put in appearance through Shri Yogeshwar Dutt on 7-5-86 and also on 11-6-86 he appeared in person. However, he is not present today nor has he filed any statement of claim. Therefore, it appears that the workman is not interested in pursuing this dispute. Hence this reference is disposed of for non-prosecution and 'No dispute' award is given.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

June 27, 1986

[No. L-41012|39|85-D.II(B)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का. था. 3745:---मौदोगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के मनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फूड कार्योरेशक माफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों भीर उनके कर्मकारों के बीच, भनुबंध में निर्दिष्ट भौदोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौदोगिक मिकरण, नह दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-86 को प्राप्त छुट्टी था।

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2745.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the

Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th July, 1986.

BEFORE SHRI G.S. KALRA, PRESIDING OFFI-CER, CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBU-NAL, NEW DELHI I.D. No. 38/83

In the mattter of dispute between:

Shri Yoginder Sharma through

General Secretary, All India joint Council of Food Corporation of India Employees Union and All India Food Corporation Executive Employees Federation, Q. No. 560, Sector V, R. K. Puram, New Delhi.

VERSUS

The Managing Director, Food Corporation of India, 16-20 Barakhamba Lane, New Delhi.

APPEARANCES:

Shri S. K. Charchara for the workman. Shri Ashwani Kumar for the Management.

AWARD

The central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-42011|31|81-FCI-D.IV(A) has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the action of the management of Food Corporation of India in transferring Shri-Yoginder Sharma, Chairman, Joint Action Committee, Naraina Depot is fair and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"
- 2. Notices were issued to the parties and the parties appeared and filed their claim statement and written statement. Today the parties have filed a written settlement and the workman do not want to pursue with the reference any more. Hence a 'No Dispute' Award is given in terms of settlement. The reference is disposed of accordingly.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

July 3, 1986.

[No. L-42011|31|81-FCI|D.IV(A)|D-II B]

का. मा. 2746: -- - भौद्योगिक विवाद मिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के मनुमरण में कैन्द्रीय सरकार, फूड कार्र्पारेणन आफ इंडिया के प्रवंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों भीर उनके कर्मकारों के बीच, भनुबंध में निविष्ट भौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक प्रधि-करण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो कैन्द्रीय सरकार को 11-7-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2746.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Food Corporation of India (PO), Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1986.

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD. B.Sc. B. L, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government) Wednesday, the 25th day of June, 1986

Industrial Tribunal No. 89 of 1985

[In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Food Corporation of India, Madras-8.]

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary, Madras Port United Labour Union, 'Bhagat House', 204, Pra-Kasam Salai, Broadway Madras-8.

AND

The Joint Manager, (PO), Food Corporation of India, Chennai House, Esplanade, Madras 8.

REFERENCE:

Order No. L-42012(9) 85-D.V., dated 10-12-1985 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference and other connected papers on record and upon hearing of Thiru P. B. Krishnamurthy, Advocate appearing for the Management and the Union being absent, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workmen and the Management of Food Corporation fo India, Madras-8 arising out of a reference under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-42012(9)|85-D.V., dated 10-12-1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issues:

- (a) Whether the action of Food Corporation of India in relating to the establishment of Joint Manager (Port Operations) Food Corporation of India, Madras Port. Madras-600011 in Cenving wages to Shri P. Dhanakoti, VCL No 140 for the period of suspention from 31-2-1983 to 29-4-1983 is justified. If not, to what relief the workman concerned is entitled
- (b) If the answer of (a) is affirmative then, whether the management is instifled and legal in denying the subsistance allowance to the worker concerned for #ie period of his suspension from 31-3-1983 to

29-4-1983 ? If not, to what relief the work-

- (2) Summons were isued for appearance of parties and filing claim statement. Union and the Management were represented by counsel.
- (3) Today, when the dispute was called, Union was absent and no representation was made on its behalf. No claim statement was filed. Hence the claim of the workmen is dismissed for default. No costs. Dated, this 25th day of June, 1986.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal [No. L-42012]9[85-D.V[D.II(B)] HARI SINGH, Desk Officer

मर्फ दिल्ली, 18 जुलाई, 1986

भादेश

का . प्रा. 2747 :- भारत सरकार के भतपूर्व श्रम मौर पूनवीस मंत्रासय की मिन्न्या संख्या का. मा. 461 दिनोक 5 फरवरी, 1963 द्वारा गठित कम न्यायांस्य, जिसका मुख्यालय सद्रास में स्थित है, के पीठासीन प्रिम्निती का पद रिक्त हो गया है ;

धतः, प्रव भौगोगिक विधाद प्रक्षितियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपवंधों के धनुसरण में केन्द्रीय सरकार थिक टी. बी. ए. मब्दुल समय को पूर्वोक्स गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन भक्षि-कारी नियुक्त करती हैं।

> [मं. एम.-11020/7/81-श्री.1(ए)] सप्ति मूर्यण, अस्तर समित

New Delhi, the 18th July, 1986

ORDER

S.O. 2747.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Madras constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 461 dated the 5th February, 1963.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Thiru T. V. A. Abdul Samad as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11020]7[81-D.I (A)] SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का. था. 2748: --- भूना पत्थर घीर डोलामाइट खान श्रीमक कल्याण निधि नियम, 1973, के नियम 3 के उप-नियम (2) के साथ पठित भूनापत्थर और डोलामाइट खान श्रीमक कल्याण मिधि घिनियम, 1972 (1972 का 62) की घारा 6 हारी प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्मिशिक्षत सवस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करती है, प्रयोग :--

सम मंत्री, उत्तर प्रवेश सरकार मध्यक्ष
 कस्थाण मायुक्त, अम कस्थाण संगठन, 555-ए/2, न्यू ममफोड़ गंज, इलाहाबाव, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष (पदेम)
 अप्रदेशिक अम मायुक्त (केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि (केन्द्रीय) कानपुर (उत्तर प्रवेश) (पदेन)

Chairman

उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा 4. श्री मोहस्मद ग्रसलम खा, विद्यायक, मजक्फराबाद, सहारन-सबस्य पुर, 75/ए, राजपुर रोड, वेहरा-दुन

 श्रो रवि प्रकास, प्रवंध निदेशक उत्तर प्रदेश खनिज विकास बोई, जसत ह

चुनापत्यर मीर डीलामाइट मालिको के प्रतिनिधि

6. श्रीसी.जा. गुजरास, 36-रेमकोर्स, बी, गोर, वेहरादन

---य**योक्**त-

7. श्री रामाश्रय सिंह, प्रेजीबेंट, इंटक, उत्तर प्रदेश, शाबा, 163/3/1, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., रामी पुर, हरिदार

चुनापस्थर और डोलोमाइट खान में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधि

8. स्री प्रवीप अजवर्ती, सेफेटरी, भारतीय मजदुर संघ, उत्तर प्रदेश, भारतीय मजदर संघ कार्यालय, जे 98 चुके, मित्रीप्र, ज**तर प्रदेश**

---ययो**क्त--**-

9. श्रीमती राज भानन्द, सेकेंटरी, महिला प्रतिनिधि वेद्ररादन लाइमस्टोन कर्मचारी संय, देहरादून, भार्फत ध्रमर अकावमी, रेसकोर्स, देहरावन

10. कल्यार्णे प्रशासक इलाहाबाद

सेन्नेटरी

2. उक्त सजाहकार समिति का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

[सं. 19012/2/85-कल्याण; 2 (सी)] एस. एस. भल्ला, प्रवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2748—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), road with sub-rule (2) of rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour W. Ifare Fund Rules, 1973 the Central Government hereby reconstitutes

on Advisory Committive for the State of Uttar Pradesh consisting of the following members, namely :-

Government of Uttar Pradesh. 2. Welfar · Commissioner. Labour Wilfur Organisation 555-A/, New Mumfordgenj, Allahabad (U.P.) 3. Rigi nal Labour C mmissioner

Vice-Chairman (Excff(cio)

(C ntril), Kinpur (U.P.)

1. Labour Minister

C ntral Government r presentative Exofficio)

4. Shri Mohammad Aslam Khan Men bor Logislative Assembly, Muzzaffrabad, Saharanpur. 75/A, Rajpur Road, D. hradun. Member of the Legislative Assembly of the State of U.P.

5. Shri Ravi Prakash. Managing Dir ctor. Uttar Paid sh Mineral Development Dolomite Board, Lucknow.

Ripresents th Limes Owners.

6. Shri C.G. Guierel, 36-B, Govind Nagar, Race Course. D hradun.

Hiridwar.

9. Smt. Rij Anand,

7. Shri Ramyash Singh. Provident INTUC, U.P. Branch. 163/3/1 BHEL, Ranipur.

R preentatives of p 'rsons employ, d in Limestone and Dolomite Mines.

8. Shri Pradcep Chakravarty, Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh U.P. Offic: Bhartiya Mazdoor Sangh. J-98 Churck, Mirzapur, U.P.

Woman representa-

Secretary. Dihradua Limistone Karamchari Sangh Dihradun, C/O Amar Academy Raceourse, D.hradun.

10. Wolfare Administrator, Allahabad. Secrete 1 y.

2. The headquarters of the said Advisory Committee shall be at Allahabad.

> [Go. 19012/2/85-W-II (c)] S.S. BHALLA, Under Secy.